Monday, 30 April, 1962

लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड २, १९६२/१८८४ (शक)

[३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ वैशाख, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumig 18·10·73

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3.12.83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड २ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय माला खंड २, अंक ११ से २०—३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ बैशाख, १८८४ (शक)]

अंक ११—सोमवार, ३० अप्रैल, १९६२/१० बैशाख, १८८४ (शक) पृष्ठ

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ६६९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६९, २७०, २७२, २८३, २७३ से २८१, २८४ से २८६ और २८८ से २९० ६६९—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७१, २८२, २८७ और २९१ से २९८ ६९४—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५० से ३२६ और ३२८ से ३६२ ६९८—७४८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ७४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ७४८—५१

१. आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी . . ७४९—५१

२. पाकिस्तान उच्च आयोग द्वारा एक ऐसे मानचित्र का परिचालन जिसमें भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है ७५१

३. पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर मुसलमानों का कथित जमा होना ७५१

समितियों के लिये निर्वाचन . ७५१–५२

१. भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति . ७५१

२. भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ७५२

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक—पुरस्थापित ७५२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७५३

दैनिक संक्षेपिका . ७९०—९६

अंक १२—मंगलवार, १ मई, १९६२/११ बैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ७९७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९९, ३०१, ३०२, ३०४ से ३०६, ३०८, ३११ से ३१५ और ३१७ से ३१९ . . ७९७—८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--
तारांकित प्रश्न संख्या ३००, ३०३, ३०७, ३०९, ३१०, ३१६, ३२० से ३३६ . . . . ८२२--३३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४१२, ४१४ से ४२२, ४२४ से ४३५, ४३७ से ४४८, ४५० और ४५१ ८३३--७३
प्रक्रिया के बारे में ८७३-७४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ८७४--७८
१. बिहार को कोयले का अपर्याप्त संभरण . . ८७४--७५
२. लाल किले के समीप शरणार्थियों की झोपड़ियों को आग लगना ८७५--७८
३. सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दल का पूर्व पाकिस्तान की ओर जाने का समाचार . ८७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . ८७९-८०
तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर में शुद्धि ८८०
बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में वक्तव्य ८८०--८१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८८१--९१६
कार्य मंत्रणा समिति--
पहला प्रतिवेदन ९१६
दैनिक संक्षेपिका ९१७--२३

अंक १३--बुधवार, २ मई, १९६२/वैशाख १२, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--
तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४४, ३४६, से ३४९, ३७०, ३५१ और ३५३ ९२५--५०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--
तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, ३५०, ३५२, ३५४ से ३६९ और ३७१ से ३७९ ९५०--६३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२ से ५२३ . . ९६३--९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ९९६--९८
१. कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड की पुनर्रचना की आवश्यकता ९९६--९७
२. गुजरात में कपास का अधिग्रहण . . ९९७--९८
३. पूर्वी पाकिस्तान में ढाका तथा राजशाही में दंगे ९९८
सभा पटल पर रखे गये पत्र ९९८--१०००
कार्य मंत्रणा समिति--
पहला प्रतिवेदन . . १०००
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . १००१--११
अनुदानों की मांगें (रेलवे) १०११--५७
दैनिक संक्षेपिका १०५८--६७

अंक १४—गुरुवार, ३ मई, १९६२/१३ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण— . .

प्रश्नों के मौखिक उत्तर १०६७

तारांकित प्रश्न संख्या ३८०, ३८२ से ३८६, ३९३ से ३९६ और ३९८ १०६७—९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . १०९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८१, ३९० से ३९२, ३९७ और ३९९ से ४१५ १०९४—११०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२४ से ६०२, ६०५ से ६२१ और ६२३ से ६३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

१. स्माल स्केल वुलन मैन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन और स्क्रीन प्रिन्टर्स द्वारा अपने समवाय बन्द कर देने की धमकी . ११५१—५२

२. हुगली के पायलेटों द्वारा त्याग पत्र देने की धमकी ११५२—५४

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११५५—५६

समितियों के लिये निर्वाचन—

१. पशु कल्याण बोर्ड . ११५६

२. भारतीय लाख उप-कर समिति . . . ११५६—५७

३. भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद का प्रशासी निकाय ११५७

अनुदानों की मांगें (रेलवे)—

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलामा—

(१) भारत को चीन को कथित अलटीमेटम ; तथा . ११९३—९४

(२) १५० नागा विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान में चले जाना ११९४—९६

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे मे आधे घंटे की चर्चा—

दैनिक संक्षेपिका १२०६—१२१४

अंक १५—शुक्रवार, ४ मई, १९६२/१४ बैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १२१५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४१९, ४२१ से ४२५ और ४२८ से ४३३ । १२१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १२३७—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२०, ४२६, ४२७ और ४३४ से ४५० . . . १२३८--४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८, ६३९, ६४२ से ७१३ और ७१५ से ७२१ . . . १२४७--८१

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . १२८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२८२

राष्ट्रपति का संदेश . . . १२८२

सभा का कार्य १२८३

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . . १२८३--१३१७

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक--

पुरःस्थापित और पारित १३१८-१९

जनता एक्सप्रैस गाड़ियों के बारे में संकल्प . . . १३१९--३८

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प . . . १३३८

दैनिक संक्षेपिका . . . १३४४-५०

अंक १६—सोमवार, ७ मई, १९६२/१७ वैशाख १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण . . . १३५१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१, ४५३ से ४६१, ४६३, ४६४, ४६६ और ४६७ . . . १३५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४६२, ४६५ और ४६८ से ४९९ . . . १३७६—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७५२, और ७५४ से ७७२ . . . १३८९—१४१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काश्मीर और चीन के सिंक्यांग क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारण के बारे में बातचीत करने का पाकिस्तान और चीन का कथित निर्णय . . . १४१०-११

सभा पटल पर रखे गये पत्र--

समितियों में निर्वाचन--

१. राजघाट समाधि समिति और . . . १४१२

२. कर्मचारी राज्य बीमा निगम . . . १४१३

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . . . १४१३--३८

दैनिक संक्षेपिका १४३९--१३

अंक १७, मंगलवार, ८ मई १९६२ / १८ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से ५०४ और ५०६ से ५१४ . . . १४४५—६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . . १४६९—७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ और ५१५ से ५४६ . . . १४७१—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७३ से ८६०, ८६२ से ८७८, ८८०, ८८१, ८८३, ८८४, ८८६ से ९१० और ९१२ से ९२३ . . . १४८६—१५५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा लैंड में भारतीय वायु सेना के एक डकोटा विमान का गिरना . . १५५३-५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र— १५५५—८७

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा १५७६-७७

राष्ट्रपति की विदाई के बारे में . . . . १५८८—९६

दैनिक संक्षेपिका—

अंक १८, बुधवार, ९ मई १९६२ / १९ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५५६ और ५५८ . १५९७—१६१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . १६१९-२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५५७ और ५५९ से ६०९ . . १६२०—४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से १०२६ . . . १६४३—८७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की कथित रिहाई १६८७

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में १६८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १६८८—९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . १६९०—१७१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . १७१५—२३

अंक १९, गुरुवार, १० मई, १९६२ / २० वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१० से ६१५, ६१७ से ६२०, ६२३, ६२६ से ६२८, ६३८ और ६२९ से ६३२ . . . . १७२५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१६, ६२१, ६२२, ६२४, ६२५, ६३३ से ६३७ और ६३९ से ६४५ . १७५०—५७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०६६ और १०७१ से १०७७ . १७५७—८०

हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में . . . . १७८०—८२

सूचना प्राप्त करने के बारे में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

चीनी वाणिज्य दूतावास कलिम्पोंग से एक सिपाही पर गोली चलाया जाना . १७८२—८३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में छपाई के कागज की कमी १७८३—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७८४

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . १७२४—१८२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १७२९—३२

अंक २०, शुक्रवार ११ मई, १९६२ / २१ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६४९, ६५१ से ६५५ और ६५७ से ६६३ . १८३३—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १८५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५०, ६५६ और ६६४ से ६९१ . . १८५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७८ से १०८२ और १०८४ से ११८६ १८७०—१९२३

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

माल गाड़ी और ट्रक की टक्कर १९२३—२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

१. फिजी के सम्बन्ध में जानकारी और विद्रोही नागाओं के एक और दल का पाकिस्तान को कथित प्रस्थान १९२८

GMGIPND—LS III—811 AI LSD—12-7-62—150

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, ३० अप्रैल, १९६२

१० वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री प्र० के० देव (कालाहान्डी)

श्री दे० द० पुरी (कैथल)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वी क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन

†*२६९. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा उस क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन को और तेज करने के लिये, जो कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वहां शिथिल पाया गया है, कोई कदम उठाये गये हैं, और यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या इस दिशा में हुई प्रगति के बारे में कुछ पता लगा है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति):** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पूर्वी क्षेत्र को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका अध्ययन भारत सरकार रिजर्व बैंक द्वारा भेजे गए एक अफसरों के एक दल ने किया था। इस दल की उपपत्तियों पर अधिकारियों की बैठकों में इन राज्यों के सहकार मंत्रियों के नवम्बर, १९६१ में हुए सम्मेलन में चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

की गई। यह तय किया गया है :--

(१) कि सहका ी संस्थाओं पर से अधिकारियों का नियंत्रण हटा दिया जाये ताकि जो व्यक्ति अधिकारी नहीं हैं वे जिम्मेदा ी के पदों पर काम कर सकें ;

(२) कि विस्तार के बजाय समेकन को पूर्ववर्ता दी जाये और सहकारी संस्थाओं में रचना सम्बन्धी जो भी त्रुटियां हों उन्हें उचित उपायों से दूर किया जाये;

(३) कि कर्मचारियों के अभाव को दूर किया जायेगा ; और

(४) इन उपायों के अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं को लम्बे अर्से तक अधिक उदार आर्थिक सहायता दी जाये ताकि वे संतोषजनक ढंग से कार्य कर सकें।

बिहार राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने कमजोर समितियों को शक्तिशाली बनाने और जो समितियां इस प्रकार कार्यक्षम नहीं बनायी जा सकतीं उन्हें समाप्त कर देने के लिये विस्तृत कार्यक्रम बना लिये हैं। बिहार राज्य के कर्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इन सभी राज्यों में उदार आर्थिक सहायता देने के लिये योजनाय बनाई जा रही हैं।

चूंकि समस्या बहुत बड़ी है इसलिये पर्याप्त प्रगति का अनुभव करने में कुछ समय लगेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास :** विवरण से स्पष्ट नहीं है कि क्या केन्द्र द्वारा इस क्षेत्र को कोई विशेष सहायता दी जाने वाली है और दी जाने वाली है तो वह क्या है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** वक्तव्य बिलकुल स्पष्ट है। तीसरी योजना के लिये यानी अगले ४ वर्षों के लिये एक करोड़ रुपया रखा गया है और इस वर्ष के लिये १० लाख रुपया है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन के कार्य की अन्तर्विष्ट खामियों की जांच करने के लिय एक विशेष दल की नियुक्ति की गयी थी। सम्मेलन ने यदि कोई महत्वपूर्ण सिफारिशें स्वीकार नहीं की तो वे क्या हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** इन सभी सिफारिशों पर विचार किया गया है और वे सिफारिशें, जैसाकि विवरण में कहा गया है, इस प्रकार हैं : (१) कि सहकारी संस्थाओं पर से अधिकारियों का नियंत्रण हटा दिया जाये ताकि जो व्यवित अधिकारी नहीं है वे जिम्मेदारी के पदों पर काम कर सकें। कुछ राज्यों में मंत्री और अधिकारी बैंकों आदि के सभापति हैं। हम यह नहीं चाहते थे। (२) विस्तार के बजाय समेकन को पूर्ववर्तिता दी जाये। इन राज्यों में सहकारी आन्दोलन को समेकित करके उसे अधिक प्रभावी बनाने के बजाय आन्दोलन के विस्तार की प्रवृत्ति विद्यमान है। (३) कर्मचारियों के खासकर लेखा परीक्षा और निरीक्षक कर्मचारियों के अभाव को दूर नहीं किया गया है। इसलिये हमने इन सिफारिशों पर जोर दिया है। जहां तक चौथी सिफारिश का संबंध है मैं बता चुका हूं कि केन्द्र की सहायता के अतिरिक्त एक करोड़ रुपया रखा गया है।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या मंत्रालय ने यह योजना बनाते समय ढेबर आयोग के प्रतिवेदन को विशेषकर आदिम-जाति क्षेत्रों में सहकारिता के कार्य का अध्ययन किया है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** आदिम-जाति क्षेत्रों की जनता को सहकारी आन्दोलन से अछूता नहीं रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में कहा गया है कि सहकारी संस्थाओं पर से अधिकारियों का नियंत्रण हटा दिया जाये ताकि जो व्यक्ति अधिकारी नहीं हैं वे जिम्मेदारी के पदों पर काम कर सकें। क्या इस आन्दोलन से ऐसे व्यक्ति भी सम्बद्ध हैं? क्या किसान सभाओं के नेता इससे सम्बद्ध हैं?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** हम किसान सभा और मजदूर सभा में कोई विभेद नहीं करते। जो भी व्यक्ति या संगठन इस आन्दोलन में दिलचस्पी रखता है वह इसमें भाग ले सकता है? आखिरकार वह स्वेच्छा से काम करने वाला एक संगठन है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** शिक्षा प्रणाली में विशेषकर उच्च माध्यमिक और कालेज के स्तर पर सहकारिता को एक विषय के रूप में रखने के लिये क्या किया गया है?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सामान्य प्रश्न है जो इससे संबंधित नहीं है।

†**श्री बसुमतारी :** क्या यह सच है कि असम में सहकारी प्रणाली अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आदिम जाति क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** आदिम जाति क्षेत्रों में सहकारी और सामूहिक ये दोनों प्रणालियां प्रचलित हैं।

कांडला पत्तन के लिये बिजली

†२७०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र अथवा राज्य सरकार कांडला पत्तन को और बिजली देने की किसी योजना पर विचार कर रही है?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) :** जी, हां। तीसरी योजनावधि में कांडला पत्तन को बिजली देने के लिये ५ मेगावाट के दो यूनिटों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

श्री रघुनाथ सिंह : कांडला पोर्ट के प्रयोग के वास्ते यहां पर जो फ्री ट्रेड जोन का एरिया कायम किया है मैं जानना चाहता हूं कि उसको जो बिजली दी जायेगी वह बम्बई के रेट से कम होगी या ज्यादा होगी?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** जब तक मैं दोनों की जांच न कर लूं तब तक मेरे लिये यह कहना मुश्किल है कि दो अलग बस्तियों में क्या दर होगी। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं।

†**श्री उमानाथ :** क्या सरकार को बिजली की दर घटाने के बारे में कांडला विकास मंडल से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** हो सकता है कि वे राज्य सरकार को मिले हों। चूंकि वे हमें नहीं मिले इसलिये हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री उमानाथ :** क्या केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं? मैं राज्य सरकार के बारे में नहीं पूछ रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : जब माननीय मंत्री कहते हैं कि वे राज्य सरकार को मिले हों तो उसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं मिले ।

†श्री मान सिंह पटेल : इस योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

†हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : १९६२—६४ तक ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान् मेरा अनुरोध है कि प्रश्न संख्या २८३ का उत्तर भी इसी के साथ दिया जाय क्योंकि ये दोनों प्रश्न एक ही विषय पर हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय को असुविधा न हो तो प्रश्न संख्या २८३ का उत्तर भी दे दिया जाये ।

हुगली के जहाज-चालक

†*२७२. { +श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री नाथ पाई :
श्री ही० ना० मूकर्जी :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुगली जहाज-चालक सेवा संघ ने मंत्रालय के साथ अपनी कठिनाइयों पर विचार करने के लिये अपने कुछ प्रतिनिधि भेजे थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जहाज-चालकों ने यह धमकी दी है कि यदि उनकी कठिनाइयां दूर न की गयीं तो वे त्यागपत्र दे देंगे ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४० ।]

हुगली के जहाज-चालक

*†२८३. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुगली के जहाज मालिकों ने हाल में अपने सामूहिक त्याग पत्रों को समझौते की किन शर्तों के आधार पर वापिस लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि उनको पहले कलकत्ता के पत्तन आयुक्तों ने जो आश्वासन दिये थे उनका पालन नहीं किया गया ; और

(ग) क्या अब जहाज चालकों के वेतन क्रम और भत्तों का पुनरीक्षण करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ग). ७ अप्रैल, १९६२ को इन जहाज चालकों ने पत्तन आयुक्तों के साथ चर्चा की। पत्तन आयुक्तों ने उन्हें इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और हुगली के जहाज चालकों तथा कलकत्ता पत्तन की अन्य ५ समुद्रीय सेवाओं के बारे में गुहा–राय समिति के प्रतिवेदन पर अपनी राय और सिफारिशों से सरकार को अवगत कराने का आश्वासन दिया जिसके बाद जहाज चालक अपने अपने पद पर काम करने के लिये सहमत हो गये। सरकार पत्तन आयुक्तों की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

(ख) जहाज-चालकों को दिये गये आश्वासनों का कोई अधिकृत रिकार्ड न तो पत्तन आयक्तों के पास है और न सरकार के पास। गुहा-राय समिति ने इस प्रश्न की जांच की थी और पत्तन आयुक्त समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के साथ इस मामले पर आगे विचार करेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : हुगली के जो पाइलट्स हैं उन को समस्या सन् १९५४ से अब तक उसी तरह है। सन् १९५४ में, सन् १९६० में और सन् १९६१ में तीन कमेटीज कायम की गई हैं और एक स्पेशल कमेटी यह कायम की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि अखिर पाइलट लोगों ने इनके फसले को क्यों नहीं माना ?

श्री जगजीवन राम : स्पेशल कमेटी का फैसला तो अभी आया ही नहीं है। स्पेशल कमेटी गुहा-राय कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन को देख रही है। उन्होंने अपनी सिफारिशें पोर्ट कमिश्नर को दे दी हैं और पोर्ट कमिश्नर की मीटिंग में उस पर विचार होने के बाद उनकी जो सिफारिशें हमारे पास आयेंगी, उन पर निर्णय होने के बाद उन को अमल में लाया जायगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण में कहा गया है कि जहाज चालकों को दिये गये किसी भी आश्वासन का कोई अधिकृत रिकार्ड नहीं है। क्या यह सच है कि समझौता होने से पहले स्वयं जहाज चालकों ने श्री एन० एम० अय्यर का जो उस समय पत्तन आयुक्तों के चेयरमैन थे, दस्तखत किया एक दस्तावेज पेश किया था और उस दस्तावेज का सही होना स्वीकार किया गया था।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं इस दस्तावेज का सही होने के बारे में कुछ न कहूंगा क्योंकि गुहा-राय समिति ने भी उसकी जांच की है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि एक विशेष समुद्रीय समिति ने १९५१ में समुद्री अफसरों के वेतन में काफी वृद्धि की थी किन्तु अपनी सिफारिशों में जहाज चालकों के मामले का उल्लेख नहीं किया और यदि हां, तो इसके क्या विशेष कारण थे ?

†**श्री जगजीवन राम** : इस समय तो मुझे इस समिति के बारे में कोई जानकारा नहीं है। हुगली के जहाज चालक १९४८ में पत्तन आयक्तों के मातहत आ गये थे और १९५२-५३ में या इसके आसपास उन्होंने कुछ मांगें की थीं और १९५४–५५ में लोकूर समिति गठित की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पतन आयुक्तों की सिफारिशें सरकार को कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

†**श्री जगजीवन राम** : मेरा ख्याल है कि वे कुछ ही दिनों में हमें प्राप्त हो जायेंगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि गुहा-राय समिति के प्रतिवेदन में श्री अय्यर के साथ हुए समझौते का कोई उल्लेख नहीं है और वह विशिष्ट पत्र और समझौता जहाज चालकों ने पत्तन आयुक्तों के समक्ष रखा है इसलिये उस समिति द्वारा इन दस्तावजों की जांच करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ?

†**श्री जगजीवन राम** : यदि वे कागजात वर्तमान चेयरमन के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं तो मेरा ख्याल है कि पतन आयुक्त विशेष समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय इस बात पर भी ध्यान देंगे और सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : जहाज चालकों की हड़ताल के फलस्वरूप कितनी हानि हुई है और उससे कितने लोग संबंधित थे ?

†**श्री जगजीवन राम** :इसके लिये मुझे अलग से सूचना दी जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं प्रश्न को सुन नहीं सकी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने पूछा कि कितनी हानि हुई ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कोई हानि नही हुई ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि जहाज चालकों ने अपने त्यागपत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि वे काम रोकना नहीं चाहते किन्तु भारत सरकार के अधीन पुनः नियुक्त किये जाना चाहते हैं ? इसलिये उन्हे डराने के लिये अत्यावश्यक सेवा अध्यादेश को क्यों जारी किया गया ?

श्री जगजीवन राम : उन्हें डराने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । किन्तु पत्तन सेवा बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक सेवा है । हमें इस बात का भी स्मरण रहे कि यह अध्यादेश केवल जहाज चालकों के लिय नहीं वरन् सभी अत्यावश्यक समुद्री सेवाओं के लिये जारी किया गया था ताकि पत्तन का काम होता रहे ।

बिजली की दरों में असमानता

†*२७३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही राज्य के विभिन्न भागों में विद्युत संभरण के लिये विभिन्न दर लागू हैं ;

(ख) क्या एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) इसमें समानता लाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं ने जो जानकारी मांगी थी वह विवरण में नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : यदि एसी बात है तो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ कर जानकारी प्राप्त कर लें।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि क्या एक ही राज्य के विभिन्न भागों में बिजली के संभरण की दरें अलग-अलग हैं। विवरण में लघु उद्योगों, कृषि कार्यों और बड़े पैमाने के उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरें दी गयी हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या एक ही राज्य, उदाहरण के लिये आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में विद्युत् निर्माण और वितरण का व्यय अलग-अलग होता है।

†श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : इस विशिष्ट प्रश्न की अलग सूचना आवश्यक नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि एक ही राज्य के विभिन्न भागों में दरें अलग-अलग होती हैं तो विभिन्न राज्यों की दरों में अवश्य ही अन्तर होगा।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या एक ही राज्य के विभिन्न भागों में विद्युत् संभरण की दरें अलग-अलग हैं।

†श्री त्यागी : श्रीमान, विवरण में कहा गया है कि "जिन जगहों में बड़े जल-विद्युत् या भाप से बिजली बनाने वाले स्टेशनों द्वारा बिजली का संभरण किया जाता है उनकी दरें कम होती हैं और जिन्हें डीजल जनरेटिंग सेट या भाप से बिजली बनाने वाले छोटे संयंत्रों द्वारा बिजली दी जाती हैं उनकी दरें ज्यादा होती हैं।"

इसलिये माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। क्या श्री हरिश्चन्द्र माथुर कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं?

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इस बात की ओर ध्यान दिया गया है कि आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई बिजली की दरें ज्यादा होती हैं? क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है और क्या वह इस संबंध में कुछ कर रही है?

†हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : जी, नहीं। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली बिजली की दरें ज्यादा नहीं होतीं। कहीं-कहीं वे ज्यादा होती हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि यद्यपि विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने के उद्योग के लिये दरों में इतनी भिन्नता नहीं है, जहां तक छोटे पैमाने के उद्योग तथा कृषि कार्यों का सम्बन्ध है, भिन्नता बड़ी है जो केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ७ और १८ अथवा १९ है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा बड़े पैमाने के उद्योग के पक्ष में ऐसी भिन्नता दूर करने के लिये राज्य बिजली बोर्डों को परामर्श देने के किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी अथवा विचार कर रही है?

†हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह कहना है कि छोटे पैमाने के उद्योग के लिये मूल्य अधिक है। यह एक बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कृषि भी ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : अन्य बात यह है कि बड़े पैमान के उद्योग के लिये मूल्य कम है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : भिन्नता भी ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : छोटे पैमाने के उद्योग के लिये बड़े पैमाने के उद्योग के लिये मूल्य की अपेक्षा यह इसलिये अधिक है कि बड़े पैमाने के उद्योग के सम्बन्ध में खपत इतनी अधिक है कि मूल्यों में किसी भी हद तक कमी की जा सकती है, परन्तु जहां तक छोटे पैमाने के उद्योग का सम्बन्ध है, उसमें ऐसी बात नहीं है । वहां पर खपत सीमित है और मूल्यों को ऐसा रखना है कि जो व्यक्ति बिजली पैदा करता है और संभरण करता है, उसको कुछ आय भी हो ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : औचित्य प्रश्न पर, मेरा प्रश्न बिल्कुल भिन्न था । मैं ने कहा था कि छोटे पैमाने के उद्योग के लिये केरल में सात और राजस्थान में १९ में बड़ी भिन्नता है। बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये यह भिन्न क्यों है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : औचित्य प्रश्न की कोई बात नहीं है । माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते थे कि क्या सरकार राज्य सरकारों को यह परामर्श देगी कि बड़े पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में इतनी भिन्नता नहीं होनी चाहिये और ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक दर लिया जा रहा है । उनका सुझाव यह था कि सरकार इस भिन्नता को दूर करने के लिये राज्य सरकारों को परामर्श दे। यह केवल एक सुझाव था।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : नहीं, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसकी अनुमति दी और मंत्री महोदय ने इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया क्योंकि वहां पर बिजली की खपत बहुत कम है, जो व्यक्ति बिजली बनाता है, उसको कुछ तो लाभ देना ही है और इसलिये दर अधिक है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने यह नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा करने को कहा, मैंने पूछा था कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। मैंने केवल ऊंचे दरों का ही नहीं परन्तु भिन्नता का जिक्र किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से इसका यह मतलब है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने के उद्योग को १९ नये पैसे, बड़े पैमाने के उद्योग को ९.४४ और कृषि को १० नये पैसे देने पड़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दामोदर घाटी निगम कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम को, जो कि एक ब्रिटिश कम्पनी है और पश्चिम बंगाल में इसके पास बड़ा लाइसेंस है, बिजली संभरण करता है, ऐसा क्यों है कि केन्द्रीय सरकार इस बात पर जोर नहीं देती कि छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग और कृषि उद्योगों से कम से कम दर ली जाय ?

†**हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम** : इन बातों का मुझे माननीया सदस्या से प्रथम बार पता चला है और यैं आश्वासन देता हूं कि मैं मामले की जांच करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** : मैं यह जानना चाहता था कि बिजली की दर वास्तविक खपत से निर्धारित की जाती है अथवा उत्पादन लागत से ?

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतः दोनों पर ही विचार करना पड़ता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में लिखा है :

"इन बातों के बावजूद राज्य बिजली बोर्डों ने प्रत्येक राज्य में, जहां वे बिजली का संभरण करते हैं, सभी स्थानों पर एक ही शुल्क लगान का प्रयत्न किया है ।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों में उद्योगों के बड़े पैमाने पर वृद्धि के हित में सरकार बिजली के एक सम दर लागू करने के बारे में विचार कर रही है ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : मैं ने भी वही उत्तर दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या सरकार दरों में समानता लाने के बारे में विचार कर रही है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : नहीं, नहीं । मैं ने बतग्राया कि सरकार इस समय इस पर विचार नहीं कर रही है और मैं ने यह भी बताया कि ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि इस सम्य स्थिति ऐसी नहीं है ।

खड़गपुर-टाटा सेक्शन पर लाइन को दोहरा करना

+

†*२७४. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० च० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-टाटा सेक्शन पर लाइन को दोहरा करने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) यह काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) मिट्टी हटाना, छोटे पुल बनाना और अन्य विभिन्न कार्य ९ मील में प्रगति पर हैं । बाकी ६३ मील में हाल में ही कार्य आरम्भ करने क लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) वर्ष १९६४ में ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस सेक्शन को दोहरा करने के लिये सुबरन रेखा नदी पर एक रेलवे पुल को भी बढ़ाना पड़ेगा । यदि हां, तो इस पुल की अनुमानित लागत क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं इस समय एक-दम प्राक्कलन बता नहीं सकता। दोहरा करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रत्येक पुल को बढ़ाया जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा :** वह एक बड़ा पुल है। इसीलिय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई प्राक्कलन बनाया गया है। यदि हां, तो कुल रकम कितनी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैंने बताया कि मैं एकदम प्राक्कलन नहीं बता सकता। परन्तु लाइन को दोहरा करने के लिये जिस किसी पुल को बढ़ाना आवश्यक होगा, वह बढ़ाया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या रेलवे लाइन की ओर भूमि प्राप्त करने की कोई आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वर्ष १९६१-६२ के आय-व्ययक में इस कार्य को ६४८ लाख रुपय की लागत से शामिल किया गया है और भूमि आदि प्राप्त करने के लिये २२० लाख रुपये के आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा :** कलाई कुंडा और सरदिया स्टशनों के बीच दूसरी लाइन को बनाने को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि यह दूसरी लाइन बनान के क्या कारण हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह बताना आवश्यक नहीं है। इस में कुछ सुरक्षात्मक कारण हैं।

†**श्री प्र० कें० देव :** क्या इस कार्य को पूरा करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी, हां। १९६४।

रेंड़ बांध

†*२७५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रेंड बांध का निर्माण इस बीच पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों का कितनी-कितनी बिजली दी जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या अब उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के गांवों में बिजली का संभरण किया जा सकेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) :** (क) जी, हां।

(ख) लगभग १०० किलोवाट लगातार।

(ग) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में मऊ, गोरखपुर और सोहवाल के तापीय बिजली घरों से बिजली मिल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने बिजली की कुल मात्रा बतलायी और मैं यह जानना चाहती हूं कि श्री बिडला के अल्युमीनियम निगम को कितनी मात्रा का संभरण किया जा रहा है और इस उद्योग को यह बिजली किस दर पर दी जा रही है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : मुझे दर का पता नहीं है । परन्तु मात्रा मैं बता देता हूं । हिन्दुस्तान अल्युमीनियम फैक्टरी को ५० किलोवाट बिजली मिलेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेंड बांध से बिजली मिलने पर, उत्तर प्रदेश में बिजली की दर में कमी होने की संभावना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके पूरा होने पर क्या उत्तर प्रदेश में बिजली के मूल्य में कमी होने की संभावना है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : समुचे राज्य में बिजली के मूल्य और किसी बिजली-घर के खोले जाने में कोई सम्बन्ध नहीं है जिससे ऐसा समझा जाये कि किसी विशेष बिजली घर के चालू हो जाने से समूचे राज्य में दर में कमी हो जायेगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि बेकार बिजली बहुत बड़ी मात्रा में पड़ी है जो रेंड में उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल नहीं की जा सकती और क्या दामोदर घाटी निगम अथवा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से इस फालतू बिजली में से कुछ भाग दामोदर घाटी निगम को देने के बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : नहीं, नहीं । जहां तक इस बिजली-घर में पैदा की जाने वाली बिजली की खपत का सम्बन्ध है, यह भी समूचे राज्य में खप सकती है । परन्तु यह कुछ स्थानों को दी जा चुकी है । उनमें दामोदर घाटी निगम भी है । इसको कुछ बिजली दी गयी है । कुछ बिजली रेलवे को दी गयी है और कुछ अल्युमीनियम कारखाने को दी गयी है और बाकी की राज्य में खपत होगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल के लिये रेंड बांध से दामोदर घाटी निगम ग्रिड को कितनी बिजली दी गयी है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि दामोदर घाटी निगम को कुछ बिजली दी जा रही है ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : मैं ने बताया कि कुछ मामलों में निर्णय कर लिया गया है। बाकी के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। हम दामोदर घाटी निगम के इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस समय दामोदर घाटी निगम ग्रिड को कोई बिजली दी जा रही है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : हम इस पर विचार कर रहे हैं। अभी इस बारे में हमने कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रा० सा० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को यह बिजली कब तक दी जाने वाली है ?

हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम : मध्य प्रदेश की बिजली के मुतल्लिक मैं ने इस हाउस में दूसरे सवाल के जवाब में अर्ज कर दिया था कि रीजनल कमेटी जो स्टेट्स की है मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की, उस में जब यह मामला पेश हुआ था तो उन्होंने तजवीज किया कि कितनी बिजली उत्तर प्रदेश रिहांड डैम से मध्य प्रदेश को दे, इसका फैसला दोनों चीफ मिनिस्टर्ज़ पर छोड़ दिया जाये। उसी स्टेज पर यह मामला है । अभी इसके बारे में कोई और फैसला नहीं हुआ है ।

रेलवे में डिवीजन प्रणाली के ढंग का संगठन

†*२७६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी रेलवे में डिवीजन प्रणाली के ढंग का संगठन बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रयोग आरम्भ किया गया है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पांच जोनल रेलवे, जैसे मध्य, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम रेलवे, में डिवीजनल प्रणाली के ढंग का संगठन पहले से ही है और हाल ही में इस प्रणाली को दक्षिण-पूर्व रेलवे पर भी लागू करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) और (ग). उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : पहले की प्रणाली की अपेक्षा संगठन की डिवीजनल प्रणाली से किस प्रकार सुधार हुआ है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : डिवीजनल प्रणाली में विकेन्द्रीकरण अधिक है और हमने देखा है कि इससे अच्छा नियंत्रण और अधिक कार्य-कुलशता होती है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस प्रणाली को लागू करने से व्यय बढ़ जायेगा और और यदि हां, तो कितना बढ़ जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कार्य-कुशलता के लिये और अधिक भार ढोने के लिये हमें यह प्रणाली लागू करनी पड़ी है और यह तो निश्चित ही है कि इससे कुछ अधिक व्यय करना पड़ेगा । परन्तु व्यय आवश्यमभावी है ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : यदि इस प्रणाली से अधिक कार्य-कुशलता होती है तो इसको एक ही समय सभी रेलवे में क्यों लागू नहीं किया गया ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम विभिन्न रेलवे पर भार के बारे में ध्यान रखते हैं और जब हम यह देखते हैं कि अब इस प्रणाली को लागू करने का और अधिक व्यय करने का समय आ गया है, तो हम ऐसा करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मैं यह समझूं कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह प्रणाली सभी रेलवे में लागू की जायेगी यदि हां, तो जैसा अभी पूछा गया था, भार से इसका क्या सम्बन्ध है, और इसको बाकी रेलवे पर भी क्यों लागू नहीं कर दिया जाता ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह तो निश्चित है कि डिवीजनल प्रणाली का यह तरीका अधिक कार्यकारी है और इससे अधिक कार्य-कुशलता मिलती है । परन्तु जैसा मैं ने कहा कि हम कार्य-भार पर निरन्तर ध्यान देते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का कहना है कि कार्य-भार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है और इसको इस परिवर्तन के साथ क्यों जोड़ा जाता है। यदि यह सिद्ध हो गया है कि यह अधिक कार्यकारी है तो इसको अन्य रेलवे पर भी क्यों नहीं लागू किया जाता ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह कोई प्रयोगात्मक प्रावस्था नहीं है और इसके बारे में वे अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं ? कार्य-भार का इससे क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसका कार्य-भार से सारा ही सम्बन्ध है । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य यह कैसे सोचते हैं कि इससे कार्य-भार का कोई सम्बन्ध नहीं है । और यह प्रणाली कार्य-भार को देखते हुए ही अपनायी गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्र० के० देव ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या हम यह समझें कि इससे कार्य-भार का सारा सम्बन्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें भिन्न भिन्न राय हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि इससे कार्य-भार का कोई सम्बन्ध नहीं है जबकि मंत्री महोदय का उत्तर है कि इससे कार्य-भार का पूरा सम्बन्ध है । प्रश्न-काल में इस मत-भेद को नहीं सुलझाया जा सकता। मुझे खेद है। मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकार चुका हूं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं इस बात को मान लेता हूं कि इससे कार्य-भार का पूरा सम्बन्ध है । मेरा प्रश्न है कि क्या हम यह समझें कि अन्य रेलवे पर कार्य-भार बहुत कम है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां । अनुपाततः कम है ।

†**श्री प्र० के० देव** : अभी अभी मंत्री महोदय ने बताया कि वे इस योजना को दक्षिण रेलवे पर भी लागू कर रहे हैं। क्या वह खुर्दा रोड में डिवीजनल सदर मुकाम बनायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सदर-मुकाम के बारे में बाद में निर्णय किया जायेगा।

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री तिरुमल राव ।

†**श्री प्र० के० देव** : मंत्री महोदय कुछ और कहना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कुछ कहना चाहें परन्तु इन ब्योरों में पड़ने में मुझे आपत्ति है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिरुमल राव** : मंत्री महोदय ने यह बताया था कि डिवीजनल प्रणाली को पुनः लागू करने से कार्य भार में सुधार हुआ है और इससे रेलवे बोर्ड को इस बात पर पुनः विचार करना पड़ा है कि विभागीय पद्धति के कारण मूल जोनल पद्धति अधिक कार्य-कुशल नहीं रही है । क्या रेलवे बोर्ड अथवा मंत्रालय के समक्ष जोनल पद्धति के समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार करने और रेलवे के कार्य को अधिक कार्यकारी और अधिक कार्य-कुशल बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : डिवीजन ही जोन के भाग हैं। समूचा देश आठ रेलवे ज़ोन में विभक्त कर दिया गया है और प्रत्येक रेलवे ज़ोन में, छः, सात अथवा आठ डिवीजन हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या वह पुनः जोनल प्रणाली नहीं अपना रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं ।

बिजली के 'मल्टिपल यूनिट स्टाक' का उत्पादन

†*२७७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजनावधि में बिजली के 'मल्टिपल यूनिट स्टाक' के उत्पादन की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितनी संख्या में ये तैयार किये जायेंगे ;

(ग) योजनावधि में बिजली के 'मल्टिपल यूनिट स्टाक' से रेलवे के कौन-कौन से मुख्य सेक्शनों का विद्युतीकरण किया जायेगा ; और

(घ) इनमें कितने पुर्जे देशी होंगे और कितने विदेश से आयात किये हुए ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष १६६२-६३ में बड़ी लाइन के १४१ सवारी डिब्बे बनाये जाने की आशा है ।

(ग) (१) सियालदह--रानाघाट और डमडम--बोनगांव ;

(२) सियालदह--डायमन्ड हारबर--बजबज लक्ष्मीकान्तपुर--कैनिंग और रानाघाट-- कृष्णगर शहर--शांतीपुर ।

(३) बर्दवान--हावड़ा--डाक्स (बरास्ता कार्ड)

(४) हावड़ा--खड़गपुर

(घ) इस समय विद्युतीकरण और नियंत्रण के सामान का आयात किया जाता है । यंत्रीकरण भाग के लिये देशीय हिस्से सामान की कुल लागत के ५५ से ६० प्रतिशत तक हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : बिजली के मल्टिपल यूनिट स्टाक्स की विशेष बातें क्या हैं ? क्या इसमें कोई विदेशी सहयोग है, और यदि हां, तो किस रूप में और किस देश से ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री सं० वें० रामस्वामी :** बिजली के मल्टिपल यूनिट उपनगरीय यातायात के लिये है। इस देश में क्षमता है । कलकत्ता के मेसर्ज जेसप्स इस वर्ष बिजली के ६८ मल्टिपल यूनिट सवारी डिब्बे बना रहे हैं। सामान्यतः इसमें तीन होते हैं—एक मोटर-कोच और दो ट्रेलर। ट्रेलर बनाने में कोई अधिक कठिनाई नहीं है परन्तु मोटर-कोच बनाने में हमें ट्रैक्शन सामान बाहर से मंगाना पड़ता है ।

†**श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या बिजली के मल्टिपल यूनिट का एक नमूना बनाया जा रहा है और यदि हां, तो इसके पूरा होने और उपलब्ध किये जाने की कब तक संभावना है ?

†**श्री सं० वें० रामस्वामी :** हमने इन्टीग्रल कोच फैक्टरी को ए० सी० मोटर कोच के दो नमूनों का आर्डर दिया ह । हम बिजली के ट्रैक्शन सामान विदेश से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उन पर प्रयोग करेंगे और यदि वे परिस्थिति में ठीक रहे तो हम उत्पादन आरम्भ कर देंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मंत्री महोदय ने बताया कि जेसप्स के यहां ये ६८ सवारी डिब्बे बनाये जायेंगे । बाकी ७४ डिब्बे कहां बनाये जायेंगे ?

†**श्री सं० वें० रामस्वामी :** बाकी ७३ बचते हैं। वे इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में बनाये जायेंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर-हावड़ा सेक्शन का विद्युतीकरण किया जा रहा है और, यदि हां, तो प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में इसका कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ?

†**श्री सं० वें० रामस्वामी :** मैंने उत्तर के भाग (ग) के संख्या (४) में बताया है— हावड़ा—खड़गपुर । वह वर्ष १९६५ में होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या इंजन-डिब्बे के लिये ट्रैक्शन सामान बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री सं० वें० रामस्वामी :** जी, हां । एसोसियेटेड इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज ट्रैक्शन सामान बनाने में हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल की सहायता कर रही है ।

†**श्री मुरारका :** जेसप्स के यहां बनाये जा रहे डिब्बों और इंटीग्रल कोच फैक्टरी में बनाये जा रहे डिब्बों के मूल्य की क्या तुलना है ?

†**श्री सं० वें० रामस्वामी :** इंटीग्रल कोच फैक्टरी के लागत ढांचे का अभी हमने हिसाब नहीं लगाया है । मैं अन्य व्यौरा दे सकता हूं। जेसप्स ने १६ लाख रुपये में यूनिट देने का प्रस्ताव किया है जब कि हमने वर्ष १९५५ में यह मैन, जर्मनी से १२.५ लाख रुपये में आयात किया था ।

"जल जवाहर" नामक जलयान का डूबना

†*२७८. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "जल जवाहर" नामक भारतीय मोटर जहाज स्पेन के उत्तर-पश्चिम किनारे पर डूब गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस भारतीय मोटर जहाज में क्या क्या सामान था ; और

(ग) इस जहाज को कितनी क्षति पहुंची है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) 'जल-जवहार' डूबा नहीं अपितु ब्रिटेन से बम्बई जाते हुए स्पेन के पश्चिम तट से दूर ४ मार्च, १९६२ को इसमें आग लग गई।

(ख) जहाज में सामान्य किस्म का माल लाया जा रहा था जिसमें विभिन्न रसायन थे जो जहरीले बताये गये थे परन्तु वे विस्फोटक, आग पकड़ने वाले और क्षयत्व नहीं थे।

(ग) जहाज कुछ क्षतिग्रस्त हो गया परन्तु कोई जन-हानि नहीं हुई।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†**श्री राज बहादुर** : उसका पता लगाया जाना है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या जांच आरम्भ कर दी गयी है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे ठीक पता नहीं है कि जांच आरम्भ की जा चुकी है या नहीं ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये यात्रा तथा भाड़े की रियायतें

+

†*२७१. { **श्री बासप्पा** :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री नाथ पाई :
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली यात्रा तथा भाड़ा सम्बन्धी रियायतों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों पर कोई फैसला किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि पी० टी० ओ० और पासों में कमी करने का यह प्रश्न मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है और यदि हां, तो रेलवे बोर्ड ने मंत्रिमण्डल से क्या सिफारिश की है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मामला विचाराधीन है।

†**श्री नम्बियार** : क्या सरकार को पता है कि रेलवे कर्मचारियों को पासों और पी० टी० ओ० की सुविधायें केवल भारत में ही नहीं परन्तु समूचे विश्व में दी जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज खां : जी हां। हमें पता है अधिकांश देशों में रेलवे कर्मचारियों को ये सुविधायें मिलती हैं।

†श्री नाथ पाई : क्या सरकार को कमी करने के बारे में रेलवे कर्मचारियों की उत्सुकता संबंधी अभ्यावेदन मिले हैं और यदि हां, तो क्या इन अभ्यावेदनों पर उचित रूप से विचार किया जायेगा ?

†श्री शाहनवाज खां : नेशनल फेडरेशन ग्राफ रेलवेमैन और ग्राल-इंडिया रेलवे मैन्स फैडरेशन से हमने पूरी तौर पर बात चीत की थी और उनके विचारों पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जायेगा।

†श्री वासप्पा : क्या सरकार ने इस निर्णय के अन्य विभागों में कर्मचारियों पर प्रभाव पर भी विचार किया है ?

†श्री शाहनवाज खां : हम इस पर अभी विचार कर रहे हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई सिफारिशें जो श्रमिकों के पक्ष में हैं, जैसे आकस्मिक श्रमिक, लागू नहीं की गयी हैं, क्या सरकार की यह नीति है कि उन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये जिससे कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ नहीं मिलते ?

†श्री शाहनवाज खां : जी, नहीं। सरकार की नीति यह नहीं है।

रेलवे के लोको शैडों में सामयिक श्रमिक[1]

†*२८०. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लोको शैडों में सामयिक श्रमिक रखने की प्रथा अभी जारी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) स्थायी रिक्त पदों पर सामयिक श्रमिकों की नियुक्ति विनियमित करने के लिये किस प्रक्रिया का अनुकरण किया जाता है ; और

(घ) सामयिक श्रमिकों को किस प्रक्रम पर केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन क्रम पाने का हक है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हां, केवल पूर्वोत्तर रेलवे को छोड़ कर।

(ख) सामयिक श्रमिक केवल आपात काल में ही लगाये जाते हैं अथवा तब लगाये जाते हैं जब ठेकेदार के श्रमिक असफल हो जाते हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) एक ही काम पर लगे छः मास की निरन्तर सेवा के बाद, सिवाय परियोजनाओं के काम के।

†श्री नम्बियार : जब कभी कोई स्थान खाली होते हैं तो क्या उन्हें भरने के उद्देश्य से सामयिक श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Casual Labour.

†श्री सें० वें० रामस्वामी : जी हां, । इस विषय में एक निदेश है और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

†श्री नम्बियार : क्या सरकार ऐसे लोगों के मामलों का, उन्हें स्थान देने के उद्देश्य से पुनरीक्षण करेगी जिन्होंने सामयिक श्रमिकों के रूप मे कई वर्ष कार्य किया है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : हम पूरी सहानुभूति से उनके मामलों पर विचार करेंगे।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या माननीय मंत्री को इस फैली हुई शिकायत का पता है कि जिन लोगो को लोको शैड में सामयिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया जाता है, उन्हें अपनी अवधि पूरी होने से पहिले हटा दिया जाता है और फिर उन्हें कुछ अन्तर से नियुक्त कर दिया जाता है। इसमें उनका मतलब यह होता है कि उनकी नौकरी पक्की न होने पाये ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह बात हमारे नोटिस में लाई गई है और हमने निदेश जारी कर दिया है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये ।

†श्री मुहम्मद इलियास : विभिन्न न्यायाधिकरणों तथा उच्चतम न्यायालय के इन वि निर्णयों तथा पंचाटों के कारण कि गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी स्थायी कार्यों पर सामयिक श्रमिक न लागाये जायें, क्या इन को रेलवे में भी लागू किया जायेगा , और रेलवे के स्थायी महत्व के कामों पर सामयिक श्रमिक नहीं लगाये जायेंगे ?

†श्री सें०वें० रामस्वामी : बिलकुल यही निदेश हमने सभी रेलवेज़ को भेजा है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार का विचार वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है, और जिस प्रकार सरकार और रेलवे बोर्ड के निदेश कार्यान्वित किये जा रहे हैं सके लिये जांच की जरूरत है और क्या सरकार का विचार इस बात की जांच करने का है कि हां तक वे कार्यान्वित हुए हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह बहुत बड़ा प्रश्न है। असल बात यह है कि सामयिक श्रमिक वल छः मास के लिये होता है यदि लगातार छः मास एक ही काम पर हो जाये तो उन्हें अस्थायी मेक बना दिया जाता है और उन्हें केन्द्रीय वेतन आयोग वाले क्रमों का लाभ प्राप्त हो जाता । यही निदेश है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न यह नहीं है। केन्द्रीय वेतन आयोग ने विशेष रूप से गरिश की है कि सामयिक श्रमिकों के बारे में निदेशों के कार्यान्वित किये जाने की जांच की जानी हये।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह मजदूर संघों का काम है कि इस बारे में स्थायो बातचीत वाली मशीनरी बातचीत करे।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर टर्मिनल इमारत

†*२८१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे की टर्मिनल इमारत, भारत के एक सर्वाधिक व्यस्त हवाई लिये पर्याप्त और योग्य है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मार्गों का सबसे अधिक हवाई यातायात होता है ;

(ग) क्या यहां अन्तर्देशीय मार्गों का भी सबसे अधिक हवाई यातायात होता है ;

(घ) क्या इसका विस्तार करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क), (घ) और (ङ) वर्तमान टर्मिनल इमारत को काफी नहीं समझा गया। १,०६,८३,००० रुपये की लागत से नयी टर्मिनल इमारत बनाने की स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) और (ग). जी, हां।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इस नयी टर्मिनल इमारत का काम शीघ्र ही आरम्भ किया जाने वाला है ; यदि हां, तो कब से ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह तो आरम्भ हो गया है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : टर्मिनल इमारतों और हवाई अड्डे में जैट धावन मार्ग के बनाने का काम एक साथ क्यों नहीं किया जाता ? दिल्ली में हो गया, कलकत्ता की उपेक्षा की गयी, मद्रास में जैटों . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। प्रश्न का संबंध एक टर्मिनल इमारत से है सबसे नहीं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : हमें मंत्री महोदय से यह पूछना है कि एक कार्य योजनाबद्ध कार्य क्यों नहीं होता। क्या कारण है कि टर्मीनल इमारत और जैट धावन मार्गों के निर्माण का कार्य एक साथ नहीं किया जाता ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह समन्वय युक्त योजना है। सारी चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों का निरंतर पुनरीक्षण किया जाता है और उस पर विचार होता है, और जब भी सुधारों के लिये योजनायें आती हैं तो स्वीकृत की जाती हैं।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†*२८४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने आदिम जादि क्षेत्र के सारे राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को विशेष बहु-प्रयोजनीय खंडों या आदिम जाति खंडों में बदलने के प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने खंड बदले गये; और

(ग) भविष्य में विशेष बहुप्रयोजनीय खंड या आदिम जाति खंड बनाने या पुराने को उन में बदलने का क्या कार्यक्रम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति):** (क) से (ग) इस प्रश्न का उत्तर देना गृह-कार्य मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। वही मंत्रालय इस प्रश्न से सम्बन्धित है और बाद में किसी दिन गृह कार्य मंत्री ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे।

यमुना पर आगरा में राजपथ का पुल

†*२८५. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में यमुना नदी पर राजपथ का एक और पुल बनाने का प्रस्ताव था ताकि वर्तमान रेल-सड़क पुल पर यातायात का जमाव कम हो जाये और यातायात काफी देर न रुका रहे ;

(ख) क्या प्रस्ताव मंजूर हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां।

(ख) नहीं, धन की कमी के कारण इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या इस प्रस्थापना को पहली बार ही स्वीकृत कर लिया गया था ?

†**श्री राज बहादुर :** वास्तव में कुछ प्रारम्भिक कार्य भी किया गया था । सर्वेक्षण भी कर लिया गया था और जमीन भी अर्जित कर ली गई थी, परन्तु धन की कमी के कारण अभी हाल उसे छोड़ दिया गया है ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या सरकार इस प्रस्थापना पर पुनः विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो कार्यवाही का सुझाव है ?

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनायें

†*२८६. **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं में सिंचाई की कितनी बड़ी और मध्यम परि-योजनायें आरम्भ की गयीं;

(ख) उन पर क्या व्यय हुआ ;

(ग) उन से कितनी सिंचाई हो सकेगी; और

(घ) इन परियोजनाओं से १९६१–६२ में वस्तुतः कितनी जमीन की सिंचाई हुई ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम):** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

प्रथम पंचवर्षीय योजना में २५० सिंचाई परियोजनायें (२० बड़ी और २३० मध्यम) सम्मिलित की गयी थीं, जिन में से २३७ (१६ बड़ी और २१८ मध्यम) परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये चुना गया था। ये सब प्रथम योजना काल में कार्यान्वित होनी थीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में १८८ नयी योजनायें (३० बड़ी और १५८ मध्यम) सम्मिलित की गयी थीं, उन में १५४ सिंचाई परियोजनायें (२१ बड़ी और १३३ मध्यम) कार्यान्वित करने के लिये चुनीं गयी थीं। इस के अतिरिक्त १३ वे सिंचाई योजनायें भी जिन्हें प्रथम योजना काल में नहीं लिया जा सकता था। इस तरह दूसरी योजना काल में ली जाने वाली परियोजनाओं की संख्या १६७ हो गयी।

दूसरी योजना के अन्त तक इन परियोजनाओं पर २७० करोड़ रुपया खर्च हुआ।

इन परियोजनाओं के द्वारा १९६१–६२ तक जो सिंचाई क्षमता का निर्माण हुआ वह १२९ लाख एकड़ थी। १९६१–६२ में ९८ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होने की आशा है। १९६१-६२ के अन्त के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

†**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** विवरण से स्पष्ट है कि ४३८ परियोजनाओं में से केवल ४०४ पर अमल हुआ। इन योजनाओं में से अभी तक कितनी पूर्ण हो चुकी हैं ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** यह विवरण में दिया हुआ है, यदि सदन की इच्छा हो तो मैं पढ़ देता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि विवरण में है तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं।

†**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** जो ४० योजनाओं को छोड़ दिया गया उन की स्थिति क्या है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** मेरे अनुमान के अनुसार जो आंकड़े माननीय सदस्य प्रस्तुत कर रहे हैं वे मेरे आंकड़ों से नहीं मिल रहे। मैं पता करूंगा और माननीय सदस्य को स्थिति बता दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को मेरे "अगला प्रश्न" कहने से पहले खड़ा होना चाहिये था।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं खड़ा हुआ था, श्रीमान्।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या ठीक है कि कुछ समय हुआ मेरे ख्याल में गत लोक-सभा में प्रधान मंत्री ने बड़ी बड़ी परियोजनाओं के विरुद्ध और छोटी परियोजनाओं के पक्ष में मत प्रकट किया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो मैं "अगला प्रश्न" कहने में ठीक ही था।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह प्रश्न बड़ी तथा छोटी दोनों प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्ध रखता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब आप बताइये कि आप कौन सी जानकारी चाहते हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : दूसरी लोक सभा में मैं था नहीं; इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि यदि उन्होंने यह कहा है तो क्या बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के कार्यों में फेर बदल किया जा रहा है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : छोटी बड़ी दोनों तरह की परियोजनायें बहुत जरूरी हैं। किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्येक योजना का परीक्षण करना होता है। उनके गुणों को देख कर ही आयोग उन के बारे में कोई निर्णय लेता है कि कौन सी योजना सम्मिलित की जाये और कौन सी छोड़ी जाये ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्राथमिकता देने का प्रश्न है, उपेक्षा करने का नहीं।

†**श्री थलमंदा रेड्डी** : विवरण में कहा गया है कि १९६१–६२ में १२६ लाख एकड़ भूमि की क्षमता का निर्माण किया गया है परन्तु सिंचाई की आशा ९८ एकड़ भूमि पर ही है। ३० लाख एकड़ छूट जायेगा। इस के क्या कारण हैं ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : यह पुरानी स्थिति है, विषमता प्रति दस वर्ष कम होती जा रही है। यदि सभा की इच्छा हो तो इस सम्बन्ध में किये गये सुधा के आंकड़े प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

उरन से गेटवे आफ इंडिया तक झूला पुल

†*२८८. **श्री नाथ पाई** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उरन से गेटवे आफ इंडिया तक झूला पुल के निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार न योजना की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). प्रस्तावित पुल जब भी बनाया गया राज्य सड़क परियोजना का अंग होगा। अतः इस का राज्य सरकार का प्रारम्भिक सम्बन्ध है। उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई प्रस्थापना प्रस्तुत नहीं की है।

†**श्री नाथ पाई** : क्योंकि बम्बई में भी यातायात की बढ़ती हुई समस्याओं को हल करना सरल नहीं, क्या भारत सरकार राज्य सरकार की इस मामले में सहायता करेगी ताकि इस प्रस्थापना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा सके ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम से यही पूछा गया है कि क्या हमें बम्बई सरकार से कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है। मुझे उत्तर में यही कहना है कि हमें कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री नाथ पाई** : मेरी जानकारी यह है कि राज्य सरकार इस ५० करोड़ मद की महत्वपूर्ण परियोजना को तब तक ही हाथ में ले सकती है जब कि केन्द्रीय सरकार से कुछ सहायता अथवा कर्जा उपलब्ध हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अथवा मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नाथ पाई : मैं जानना चाहता हूं कि इस जानकारी के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†श्री राज बहादुर : मुझे इस बहुत बड़ी परियोजना की उपयोगिता के बारे में कोई सन्देह नहीं। यह बहुत अच्छी है। इस से देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचेगा। इस से बम्बई में यातायात की भीड़ कम करने में सहायता जरूर मिलेगी। परन्तु हर बात का आधार वह धन है जोकि हमें उपलब्ध हो सकता है।

गन्ने की पिराई

+

†*२८६. श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बा० वर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में गन्ने की पिराई के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस बारे में जानकारी है कि सभी राज्यों में खेतों में खड़ा समस्त गन्ना मिलों अथवा अन्य कारखानों द्वारा पेर लिया जायेगा;

(ग) कितना नहीं पेरा जा सकेगा तथा देश के किस भाग में ; और

(घ) स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) ३१ मार्च १९६२ तक कारखानों द्वारा विभिन्न राज्यों में ५६.८ करोड़ मन गन्ना पेरा गया।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानों ने शेष गन्ने की पिराई इस शर्त पर करने की पेशकश की है कि उन्हें कुछ रियायतें दी जायें और काश्तकारों को चीनी की 'रिकवरी' के आधार पर समुचित दाम दिया जाय ?

†श्री अ० म० थामस : बिहार के कारखाने वाले तो 'न लाभ न हानि' के आधार पर गन्ने की पिराई करना मान गये हैं। परन्तु इस बारे में विस्तारपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है। वास्तव में बिहार के गन्ना आयुक्त और सचिव आये थे और उन्हों ने हमारे अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की थी।

†मूल अंग्रेजी में

वे यह कह कर गये थे कि केन्द्रीय सरकार के समक्ष इस बारे में निश्चित प्रस्थापनायें प्रस्तुत करेंगे। यह राज्य सरकार का काम है यदि वह चाहे तो सारे गन्ने की पिराई के विचार से गन्ना उपकर छोड़ सकती है।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या राज्य सरकारों ने उनकी सहायता करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार से रियायतें देने का अनुरोध किया है ?

†श्री अ० म० थामस : इस बारे में बिहार के मुख्य मंत्री ने माननीय मंत्री को पत्र लिखा था और उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। यदि गन्ना उपकर छोड़ दिया गया तो इस से एक प्रतिशत तक वसूली कम हो जायेगी। यह गन्ना उपकर ३ आना प्रति मन का है। बिहार सरकार का विचार तो उत्पादन शुल्क में भी कुछ छूट देने का है। इस बात पर और आगे विचार करने का है। मेरा निवेदन है कि यदि राज्य सरकार कारखानों और गन्ना उत्पादकों ने यह काम हाथ में लिया तो मेरा विचार है कि सारा गन्ना पेरा जा सकेगा।

†श्री अ० ना० विद्यालंकार : गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये क्या किया गया है ?

†श्री अ० म० थामस : मैं ने कहा है कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इस ने कमी वाले इलाके का आवंटन वहां कर दिया जहां कि गन्ने का उत्पादन जरूरत से अधिक है। अतः केन्द्रीय सरकार इससे अधिक इस समय कुछ नहीं कर सकती।

†श्री वी० चं० शर्मा : क्या केवल बिहार राज्य ही विचाराधीन है कि भारत के अन्य राज्यों पर भी विचार किया जा रहा है ; यदि हां तो कहां तक ?

†श्री अ० म० थामस : यह समस्या केवल बिहार और उत्तर प्रदेश से ही पैदा हुई है। दक्षिण में यह बात नहीं है, क्योंकि वहां कम 'रिकवरी' का प्रश्न ही नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सम्बन्ध है, बताया गया है कि उन का विचार सारे गन्ना उपकर की छूट देने का है ताकि सारा फालतू गन्ना पेरा जा सके। बिहार सरकार—जैसाकि मैं ने कहा है—'न हानि न लाभ' के आधार पर गन्ने की पिराई कर रही है।

†श्री हेडा : क्या सरकार को यह पता है कि आंध्र प्रदेश की निजाम चीनी फैक्टरी ने सारा गन्ना पेरने से इन्कार कर दिया है। वह उतना भी गन्ना पेरने को तैयार नहीं जितना कि उस ने गत वर्ष पेरा था। उन का कहना है कि केन्द्रीय सरकार ने १० प्रतिशत की कटौती कर देने का निदेश दिया है ?

†श्री अ० म० थामस : केन्द्रीय सरकार की ओर से बिल्कुल कोई निदेश नहीं दिया गया। वास्तव में हम ने तो सभी चीनी कारखानों से कह दिया कि उन्हें सारा का सारा गन्ना पेरना होगा। केवल कम 'रिकवरी' का प्रश्न है जिस के कारण हो सकता है कि कुछ कारखाने सारा गन्ना नहीं पेर सकें और गन्ना लेने से इन्कार कर दें। यह केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में ही होगा।

†श्री शि० स्वामी : क्या होसपट और काम्पली के चीनी कारखानों में केवल ७५ प्रतिशत गन्ना ही पेरा जा रहा है ? इस से सारी खड़ी फसल नष्ट हो रही है ?

†श्री अ० म० थामस : वह नष्ट नहीं हो रही है। वास्तव में मैं व्यक्तिगत रूप से इस के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हूं कि गन्ना उत्पादकों को हानि न पहुंचे। जब मैसूर की अन्य स्थानों पर कमी की घोषणा हुई तो हम ने काम्पली और होसपेट के कारखाने को 'पुनः आवंटन' कर दिया।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय उपमंत्री महोदय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना उपकर छोड़ रही है ताकि सारे गन्ने की पिराई हो जाय। नियोजकों ने अभी बकाया गन्ना उपकर की भा ी राशि का भुगतान नहीं किया है। क्या भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को उपकर की छूट देने की अनुमति दे दी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह मामला राज्य सरकार के प्राधिकार का है वह जैसा चाहे कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार इस में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी।

श्री बड़े : क्या सच नहीं है कि चूंकि आजकल नई शुगर फैक्ट्रीज़ स्टार्ट करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है इसलिए मध्य प्रदेश में शुगर केन अनक्रश्ड पड़ा रहता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : नई फैक्ट्रीज़ तो बहुत हैं सदर्न रीजन में। उस को परमिशन मिलती है। मैं मानता हूं कि वहां शुगर प्रोडक्शन बढ़ा है, कम नहीं हुआ है।

श्री बड़े: मेरा प्रश्न यह है कि चूंकि मध्य प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज़ के लिये लाइसेन्स नहीं मिलते हैं इसलिये वहां शुगर केन अनक्रश्ड पड़ा रहता है, यह सच है या नहीं।

श्री स० का० पाटिल : इस तरह तो आज कल किसी को परमिशन नहीं मिलती है क्योंकि हमें १० लाख टन शुगर ज्यादा मिली है। तब भी कभी-कभी ऐसे केसेज़ होते हैं कि कोआपरेटिव फैक्ट्रीज़ लोगों को खोलनी होती हैं, साथ ही ऐसे रीजन होते हैं जहां पर रिकवरी अच्छी है या जहां गन्ना ज्यादा होता है। उन में अगर मध्य प्रदेश आयेगा तो उस को भी इजाजत मिल जायेगी।

†**श्री दे० द० पुरी** : माननीय उपमंत्री ने कहा कि यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश और बिहार ही की है। क्या इस बारे में उसे पंजाब सरकार से भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक १० प्रतिशत कटौती का सम्बन्ध है, हम ने राज्य सरकारों को बता दिया है कि जहां तक सम्भव होगा खड़ी फसल कहीं भी होगी उसे सूखने नहीं दिया जायेगा। अतः जहां भी प्रश्न उत्पन्न होगा या कमी महसूस होगी, हम हस्तक्षेप करेंगे। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि सारी खड़ी फसल की पिराई अवश्य होगी।

गेहूं का उत्पादन

†*२९०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में गेहूं के उत्पादन का क्या अनुमान है ;

(ख) सरकार का समाहार कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) सरकार का विदेशों से मंगाया गया तथा देश में वसूल किया गया वर्तमान स्टाक कितना है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १९६१-६२ में गेहूं के उत्पादम की सूचना केवल जून १९६२ में प्राप्त होने की आशा है।

(ख) देश की मंडियों से अभी तक सरकार ने कोई गेहूं नहीं खरीदी। देश में वितरण के लिए गेहूं बाहर से मंगाया जाता रहा है। देश में से गेहूं खरीदने का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अप्रैल १९६२ में सरकार के पास निम्नलिखित गेहूं का स्टाक था :—

	(एक हजार मीट्रिक टनों में) बाहर का	देश का
केन्द्रीय डिपों में	१,३२३	..
राज्य सरकारों के पास	८२	२
कुल	१,४०५	२

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार को इस वर्ष भारी फसल की आशा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : गत वर्ष १०८ लाख मीट्रिक टन का उत्पादन था। इस वर्ष इस से कुछ अधिक अर्थात् ११० लाख मीट्रिक टन हो जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या केन्द्रीय सरकार ने खरीद के मामले में राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम ने गेहूं को कम से कम कीमत निर्धारित कर दी है, उत्तम कोटि के लिए १४ रुपये और लाल कोटि के लिए १२ रुपये। यदि कीमतें इस से नीचे चली जायें तो हम सब गेहूं ख़रीद लेंगे।

डा० गोविन्द दास : जबकि इस वर्ष आशा है कि हमारी गेहूं की फसल बहुत अच्छी होगी तो क्या इस बात का विचार किया जा रहा है कि हम बाहर से गेहूं उससे कम मंगायें जितना पिछले साल मंगाया था, और कब तक यह आशा की जाती है कि हमें बाहर से गेहूं न मंगाना पड़ेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): बाहर से गेहूं इसलिये आता है कि जो हमारा पुराना कंट्रैक्ट है चार वर्ष के लिये उसको तो हम को पूरा करना ही चाहिये, वह भी स्टाक पाइल के लिये जो कि ५० लाख टन का हम रखना चाहते हैं। नहीं तो बाहर से गेहूं नहीं आता है। मैं मानता हूं कि जो आस्ट्रेलिया और कैनाडा से मार्केटिंग का एक क्लाज है उसके मुताबिक भी थोड़ा हम लेते हैं। और किसी तरह से बाहर से आने की सम्भावना नहीं है। मैंने एक नहीं कई दफे कहा है कि दो चार वर्ष के बाद हमें गेहूं बाहर से लेना ही नहीं पड़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

देश में बाल पक्षाघात (पोलियो) के मामले

†*२७१. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बाल पक्षाघात (पोलियो) के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में हुई इस बीमारी के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२]

नर्सों का प्रशिक्षण

†*२८२. { श्री अ० सिं० सहगल :
श्री बिशनचंद्र सेठ :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्सों को इस समय जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो उनको व्यापक प्रशिक्षण देने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ;

(ग) इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(घ) इन सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और बातों के साथ-साथ समिति ने यह भी सिफारिश की है कि शिक्षार्थी नर्सों के पास अस्पतालों में सामान्य दैनिक कार्य अधिक नहीं होना चाहिये। लेकिन प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक अनुभव पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

(घ) समिति ने जो सिफारिशें की हैं वे नर्सिंग स्कूल सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में लागू की जा चुकी हैं।

स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा योजना समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं ताकि वे सिफारिशों के बारे में आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

सोनपुल

†*२८७. { श्री फ० गो० सेन :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन पुल का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि की सहायता से आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब पूरा होगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ऋण कार्यक्रम के अधीन इस पुल के निर्माण कार्य के लिये भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है और विश्व के सारे देशों से इसके लिये टेंडर मांगे गये हैं।

(ख) मार्च १९६५ के अन्त तक इसके समाप्त हो जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माता टीला बांध

†*२९१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में माता टीला परियोजना अब पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) इस पर कितनी रकम खर्च हो जाने की आशा है; और

(घ) बांध को पूरा करने के लिये कितनी रकम खर्च हो जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) माता टीला बांध का प्रथम प्रक्रम समाप्त हो गया है । दूसरे प्रक्रम के अधीन सीमा वाला बांध तथा प्रदर्शक दीवार बना दी गई है । शेष काम जैसे नालियों का बनाना, स्पिलवे दरवाजे, बड़े-बड़े दरवाजे तथा नहर का पुनर्नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ३१ मार्च १९६१ तक इस बांध के प्रक्रम १ तथा २ पर १०३० लाख रुपये व्यय हुए हैं ।

(घ) ११९९.४० लाख इसमें परियोजना के जल विद्युत् भाग का व्यय सम्मिलित नहीं है ।

"इंडियन नेवीगेटर" जहाज के साथ दुर्घटना

†*२९२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ते के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट का फैसला तथा टिप्पणी देखी है जो 'इण्डियन सक्सैस' के १३ कर्मचारियों की दुखद मृत्यु के सम्बन्ध में है और जिनको जहाज के कप्तान ने ३१ दिसम्बर, १९६० को अटलांटिक सागर में विस्फोट के पश्चात् डूबे हुये जहाज 'एस० एस० इण्डियन नेविगेटर' पर भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।
(ख) प्रतिवेदन पर सरकार आजकल विचार कर रही है ।

नमूने की मोटर कोच[1]

†*२९३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो नमूने की मोटर कोच (प्रोटोटाइप मोटर कोच) बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का खर्चा क्या है ;

(ग) इनका निर्माण कब तक हो जायेगा ;

(घ) क्या इनका निर्माण पूर्णतः देसी वस्तुओं से होगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें कितने पुर्जे आयात किये हुये होंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक कोच का अनुमानित मूल्य ९ लाख रुपये है ।

(ग) १९६३ तक उनके बन जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Prototype Motor Coach.

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रोटोटाइप कोचें पूर्ण रूप में विदेशों से आयात की जायेंगी जिसका मूल्य ६ लाख रुपये होगा । इसमें से ५ लाख रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे । मोटर कोचों के लिये विदेशों से जिन पुर्जों का आयात होगा उनका अनुमान ४० से ४५ प्रतिशत तक होगा ।

मनीपुर में डाक्टरों की कमी

†*२९४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में ४२ डिस्पेंसरियों, चार अस्पतालों तथा दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इस समय डाक्टर नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मनीपुर तथा अन्य किसी स्थान से डाक्टरों की सेवायें प्राप्त करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नर्मदा घाटी परियोजना

†*२९५. **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुप्रयोजनीय नर्मदा घाटी परियोजना की क्रियान्विति में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) परियोजना पर कितना खर्चा होने का अनुमान है और इससे कितनी सिंचाई और विद्युत् क्षमता उपलब्ध हो जाने की आशा है ; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) परियोजना का पहिला प्रक्रम जो ब्रोच परियोजना के नाम से भी विख्यात है, योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है । और राज्य सरकार ने प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया है। मुख्य बांध पर इस वर्ष काम शुरू होने वाला है ।

(ख) परियोजना के प्रथम प्रक्रम पर लगभग ४१.४१ करोड़ रुपये व्यय होंगे और लगभग १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। दूसरा प्रक्रम पूरा हो जाने पर इससे ६.० किलोवाट बिजली तैयार होने लगेगी और लगभग १० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होने लगेगी ।

(ग) अभी तो पहले प्रक्रम की स्वीकृति ही दी गई है और वह चौथी योजना के दौरान में शायद समाप्त होगी ।

इलैक्ट्रो मैगनैटिक सौर्टिंग मशीन[1]

†*२९६. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर नगर रेलवे डाक सेवा कार्यालय में इलैक्ट्रो मैगनेटिक सौर्टिंग मशीन स्थापित की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Electro Magnetic Setting Machine.

(ख) यदि हां, तो इसकी चालन रफ्तार क्या है तथा यह कितनी सफल हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) अभी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

हैजा

†*२६७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैजे से प्रभावित भारत के कुछ स्थानिक क्षेत्रों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भेजे गये विशेषज्ञों के दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भारत सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन दलों द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार किस सीमा तक क्रियान्वित करेगी ;

(ग) मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) क्या इसके वित्तीय पहलू पर विचार कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**

कलिंग एयरलाइन्स

†*२६८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९, १९६० तथा १९६१ में कलिंग एयरलाइन्स की कई दुर्घटनायें हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी दुर्घटनायें हुईं थीं ;

(ग) दुर्घटनाओं को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय के उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) तथा (ख). इस दौरान में कलिंग एयरलाइन्स के ६ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए जिनमें से दो दुर्घटनाएं छोटी छोटी थीं ।

(ग) तथा (घ). वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]**

पठानकोट रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय

†२५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान में उत्तर रेलवे के पठानकोट स्टेशन पर कितने प्रतीक्षालय बनवाये गये हैं ; और

(ख) यदि एक भी नहीं बनवाया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान में २ अतिरिक्त प्रतीक्षालय बनवाये गये हैं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बटाला में चीनी निर्माण

†२५१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बटाला तथा मोरिंदा सहकारी चीनी मिलों को चीनी बनाने के लिये संयंत्रों का संभरण करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या उपरोक्त मिलों ने काम करना शुरू कर दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) तथा (ख). बटाला तथा मोरिंदा सहकारी संस्थाओं ने १९६० में मशीनों के लिये आदेश दिया था। मशीनों के संभरण करने का काम ज़ोरों से चल रहा है और ऐसी आशा है कि ये १९६२-६३ में अपना काम शुरू कर देंगे ।

अमृतसर-पठानकोट लाइन पर यात्रियों को सुविधा

†२५२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९, १९६० तथा १९६१ के दौरान में उत्तर रेलवे के अमृतसर पठानकोट लाइन पर आने वाले स्टेशनों पर मालगोदाम के लिये शेड बनाने, पीने के पानी का प्रबन्ध करने, पार्सलों के लिये गोदाम बनाने, तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालयों का विकास करने एवं उन पर छत डालने के बारे में कुछ सुझाव आये हैं ;

(ग) यदि हां, उनमें से कितनों को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) तो उनमें से कितनों के बारे में कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी हां। १९५९, १९६० तथा १९६१ के दौरान में निम्नलिखित सुझाव मिले हैं :

(१) बटाला में मालगोदाम शेड का विस्तार ;

(२) बटाला में यात्रियों के प्रतीक्षालयों का विस्तार ;

(३) वेरका में मालगोदाम शेड पर छत डालना ;

(४) बटाला में माल लदान करने वाले स्थान का विस्तार करना ;

(५) सरना में यात्रियों के प्रतीक्षालय से शेड हटाकर मालगोदाम पर डालना ।

(ख) इन सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है ।

(ग) (१) बटाला में मालगोदाम शेड को दोनों ओर से खुला रख कर बनाने का काम पूरा हो गया है ।

(२) बटाला में यात्रियों के प्रतीक्षालय पर शेड डालने का काम शुरू हो गया है ।

(३) सरना में यात्रियों के प्रतीक्षालय से शेड को हटाकर मालगोदाम पर डालने का काम मंजूर कर लिया गया है और शीघ्र ही वहां काम शुरू होने की आशा है ।

(४) वेरका में मालगोदाम शेड बनाने तथा बटाला में मालगोदाम साइडिंग को बढ़ाने का काम निधि उपलब्ध होने पर आगामी वर्षों में शुरू किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सड़क दुर्घटना

†२५३. **श्री वी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के दौरान में दिल्ली परिवहन उपक्रम की कितनी बसें दुर्घटना-ग्रस्त हुईं ;

(ख) १९६० की अपेक्षा दुर्घटनाओं की स्थिति कैसी रही ; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १८४५।

(ख) १६३८। इस वर्ष दुर्घटनाओं की संख्या इसलिये अधिक रही क्योंकि एक तो बसों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा दूसरे उनकी प्रतिदिन की यात्रा की लम्बाई भी अधिक बढ़ा दी गई है ।

(ग) (१) चालकों को सुरक्ष रखने तथा मन्थर गति से चलाने के लिये व्यावहारिक तथा मौखिक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(२) अधिक तेज़ चाल को रोकने तथा लापरवाही से बसों को चलाने की गति को देखने के लिये एक विशेष दस्ते द्वारा आकस्मिक रोकथाम की जाती है । और दोषी चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

(३) अच्छी तरह चलाने तथा कोई दुर्घटना न करने पर ऐसे चालकों को हर तिमाही में २० रुपये का पुरुस्कार दिया जाता है ताकि उनको अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती रहे ।

टेलीफोन के कनेक्शन

†२५४. **श्री इ० मधुसूदन राव : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ के दौरान में हैदराबाद तथा वारंगल क्षेत्रों में नये टेलीफोन के लिये कुल कितने प्रार्थनापत्र आये तथा उनमें कितने प्रार्थनापत्रों के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ख) उसी अवधि में कुल कितने नये टेलीफोन लगाये गये ; और

(ग) अधिक टेलीफोन लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिट १, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ग) **वारंगल** भूमिगत कुछ तार बिछाना है । तार आने की देरी है ।

हैदराबाद

हैदराबाद के ग्वालीगुडा एक्सचेंज के स्थान पर दूसरा स्वचलित एक्सचेंज बनाया जा रहा है तथा ९०० लाइन बढ़ा कर उसकी क्षमता भी बढ़ाई जा रही है । सैफाबाद के स्वचलित एक्सचेंज को ५०० लाइन बढ़ा कर क्षमता भी बढ़ाई जा रही है । क्षमता बढ़ाने का यह कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा और उसके बाद हो नये कनेक्शन दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में कोढ़ियों का बन्ध्यकरण

†२५५. { श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री अ० सि० सहगल :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम ने अब तक कुल कितने कोढ़ियों का वन्ध्यकरण किया है ;

(ख) इनमें से कितने पुरुष हैं तथा कितनी महिला;

(ग) क्या दिल्ली के अथवा उसके आसपास के सभी कोढ़ी वन्ध्यकरण के लिये तैयार हो गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनकी कुल कितनी संख्या होगी ; और

(ङ) इस कार्य पर कुल कितना व्यय होगा ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) तथा (ख) वन्ध्यीकरण के लिये अब तक कुल ३६ कोढ़ियों ने अपने आपको समर्पित किया है, और निगम द्वारा अब तक कुल ३१ कोढ़ियों का वन्ध्यकरण किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) वांछित जानकारी तो मिल नहीं सकी है । किन्तु फिर भी जो आपरेशन करायेंगे उनमें से प्रत्येक को निगम द्वारा १५ रुपये दिये जायेंगे ।

क्विलौन में ऊपरी पुल

†२५६. श्री मे० क० कुमारन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के मदुर क्षेत्र में क्विलौन नामक शहर में रेलवे सड़क पार करने के लिये जो द्वार बने हैं उनके स्थान पर ऊपरी पुल बनाने के प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): रेलवे लाइनों पर ऊपरी भूमिगत पुल बनाने की योजना राज्य सरकारों द्वारा चालू की जाने की हैं । रेलवे उपक्रम उन्हीं कामों को अपने हाथ में लेता है जिनकी सिफारिश राज्य सरकारें करती हैं और सड़क प्राधिकारियों को खर्च करने के लिये नियम के अनुसार अपना अंश देती है ।

क्विलौन स्टेशन के आसपास के चार क्रोसिंग में से केरल सरकार ने केवल एक क्रोसिंग के बारे में सिफारिश की है जो क्रू ४७३/२५-२६ (चिन्नाकडडूई लेविल क्रोसिंग) पर स्थित है । रेलवे का अंश इस काम के लिये जितना होगा उसकी स्वीकृति दे दी गई है और राज्य सरकार के परामर्श से यह काम शुरू होने को है ।

नई दिल्ली में स्कूल के बच्चों के लिये स्वास्थ्य सेवा योजना

†२५७. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने नई दिल्ली में स्कूल जाने वाल बच्चों के स्वास्थ्य के लिये कोई योजना बनाई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस योजना की विस्तृत बातें क्या है ;

(ग) इस योजना को कितने क्षेत्र में लागू किया जायेगा ; और

(घ) नगरपालिका प्रति वर्ष कितना धन व्यय करेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां ।

(ख) से (घ). इस स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आजकल नगरपालिका के ८,००० बच्चे तथा गैर नगरपालिका के स्कूलों के ७,००० बच्चे लाभ उठा रहे हैं।

ऐसा विचार है कि इस योजना से ५५ स्कूलों के (४१ नगरपालिका के तथा १४ गैर नगर-पालिका स्कूलों) २६,००० बच्चों को लाभ पहुंचे । सारे क्षेत्र को ५ बराबर की जोनों में बांटा जायेगा जिसमें से प्रत्येक जोन की देखभाल एक विशेष चिकित्सा पदाधिकारी करेगा। मुख्य अस्पताल के अधीन दो छोटे छोटे अस्पताल भी होंगे । नीचे लिखे ढंग के अनुसार स्कूलों को निम्न जोनों में बांटा जायेगा :

(१) प्रत्येक जोन में विद्यार्थियों की संख्या लगभग एक समान होगी ;

(२) स्कूलों को इस ढंग से रखा जावेगा ताकि स्कूल चिकित्सा पदाधिकारी आसानी से वहां जा सकें;

(३) लड़के तथा लड़कियों की संख्या के अनुसार;

(४) कुल लड़कों के लिये ३ चिकित्सा पदाधिकारी एवं कुल लड़कियों के लिये दो चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

इस स्कूल स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य नागरिकों के प्रारम्भिक जीवन में स्वास्थ्य को बनाने के लिये प्रबन्ध करना ताकि उनका स्वास्थ्य सुधर सके और बच्चों में मूलभूत बीमारी न रह सके ।

नगरपालिका आजकल १५,००० बच्चों पर ५७,८३५ रुपये व्यय कर रही है । इस योजना को बढ़ाने के लिये इस चालू वित्तीय वर्ष में ३५,००० रुपये व्यय होने की संभावना है, और तीसरी योजना के बाकी तीन वर्षों में २०,००० रुपये प्रति वर्ष व्यय होंगे ।

दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति

†२५८. **श्री सिद्धय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में उस आदेश को लागू कर दिया गया है जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे जिनकी भर्ती पदोन्नति के आधार पर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण रेलवे में १ अप्रैल १९६२ तक प्रत्येक श्रेणी में उनके लिये कितने कितने सुरक्षित रखे गये हैं;

(ग) क्या उन सभी पदों के लिये चुनाव कर लिया गया है और क्या उन स्थानों पर व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

संवरण पद[1]

†२५९. श्री सिद्धय्या : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय केन्द्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति से पहले रेलवे प्रशासन में कौन से पद ऐसे थे जिन्हें संवरण पद माना जाता था;

(ख) कौन से संवरण पद अब "गैर संवरण पद" हो गये हैं;

(ग) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब कौन से "गैर संवरण पद" अब "संवरण पद" बना दिये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १ अनुबंध संख्या ४६७**।]

(ख) तथा (ग). द्वितीय वेतन आयोग ने तो ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी किन्तु कुछ श्रेणियों के मिश्रण करने से ऐसा करना स्वाभाविक हो गया था और उनका उल्लेख विवरण में दिया गया है ।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के उम्मीदवारों को संवरण पदों पर पदोन्नति

२६०. **श्री सिद्धय्या**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रल, १९६२ तक उस आदेश के अनुसार जिसके अन्तर्गत कुछ प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए संवरण पद सुरक्षित रखे जाते हैं, प्रत्येक रेलवे में ऐसे कितने उम्मीदवारों को पदोन्नति दी गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

१९६१-६२ में विभागीय भोजन व्यवस्था

†२६१. **श्री सिद्धय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में रेलवे को विभागीय भोजन व्यवस्था से कितना लाभ या हानि हुई है; और

(ख) क्या व्यय में कमी करने के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) १९६१ के लिए अनुमानित हानि ६.५ लाख रुपये है, जिस में पिछले सालों का ४ लाख रुपये का घाटा भी जमा है।

(ख) हानि को घटाने के लिए उठाये गये कदमों में से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं :—

(१) खाद्य पदार्थों के क्रय मूल्यों में बचत और नियंत्रित पदार्थों का अधिकृत, नियंत्रित निर्धारित मूल्यों पर क्रय।

(२) विभिन्न प्रकार के भोजनों के लिए निर्धारित वस्तुओं की संख्या कम कर देना।

(३) बिक्री को बढ़ाना और वेटरों, स्टाल वालों और खौंचे वालों को कमीशन के आधार पर खाना बेचने और खिलाने के लिए नियुक्त करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Selection Post.

(४) विभिन्न प्रकार के भोजन स्नेक आदि देना, ताकि विभागीय भोजन व्यवस्था अधिक लोकप्रिय हो सके और बिक्री बढ़ सके तथा ऊपर का खर्च कम हो सके।

(५) पकाने के लिए ईंधन के प्रयोग में कमी करना।

(६) सफ़ाई ठेकों को बढ़ाना और वेतन पाने वाले क्लीनरों के पदों को समाप्त करना।

श्रीरंगापटनम के समीप कावेरी पर पुल

†२६२. **श्री सिद्धय्याः** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के बंगलौर-मैसूर विभाग पर श्रीरंगापटनम के करीब कावेरी पर पुल बनाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) काम कब खत्म होगा; और

(ग) योजना का कुल व्यय कितना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) श्रीरंगापटनम के करीब कावेरी और कावेरी दक्षिण नदी पर तीन रेलवे पुल संख्या ७१५, ७१६ और ७१८ बनाने में लगभग ४० प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) काम के अप्रैल, १९६२ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

(ग) सारी योजना का अनुमानित व्यय ३३.७९ लाख रुपये है, जिस में श्रीरंगापटनम पर एक नये स्टेशन की इमारत बनाने का व्यय भी है।

नंजनगूड़, दक्षिण रेलवे के समीप रेलवे सड़क का पुल

†२६३. **श्री सिद्धय्याः** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में मैसूर-नंजनगूड विभाग में नंजनगूड के करीब रेल व सड़क का पुल बहुत पुराना है और १९६१–६२ की बाढ़ में पानी के नीचे डूब गया था;

(ख) क्या ऊंची सतह पर एक नया पुल बनाया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) वर्तमान पुल जो रेल और सड़क दोनों का है और उस में ५४'+८' की महराबें हैं और काफी पुराना है। यह १९६१–६२ में पानी में नहीं डूबा था किन्तु पानी का स्तर जुलाई १९६१ में महराबों के स्तर तक पहुंच गया था, जब कि सब गाड़ियां लाइन निरीक्षक द्वारा ले जाई गई थीं।

(ख) एक नया रेल का पुल बनाने का विचार है और यह काम दक्षिण रेलवे के १९६३–६४ के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा। मैसूर-ऊटाकमन्ड सड़क पर यातायात की भीड़ कम करने के लिए राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग ने सड़क का एक अलग पुल बनाने का निर्णय किया है।

मध्य प्रदेश में मध्यम सिंचाई योजनाएं

†२६४. **श्री वि० भू० देवः** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० और १९६०–६१ में मध्य प्रदेश को विशेषकर सरगुजा, माडल और रायगढ़ के लिए मध्यम सिंचाई कार्य योजनाओं के लिए अनुदानों और ऋणों के रूप में कितना रुपया दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**: मध्य प्रदेश सरकार को १९५९–६० और १९६०–६१ के वर्षों के लिए उसकी अनुमोदित विधि विकास योजनाओं के लिए जिसमें केवल रायगढ़ की 'केदार नाला' सिंचाई योजना सम्मिलित है, क्रमशः ५१६·२८ लाख रुपये और ७३६·६५ लाख रुपये दिये गये थे ।

मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनाएं

†२६५. **श्री वि० भू० देव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० और १९६०–६१ में सरगुजा, मांडला, और रायगढ़ के लिए मध्य प्रदेश को छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए अनुदानों और ऋणों के रूप में कितनी राशि दी गई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की संशोधित प्रक्रिया के अन्तर्गत, जो कि १९५८–५९ में शुरू की गई थी, विभिन्न राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 'कृषि' शीर्षक के अधीन योजनाओं के समूह के लिए दी जाती है, जिस में छोटी सिंचाई और भूमि विकास भी सम्मिलित है और अलग अलग योजनाओं के लिए नहीं । इसलिए १९५९–६० और १९६०–६१ में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि बतलाना संभव नहीं है । तथापि १९५९–६० और १९६०–६१ में कृषि विकास योजनाओं के लिए जिस में छोटी सिंचाई और भूमि विकास भी सम्मिलित है मध्य प्रदेश सरकार को दिये गये अनुदानों और ऋणों के बारे में जानकारी नीचे दी जाती है :—

वर्ष	अनुदान रुपये	ऋण रुपये
१९५९–६० .	४०·०३ लाख	२२४·४० लाख
१९६०–६१	३४·४३ लाख	२५७·७१ लाख

टेलीप्रिंटर

२६६. { **श्री म० ला० द्विवेदी**:
श्री सं० चं० सामन्त:
श्री बालकृष्णन्: }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड ने १९६१ के अन्त तक जो १७० टेलीप्रिंटर बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है उसके सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इनमें से कितने हिन्दी के और कितने अंग्रेजी के हैं ;

(ख) क्या कारण है कि हिन्दी टेलीप्रिंटर के निर्माण की दिशा में आशातीत प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ग) हिन्दी के टेलीप्रिंटर उचित मात्रा में बनाने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है और यह कब तक सफल हो सकेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड द्वारा बनाये गये सभी १७० टेलीप्रिंटर अंग्रेजी वर्णमाला में थे ;

(ख) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड १९६१ के उत्पादन कार्यक्रम में हिन्दी टेलीप्रिंटरों का निर्माण सम्मिलित नहीं किया गया था ; और

(ग) इटली के मेसर्स ग्रौलिवेत्ती के साथ किए गए करार के ग्रनुसार, जिनके सहयोग से हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर का कारखाना स्थापित किया गया है, भारत में अंग्रेजी टेलीप्रिंटरों के साथ साथ हिन्दी टेलीप्रिंटर भी बनाये जायेंगे। आशा की जाती है कि हिन्दी टेलीप्रिंटरों का वास्तविक निर्माण लगभग ३ वर्ष की अवधि में शुरू हो जाएगा जब कि उन पुरजों का उत्पादन होने लगेगा जो कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों टेलीप्रिंटरों के लिए एक से हैं।

बिहार में चीनी मिलें

†२६७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की चीनी मिलों ने सूखते हुए गन्ने के अतिरेक को न लाभ न हानि के आधार पर पेरना स्वीकार किया है, इस शर्त पर कि सरकार उन्हें उपकर तथा उत्पादन शुल्क में छूट दे और किसान लोग गन्ने का मूल्य चीनी की प्राप्ति के अनुसार लेने के लिए तैयार हों:

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार और किसान इस प्रस्ताव से सहमत हैं ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

गन्ने पर कर

२६८. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी उद्योग संघ की उत्तर प्रदेशीय शाखा ने भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से गन्ने पर उत्पादन कर तथा अन्य करों में छूट की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ;

(ग) उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग को निराशाजनक परिस्थिति से बचाने के लिये और क्या राहतें मांगी गई हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां। भारतीय चीनी मिल्स एसोसियेशन की पूर्वी उत्तर प्रदेश शाखा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानों को करों में छूट दिलाने के लिये अभ्यावेदन दिये हैं।

(ख) मामला विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) एसोसियेशन ने केन्द्रीय सरकार को दिये अपने अभ्यावेदन में अन्य किसी छूट की मांग नहीं की है ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली का चिड़ियाघर

†२६९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अप्रैल, १९६२ को दिल्ली चिड़ियाघर के अन्दर एक चीते ने एक कारीगर की लड़की को घायल कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा ; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या अतिरिक्त पूर्वोपाय किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** (क) लड़की को चीते ने नहीं एक शेरनी ने घायल किया था ।

(ख) १ अप्रैल, १९६२ को दर्शकों की एक बहुत बड़ी भीड़ शेरों के कमरे के पीछे को छोटी गली जो मुख्य अहाते को मिलाती है के चारों तरफ इकट्ठे हो गये थे, जहां कि शेर और शेरनी को रखा हुआ था, ताकि उनका कमरा साफ किया जा सके । दर्शकों को वहां नहीं जाना चाहिये । किन्तु कर्मचारियों के बार बार प्रार्थना करने पर भी दर्शक दोनों तरफ से इकट्ठे होते रहे । कुछ दर्शकों ने जो गली की दूसरी तरफ जमा हो गये थे, एक रंगीले रूमाल से जानवरों को छेड़ने की कोशिश की थी । शेरनी कपड़े को पकड़ने के लिये कूदी और साथ ही उसने उस लड़की को जो सलाखों के करीब खड़ी थी, बाईं गाल पर घायल कर दिया ।

(ग) खतरनाक जानवरों के पिंजरे और अहातों के गिर्द पाइप या लकड़ी की बाड़ लगाई जाती है, ताकि दर्शक बहुत करीब न आयें । हिन्दी और अंग्रेजी में चेतावनी बोर्ड लगाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त दो या इससे अधिक कर्मचारी अहातों पर नियुक्त किये जाते हैं । इस घटना के बाद बाड़ को और मजबूत कर दिया गया है ।

चीनी

†२७०. { **श्री श्रीनारायण दास:**
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री द्वा० ना० तिवारी:
श्री भागवत झा आजाद:
श्री र० चं० बरुआ:
श्री काशीनाथ पांडे : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चीनी के सम्बन्ध में उत्पादन, विक्रय, निर्यात, उपभोग और वर्तमान संग्रह की स्थिति क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां भारतीय चीनी की मंडियां बन सकी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: १९६१–६२ के मौसम में १ नवम्बर, १९६१ से १५ अप्रैल तक की अवधि में स्थिति इस प्रकार है :—

	आंकड़े लाख टनों में
१. चीनी का उत्पादन . . .	२२.६६
२. बेची गई तथा भेजी गई कुल चीनी की मात्रा .	१०.९६
३. निर्यात	०.८९
४. आन्तरिक खपत के लिए चीनी का प्रयोग . .	१०.३०
५. १५–८–६२ को मिलों के पास चीनी का संग्रह . .	२३.५३

भारत से चीनी का निर्यात अमेरिका, केनेडा, मलाया और मध्य पूर्व के देशों को किया गया है ।

भारत में अन्धे व्यक्ति

†२७१. **श्री रघूनाथ सिंह**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने अंधे व्यक्ति हैं और इनका विश्व की कुल अन्धी जनसंख्या से क्या अनुपात है है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: १९३१ से भारत में अन्धे व्यक्तियों की कोई गणना नहीं की गई है । तथापि अनुमान है कि १९४७ में भारत में अन्धों की संख्या २० लाख थी, जब कि विश्व में कुल १०० लाख अन्धे व्यक्ति हैं। अतः अनुपात १:५ है ।

अधिकृत प्राधिकारों का कहना है कि भारत में अन्धों की संख्या अब भी उतनी ही है अर्थात २० लाख। विभाजन से जो परिवर्तन हुआ था; वह जन संख्या में वृद्धि से पूरा हो गया है । भारत को ट्रेकोमा नियन्त्रण अग्रिम परियोजना सर्वेक्षण से पता चलता है कि आर्थिक रूप से अन्धे व्यक्तियों (जो २ मीटर से अधिक फासले पर ऊंगलियां नहीं गिन सकते) की संख्या ३९.६ लाख है ।

टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों की चोरी के मामले

†२७२. **श्री रघूनाथ सिंह**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९६२ से डाक तार विभाग द्वारा तार और टेलीफोन की तारों के चोरी के मामलों का पता लगाया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवनराम)** : जनवरी, फरवरी, और मार्च, १९६२ के महीनों में भारत में तार और टेलीफोन की तारों की चोरी के १७०६ मामले हुए थ । सब मामलों की सूचना पुलिस को दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाल वाले जहाजों द्वारा ले जाया गया सामान

†२७३. **श्री रघूनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में तटीय और विदेशी व्यापार के लिए पाल वाले जहाज़ों द्वारा कितना सामान ले जाया गया और उनकी सामान ले जाने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: भारतीय पाल वाले जहाजों ने तटीय और विदेशी व्यापार के लिए १९६०-६१ में क्रमशः १४ लाख टन और २ लाख टन माल पहुंचाया । १९६१–६२ के सम्बन्ध में आकड़े मई, १९६२ में मौसम की समाप्ति के बाद उपलब्ध होंगे ।

प्रश्न का दूसरा भाग स्पष्ट नहीं है । तथापि यह समझा जाता है कि माननीय सदस्य का निर्देश उन उपायों की ओर है, जो सरकार ने पाल वाले जहाज उद्योग के विकास के लिए उठाये हैं।

(१) नौवहन महा निदेशक के अधीन पाल वाले ज़हाजों की समस्या की पूर्ति के लिए एक अलग संघ बनाया गया है और जामनगर बम्बई, टूटीकोरिन और मसूलीपटनम् में इसके चार क्षेत्रीय दफ़्तर हैं । क्षेत्रीय अधिकारी जहाज नौवहन उद्योग तथा संबंधित व्यक्तियों से सम्पर्क करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त सामान प्राप्त करने में और बन्दरगाहों पर शीघ्र वापस आना सुनिश्चित करने में सहायता देते हैं।

(२) पाल वाले जहाज़ों के लिये चार क्षेत्रीय सलाहकार समिति यां और एक केन्द्रीय समिति बनाई गई है जिन में पाल वाले जहाज़ों के मालिकों टिंडल/मल्लाहों बन्दरगाह-अधिकारियों, विधान मंडलों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं । इन समितियों का काम सरकार को माल ढोने वाले जहाजों के विकास से सम्बन्धित सारे मामलों पर सलाह देना है । क्षेत्रीय सलाहकार समितियां माल ढोने वाले जहाजों के मालिकों के लिये स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करने का और जहाज़ों के चलाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर कराने का स्थान बन गई है ।

(३) जहाज़ मालिकों और अभिगोपकों में यह विश्वास पैदा करने के लिए कि माल लदान उद्योग पर माल ले जाने और सामान को अच्छी तरह और जल्दी पहुंचाने का विश्वास किया जा सकता है । केन्द्रीय सरकार ने वाणिज्य नौवहन अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत यह अधिकार ले लिये हैं कि वे कर्मचारियों और सुरक्षा की दृष्टि से जहाजों के समुद्रों में चलने के योग्य होने के अपेक्षित स्तर बनाया रखे। अपक्षेपण आदि जैसी बुराइयों को रोकने के लिये भी अधिकार लिये हैं ।

(४) पाल वाले जहाज़ यातायात के लिए बन्दरगाह की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।

(५) पाल वाले जहाजों के मालिकों को अपने जहाजों में सहायक इंजन लगाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि जहाज तेज चल सके और फलस्वरूप साल में अधिक चक्कर लगा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) पाल वाले जहाजों के मालिकों पर आधुनिक नमूने के नये जहाज बनाने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। अनेक व्यापारों में प्रयोग होने के लिए माल के जहाज़ों के निश्चित नमूने बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

नौवहन कम्पनियों को ऋण

†२७४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा या नौवहन विकास निधि में से भारत की विभिन्न नौवहन कम्पनियों को कुल कितना ऋण दिया गया है और इन कम्पनियों की अब तक प्रदत्त पूंजी क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]

दिल्ली से कोटद्वार तक एक्सप्रेस गाड़ी

२७५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीछे दिल्ली से कोटद्वार तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का विचार किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उस योजना को किसी कारणवश अन्त में रोक दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वह क्या कारण है ; और

(घ) क्या फिर दिल्ली से कोटद्वार का सीमा सम्बन्ध जोड़ने के लिये बिजनौर होते हुए एक एक्सप्रेस गाड़ी के चलाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ). गजरौला और बिजनौर के रास्ते दिल्ली और कोटद्वार के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने के लिए यात्रियों की ओर से प्रतिवेदन मिले हैं। इस सम्बन्ध में समय-साय पर विचार किया गया है लेकिन मख्यत निम्नलिखित कारणों से गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं समझा गया :—

(१) अपर्याप्त यातायात ;

(२) अतिरिक्त लाइन क्षमता का अभाव ; और

(३) परिचालन–सम्बन्धी दूसरी कठिनाइयां ।

कलकत्ता में भुमिगत रेलवे

†२७६. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में भमिगत रेलवे की संभाव्यता का परीक्षण करने के लिए कुछ विदेशी विशेषज्ञ बुलाये गये थे ;

(ख) क्या यह सरकार की अनुमति से किया गया था ; और

(ग) उनके निष्कर्ष क्या थे ?

†मूल अंग्रजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने एक फ्रांसीसी शिष्ट मंडल को इस संबंध में प्रारम्भिक जांच करने के लिये आमंत्रित किया था। उस ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने कहा है कि प्रस्ताव को अत्यधिक खर्च के अनुमान के कारण आगे नहीं बढ़ाया गया था। अब उस पर पुर्नविचार किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार को अभी राज्य सरकार ने इस विषय में नहीं लिखा। तथापि मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है।

बाढ़ के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय समिति

†२७७. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किन्हीं राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, नाली और पानी से डूबने से बचाने के सम्बन्ध में कोई व्यापक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने ; और

(ग) इन को पूरा करने के लिये कितनी राशि की जरूरत है ?

†**सिंचाई और विद्यूत् मंत्री (हाफ़िज मूहम्मद इब्राहीम)**: (क) और (ख). अभी तक तीन राज्यों अर्थात् जम्मू और काश्मीर पंजाब और उत्तर प्रदेश ने अपनी अपनी वृहत योजनाएं प्रस्तुत की है। जम्मू और काश्मीर और उत्तर प्रदेश की योजनाओं की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

चूंकि पंजाब की योजना समिति के सिफारिशों के आधार पर नहीं बनाई गई थी, यह परिवर्तन के लिए राज्य सरकार को वापस भेज दी गई है।

भूमि को डूबने से बचाने की कोई वृहत् योजना किसी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई ?

(ग) अपेक्षित राशि का अनुमान तब लग सकेगा जब वृहत् योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुकेगा और वह अनुमोदित हो जायेंगे।

केन्द्रीय भण्डागार निगम

†२७८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम के दिल्ली से बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महगाई भत्ता नहीं दिया रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस अनियमितता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) प्रधान कार्यालय द्वारा अखिल भारतीय आधार पर भर्ती किये गये केन्द्रीय भाण्डागार निगम के उन कर्मचारियों

†मूल अंग्रेजी में

को जो दिल्ली से बाहर काम कर रहे हैं, वेतन आयोग की सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर महंगाई और अन्य भत्ते दिये जा रहे हैं ।

प्रत्येक राज्य मे सेवा के लिये विशेष रूप से भर्त्ती किये जाने वाले अन्य कर्मचारियों को उनके समान अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही भत्ते मिलते हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

१९६१ में रेलवे दुर्घटनायें

२७९. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ मे, १९६० के मुकाबले बड़ी और छोटी रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या अधिक थी ;

(ख) यदि हां, तो १९६१ में छोटी और बड़ी दुर्घटनाओं की, पटरी से गाड़ी उतरने की दुर्घटनाओं सहित, कितनी संख्या थी ; और

(ग) १९६० में ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या कितनी थी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). वर्ष १९५९-६०, और १९६०-६१ मे भारतीय सरकारी रेलवेज पर होने वाली रेल दुर्घटनाओं (टक्करों, पटरी से उतरने, ट्रेनों में अग्निकांड और रेलवे फाटकों पर सड़क परिवहन से ट्रेनों की टक्करों) की संख्या क्रमशः २,०९६ और २,२२३ थी ।

रबी की फसल

२८०. **श्री बाल्मीकी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती मैमुना सुल्तान :
श्री बासप्पा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, रबी की फसल की क्या स्थिति है ;

(ख) सब से अच्छी स्थिति किस राज्य की है ;

(ग) प्राकृतिक प्रकोपों से राज्यवार, कितनी-कितनी हानि हुई ;

(घ) सब से अधिक हानि किस राज्य को पहुंची ;

(ङ) देश में खाद्य के स्टाक, संभरण और मांग की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(च) क्या इस फसल के कट जाने पर अमरीका से आयात घटा दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी मे

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० क० पाटिल): (क) से (घ). रबी फसलों के उत्पादन और पिछले साल की तुलना में उत्पादन में राज्यवार हानि या लाभ से सम्बन्धित जानकारी जून के अन्त तक उपलब्ध होने की आशा है, जबकि सारी फसलों के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमान तैयार हो जायेंगे । फिर भी आमतौर पर रबी फसलों की सम्भावनायें खासी अच्छी हैं ।

(ङ) व्यापारियों और किसानों के पास खाद्यान्नों की स्थिति के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन सरकार के पास खाद्यान्नों का बहुत बड़ा भंडार है और वह किसी भी स्थिति का सामना करने में समर्थ है। अच्छी फसल की सम्भावनाओं, भावों का चालू रुख, स्टाक की स्थिति तथा भारी आयात के कार्यक्रम को देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि देश में खाद्यान्नों के सम्भरण की स्थिति सन्तोषजनक रहेगी ।

(च) आयात के कार्यक्रम की समय समय पर समीक्षा होती रहती है। और आरक्षित भंडार बनाने के निश्चय तथा आवश्यकताओं के अनुसार उसमें संशोधन होता रहता है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अमेरिकी साधनों से गेहूं के आयात की निकट भविष्य में वर्तमान स्तर से नीचे जाने की कोई सम्भावना नहीं है ।

ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगाना

२८१. श्री बाल्मीकी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामों में बिजली पहुंचाने के लिये राज्यवार मार्च, १९६२ तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) राज्यवार कितने ग्रामों में बिजली लग गई है ; और

(ग) किन-किन राज्यों में अधिकतम संख्या में गांवों में बिजली लग गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम): (क) देहातों में बिजली लगाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को २.७२२९ करोड़ रुपए की रकम कर्ज के रूप में दी गई । उनको यह भी सिफारिश की गई कि देहाती इलाकों में लाइनें बनाने के लिए उस इलाके में मिलने वाले सस्ते सामान को ही काम में लाया जावे और निर्माण के ऐसे, कम खर्चीले तरीके अपनाएं जावें जिनसे कि काम बेखटके और चुस्ती से चलता रहे।

(ख) इनकी जानकारी नीचे दी जाती है :--

राज्य का नाम	३१-३-१९६१ तक जितने गांवों/कस्बों में बिजली लगी	१९६१-६२ के दौरान जितने गांवों/कस्बों में बिजली लगने का अनुमान है
१	२	३
आंध्र प्रदेश	२,१२५	*
आसाम	५५	*

१	२	३
बिहार	१,८५०	१९०
गुजरात . .	७३५	११०
केरल . . .	१,६७०	११५
मध्य प्रदेश . .	४२०	९६
मद्रास	६,०००	१,६००
महाराष्ट्र	६९०	*
मैसूर . . .	१,६५०	१२०
उड़ीसा . .	१४०	२५
पंजाब .	२,०३०	६००
राजस्थान	१४०	*
उत्तर प्रदेश .	४,५००	*
पश्चिमी बंगाल	४८०	१२
जम्मू और काश्मीर	*	४०
संघीय प्रदेश	३००	२०३

*अभी तक जानकारी नहीं आई ।

(ग) मद्रास, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, केरल, और मैसूर ।

पंचायतों में हरिजन प्रतिनिधि

२८२. **श्री बालमीकी : क्या सामुदायिक विकास, पंचायतीराज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचायती राज के अन्तर्गत पंचायतों में हरिजनों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है ; और

(ग) उस में क्या प्रगति हुई है ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जी नहीं । विभिन्न राज्यों की पंचायतों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन-जातियों (हरिजन नहीं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) के प्रतिनिधित्व की मौजूदा स्थिति को बताने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

(ख) व (ग). प्रश्न नहीं उठते । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४८]**

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में रेल के फाटकों पर ऊपरी पुल

२८३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पटेल रोड के रेलवे क्रासिंग पर तथा नई रोहतक रोड, नई दिल्ली के क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने के लिये एक योजना बना ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं । इन ऊपरी पुलों के लिए रेलवे को संबंधित सड़क-अधिकारियों की ओर से कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं मिलें हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मछुओं को सहायता

†२८४. { **श्री वारियर** :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मछुओं को सहायता के लिये नाइलोन धागे, और जाल बुनने की मशीनों और यंत्रीकृत नौकाओं जैसी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों को राशियों का कोई आवण्टन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) केरल, मद्रास, उड़ीसा, मैसूर, महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश, ने नाइलोन धागे, इत्यादि जैसी मछुओं के लिये अपेक्षित सामग्री और यंत्रीकृत नौकाओं में के संभरण की योजनायें अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित की हैं ।

(ख) और (ग) इन पांच राज्यों द्वारा वर्ष १९६२-६३ में व्यवस्थित राशियां इस प्रकार हैं :—

(१)	केरल	१७.७६ लाख रुपये
(२)	मद्रास	४.८७५ लाख रुपये
(३)	उड़ीसा	२.७५ लाख रुपये
(४)	मैसूर	४.६० लाख रुपये
(५)	गुजरात . . .	१२.२२ लाख रुपये

महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में सूचना संग्रह की जा रही है और तैयार होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सर्प-दंश की चिकित्सा के लिये केरल को अनुदान

†२८५. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सर्प-दंश की चिकित्सा को आयुर्वेदिक की एक विशेष शाखा के रूप में विकसित करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी अनुदान का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो अनुरोध कब किया गया था और कितनी राशि मांगी तथा कितनी स्वीकृत की गई थी ; और

(ग) केरल सरकार ने वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी, हां ।

(ख) फरवरी, १९५९ में केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध किया गया था और नेत्र, विष-वैद्य तथा मर्म चिकित्सा में विशषीकृत पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये कुल मिला कर ५६, ४१४ रुपये की राशि मांगी गई थी । उस पर ३०,००० रुपये की राशि विष-वैद्य तथा मर्म-चिकित्सा में विशेषीकृत पाठ्यक्रम चालू करने के लिये मंजूर की गई थी ।

(ग) राज्य सरकार ने योजना को कार्यान्वित नहीं किया ।

गोआ विलय की स्मृति में डाक-टिकट

२८६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के भारत विलय की स्मृति में एक विशेष डाक-टिकट प्रकाशित करने के सुझाव पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वह विशेष डाक-टिकट किस तारीख को प्रकाशित किया जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) यह डाक-टिकट दिसम्बर, १९६२ में जारी किया जाएगा । ठीक तारीख निश्चित करना अभी बाकी है ।

अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य की संस्था, बंगलौर

२८७. श्री भक्त दर्शन : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य की अखिल भारतीय संस्था को बंगलौर से रांची स्थानान्तरित करने के कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री डा० सुशीला नायर : इस मामले की स्थिति इस प्रकार है :—

जून, १९५४ में जब अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था को बंगलौर में स्थापित किया जा रहा था, मैसूर सरकार के साथ एक ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि इस संस्था का निदेशक मानसिक चिकित्सालय का पदेन चिकित्सा-अधीक्षक होगा। १९६० के शुरू में ही यह देखा गया कि मैसूर सरकार इस मानसिक चिकित्सालय के लिये एक पूर्णकालिक स्वतन्त्र चिकित्सा-अधीक्षक नियुक्त करना चाहती है। भारत सरकार का यह विचार था कि इस संस्था और अस्पताल के कुशल कार्य-संचालन के लिये ये दोनों संस्थायें एक ही व्यक्ति के अधीन काम करें। मैसूर सरकार से मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का अनुरोध किया गया था तथा उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि यदि राज्य सरकार इस मत से सहमत न हो सके तो भारत सरकार को विवश हो कर अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था को बंगलौर से किसी दूसरे उपयुक्त स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। किन्तु मैसूर सरकार ने ६ जनवरी, १९६१ को मानसिक चिकित्सालय बंगलौर के लिये एक पूर्णकालिक चिकित्सा-अधीक्षक नियुक्त कर दिया है। इस व्यवस्था को बदल कर पहली जैसी व्यवस्था करने के प्रश्न पर राज्य सरकार से बात चीत चल रही है। उन के अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

मछली पकड़ने के बन्दरगाह

†२८८. { **श्री अ० क० गोपालन:**
श्री प० कुन्हन : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक राज्य में मछलीमारी के कितने बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस कार्यक्रम में राज्यवार कितना प्रगति हुई ;

(ग) गत दो वर्षों में से प्रत्येक में मछलीमारी के बन्दरगाहों के निर्माण के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई ; और

(घ) उस में से कितनी राशि प्रयुक्त हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) से (घ). उड़ीसा, मैसूर, केरल और मद्रास राज्यों से सम्बन्धित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। शेष राज्यों से सम्बन्धित अपेक्षित जानकारी संग्रह की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९**]

बंगलौर नगर के लिये जल-संभरण

†२८९. **श्री अ० क० गोपालन:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने बंगलौर नगर के जल-संभरण में वृद्धि करने के लिये भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है,

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में मैसूर सरकार को कितनी राशि अदा करने की संभावना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):** (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी, १९६१ में बंगलौर नगर जल संभरण सुधार योजना (तीन मेन) के प्रथम क्रम का, जिस की अनुमित लागत ५० लाख रुपये है, अनुमोदन किया गया था। संविहित पद्धति के अनुसार, भारत सरकार ऋण के रूप में मैसूर सरकार को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था कर रही है।

(ग) राज्य सरकारों को १९६२–६३ में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के बटवारे के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है।

कावेरी नदी का जल

†२९०. **श्री उमानाथ** : क्या **सिंचाई और विद्यूत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने तिरुची जिले के पुदुक्कोट्टाई डिवीजन और पूर्वी रामनाथपुरम् की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये कावेरी नदी से जल लेने का कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्यूत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) :** (क) हमारे पास मद्रास सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता :

चीते के बच्चे

†२९१. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल द्वारा अमरीका के राष्ट्रपति की पत्नी, श्रीमती कैनेडी को भेंट किये चीते के बच्चे दिल्ली चिड़ियाघर में आने के चौबीस घंटे के अंदर ही मर गये थे;

(ख) उन की अचानक मृत्यु का क्या कारण था; और

(ग) क्या सरकार उन की मृत्यु की परिस्थितियों की कोई जांच करायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** (क) चिड़ियाघर में चीते के दो बच्चे २१ मार्च, १९६२ को साढ़े तीन बजे शाम को आये थे। उन में से एक तो छः घंटे के अन्दर ही मर गया था। दूसरा बच्चा २३ मार्च, १९६२ को १० बजे सुबह एस० पी० सी० ए० अस्पताल में मर गया था।

(ख) दोनों बच्चे आन्त्र ज्वर के कारण मरे थे, जो रोग उन को चिड़ियाघर में आने से पहले ही हो गयय था। इसलिये कि उन को जरूरत से ज्यादा खाना खिलाया गया था। और उन की पर्याप्त कसरत नहीं हो पाई थी।

(ग) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

छूत के रोगों का निवारण

†२६२. **श्री बासप्पा:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में अभी तक छूत के रोगों के निवारण के लिये मैत्रीपूर्ण सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा क्या सहायता मिली; और

(ख) अभी तक रोगों की रोक थाम किस सीमा तक हो पाई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):** (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संग्रह की जा रहीं है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बनसन्द्रा रेलवे स्टेशन

†२६३. **श्री बासप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि बंगलौर-पूना सैक्शन का बनसन्द्रा रेलवे स्टेशन इंजनों के पानी लेने का स्टेशन और एक जंक्शन है जो चार तालुकों के प्रधान कार्यालयों को संयोजित करता है इसलिये उसका विस्तार करना और उसमें सुधार करना और आवश्यक है; और

(ख) क्या स्टेशन तक जाने वाली सड़क का सुधार किया गया है और पहले दर्जे के यात्रियों का प्रतीक्षालय बन गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) बनसन्द्रा रेलवे स्टेशन इंजनों के पानी लेने का ही स्टेशन है , जंक्शन नहीं । उस के यातायात को देखते हुए वहां सुलभ सुविधायें सामान्यतया पर्याप्त मानी जाती हैं इसलिये उस के विस्तार या सुधार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, सिवाय इस के कि तीसरे दर्जे के यात्रियों के वर्तमान प्रतीक्षालय को बढ़ाया जा रहा है। इस का काम शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा ।

(ख) रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क का ठीक ढंग से संधारण हो रहा है और उस की दशा अच्छी है। उच्च श्रेणियों के मुसाफिर वहां इतने नहीं आते कि उन के लिये प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की जाये ।

कम्बाडोकोडा और हरन्गी परियोजनायें

†२६४. **श्री बासप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(अ) क्या कुर्ग में कम्बाडोकोडा और हरंगी परियोजनाओं के निर्माण के लिये कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या वे वैकल्पिक प्रस्ताव कम्बाडोकोडा और हरंगी परियोजनाओं से अधिक लाभदायक हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम):** (क) से (ग) कम्बाडोकोडा परियोजना के लिये कोई वैकल्पिक प्रस्ताव नहीं है ; हरंगी परियोजना के सम्बन्ध में एक वैकल्पिक प्रस्ताव है। यह कि हरदुर के पास हरंगी नदी पर एक बांध बनाने के बजाय उस की दोनों सहायक नदियों

---

†मूल अंग्रेजी में

पर दो पुल बनाये जायें। मैसूर सरकार के सामने यह वैकल्पिक प्रस्ताव आया है। यदि जांच-पड़ताल के बाद यह प्रस्ताव व्यावहारिक मालूम पड़ेगा तो काफी बागान की और भाधपुर गांवों की जमीनें पानी में नहीं डूबेंगी, और हट्टीहोल के पुल, मादापुरहोल और सोनवरपेटमैकारा रोड का कुछ भाग भी डूबने से बच जायेगा।

कश्मीरी सेव

†२९५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीरी सेव की किस्म और उस के उत्पादन में सुधार करने तथा अनुकूल जलवायु वाले अन्य हिमालय क्षेत्रों में व्यापक तौर पर उन को उगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के सरकारी फल गवेषणा केन्द्र, चौबत्तिया में संसार के अन्य प्रकार के कई सेवों के साथ कश्मीरी सेवों के भी उगाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में चूंकि सेवों में 'सान जोस स्केल' कीड़ा काफी बड़े पैमाने पर लग जाता है, इसलिये पौधों को कीट-रहित बना लेना जरूरी है। उस के बाद ही वे उत्तर प्रदेश में लाये और लगाये जाने चाहियें। १९५५ में कुछ थोड़े से पौधों को 'सान जोस' कीट से मुक्त कर लिया गया था। बाद में उन पौधों से और नये पौधे पैदा किये जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में कश्मीरी सेव के कुछ थोड़े से कीट-रहित पौधे (अम्बरी किस्म के) इस राज्य में इधर-उधर लगाये गये हैं। इस समय कश्मीरी सेवों की अन्य किस्मों पर परीक्षण चल रहे हैं, पर अभी उन का फल नहीं निकला है। कुमायूं की जलवायु में उन का अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन चूंकि अम्बरी किस्म के सेव अधिक लोकप्रिय हैं, इसलिये इसे विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया जा रहा है।

आसाम :

आसाम में कश्मीरी सेव के पौधे पनप नहीं पाते और उन के फल भी अच्छे नहीं होते। इसलिये वहां इस का कार्य शुरू नहीं किया गया है।

पश्चिमी बंगाल :

पश्चिमी बंगाल में कश्मीरी सेवों की खेती स्थायी तौर पर करने का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। दार्जिलिंग जिले में फलों की गवेषणा के लिये एक उप केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया जा चुका है। वही कश्मीरी सेवों को उगाने के परीक्षण किये जायेंगे। यदि वे सफल हुए तो अन्य स्थानों पर उन को उगाने की कोशिश की जायेगी।

पंजाब :

कश्मीर की कृषीय जल वायु हिमालय के अन्य सभी प्रदेशों से भिन्न है। कश्मीर में पैदा होने वाली किस्में अन्य प्रदेशों में उसी तरह नहीं रह पातीं। कुलू के उद्यानिकी गवेषणा केन्द्र में कश्मीरी सेव की अम्बरी किस्म कोई उपयोगी सिद्ध नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश :

हिमाचल प्रदेश में अभी तक कश्मीरी सेवों की अम्बरी किस्म के पौधे नहीं लगपाये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अम्बरी किस्म की कुछ अच्छी विशेषताओं, जैसे उस का अधिक दिनों तक न बिगड़ना देर से पकना, इत्यादि, का लाभ उठाने के लिये अन्य किस्मों के साथ प्रादेशिक फल-गवेषणा केन्द्र, माशोबा में सुलभ कुछ 'जायकेदार' किस्मों के साथ उस का अन्योन्यगमन कराया गया है और उस के बीजों से पौधे बनाये जा रहे हैं।

कलकत्ता से बम्बई के लिये बेल फल की बुकिंग

†२९६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से बम्बई के लिये बुक कराये जाने वाले बेल फल को अब रेलवे बुकिंग के लिये 'जल्द बिगड़ने वाली वस्तुओं' की श्रेणी में रख दिया गया है और उस का माल-भाड़ा चारगुना बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब इस फल को जल्द बिगड़ने वाला क्यों माना गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) बेल फल के माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस के लिये पार्सल की पूरी दर पर भाड़ा लिया जाता है। बेल फल को ताजे फल सब्जी की श्रेणी में नहीं रखा गया है जिन के लिये पार्सल की दरों में कुछ रियायत की जाती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली—फाजिल्का छोटी लाइन पर यात्री-डिब्बों में पंखों की व्यवस्था

†२९७. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और फाजिल्का के बीच छोटी लाइन पर चलने वाले तीसरे दर्जे के कितने यात्री-डिब्बों में अभी तक पंखे नहीं लगाये गये हैं; और

(ख) उनमें पंखे लगाने में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) पाच यात्री डिब्ब।

(ख) इन यात्री डिब्बों में पंखों की व्यवस्था का काम चल रहा है और अगले कुछ महीनों में पूरा हो जायेगा।

दिल्ली—फाजिल्का छोटी लाइन पर गाड़ियों में सोने की बर्थें

†२९८. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-फाजिल्का छोटी लाइन पर चलने वाली ट्रेनों में सोने के लिये कितनी बर्थों की व्यवस्था रहती है; और

(ख) तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में ऐसी कितनी बर्थों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) दिल्ली-फाजिल्का छोटी लाइन पर चलने वाले ट्रेनों के तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने के लिये बर्थों की व्यवस्था नहीं की जाती, क्योंकि अभाव के कारण, ऐसी बर्थों की व्यवस्था बड़ी और छोटी लाइनों पर क्रमशः ८०० किलोमीटर और ४५० किलोमीटर चलने वाली ट्रेनों तक ही सीमित रखी गई है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में आंत्रशोध के मामले

†२९९. { **श्री बी० चं० शर्मा:**
श्री महेश्वर नायक:

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चालू वर्ष में अब तक आंत्रशोध के कितने मामले हुए हैं;

(ख) उन में से कितने मामले घातक सिद्ध हुए; और

(ग) उनको दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):** (क) जनवरी, १९६२ से ११ अप्रैल १९६२ तक ८७ मामले हुए ।

(ख) तीन ।

(ग) इन्हें रोकने के लिये निम्न कार्यवाही की गयी ।

(१) सम्बन्धित क्षेत्रों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के ध्यान में लाये जाने पर, नगरपालिका की एम्बुलेंस से मामलों को तत्काल संक्रामक रोग अस्पताल दिल्ली में भेज दिया गया, जहां आंत्र-शोध के रोगियों को भर्ती करने की उचित व्यवस्था है।

(२) प्रभावित क्षेत्रों की पूरी तरह जांच की जाती है जिससे वहां किसी अन्य मामले का पता चल सके ।

(३) संक्रामक रोग अधिनियम, १८९७ को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विस्तृत किया गया।

(४) डाक्टरों के एक दल के द्वारा हैजा विरोधी टीके लगाने की व्यवस्था की गई है।

(५) हानिकारक खाद्यपदार्थों और पेयों की बिक्री को रोकने के लिये खाद्य स्वास्थ्य रक्षा क्रियान्वय दलों तथा स्वच्छता निरीक्षकों द्वारा कड़ी कार्यवाही ।

(६) संक्रामक क्षेत्रों में कृमिनाशकों के छिड़काव की आवश्यक व्यवस्था। मक्खी विरोधी तरीकों को पुरजोर अमल में लाया जा रहा है ।

(७) १ जुलाई, १९६२ से पिछले वर्ष की तरह मक्खी की सफाई सप्ताह मनाया जायेगा।

(८) नगरपालिका क्षेत्रों से सभी प्रकार के मल को तत्काल हटाने की व्यवस्था की गयी है।

(९) बीमारी रोकने के लिये पर्याप्त प्रचार कार्य की व्यवस्था की गई है ।

(१०) स्वच्छता की दृष्टि से नगरपालिका जल संभरण की कड़ी निगरानी रखी जाती है इसके लिये विभिन्न उपभोक्ता नाकों से पानी के नमूने लिये जाते हैं ।

(११) ग्रामीण क्षेत्रों के पीने के पानी में नियमित रूप से क्लोरीन डाला जाता है ।

(१२) नई दिल्ली नगरपालिका ने एक पृथक नगर स्वच्छता विभाग स्थापित किया है जो पाखानों और सफाई की देख रेख कर सके ।

सफदरजंग हवाई अड्डे से कुतुब मीनार तक का रास्ता

†३००. **श्री ई० मधुसूदनराव:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग से कुतुब मीनार तक के रास्ते को चौड़ा और सुन्दर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब से आरम्भ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). कुतुब रोड को चौड़ी करने की योजना दिल्ली नगर निगम की तीसरी परियोजना में शामिल है जिस पर अनुमानतः २ लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट कुतुब रोड को मोड़ने के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर यथा समय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद्

†३०१. **श्री राम हरख यादव:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष १९६१-६२ के दौरान किये गये कार्यों को बतलाने की कृपा करेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् के द्वारा १९६१-६२ में किये गये कार्यों को दिखलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५०।]

उद्यानों का विकास

†३०२. **श्री कर्णीसिंह जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के लिये राजस्थान को कुल कितनी सहायता राशि या अनुदान मंजूर किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: द्वितीय पंच वर्षीय योजना के क्षेत्र में उद्यानों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को अनुदान और ऋण के रूप में निम्नलिखित राशि प्रदान की गई है :

अनुदान	रु० १,१२,०००
ऋण	रु० १०,७२,०००

टेलीफोन

†३०३. **श्री कर्णीसिंह जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बीकानेर एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी के लिये बहुत सी अर्जियां पड़ी हुई हैं; और

(ख) यदि हां, इन सम्बन्धों को मंजूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, या की जाने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) प्रतीक्षा सूची में ८२ अर्जियां पड़ी हैं ।

(ख) बीकानेर एक्सचेंज में लाइनों की संख्या को ४८० से बढ़ा कर ६०० करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आशा है कार्य अक्टूबर १९६२ तक समाप्त हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्घटना की रोकथाम के लिये मशीन का आविष्कार

†३०४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय इंजीनियर ने एक ऐसी नयी मशीन का आविष्कार किया है जिससे रेलवे लाइन की खराबी से होने वाली दुर्घटनायें रोकी जा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे रेलवे दुर्घटनाओं का पता लगाने में कहां तक सफलता मिली है; और

(ग) सरकार उस मशीन का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

'सबसे अच्छे ग्राम सेवक' का चुनाव

३०५. श्री नवल प्रभाकर: क्या **सामुदायिक विकास, पंचायतीराज और सहकार** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में "सब से अच्छा" ग्राम सेवक छांटने के लिये कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस चयन का आधार क्या है ?

सामुदायिक विकास, पंचायतीराज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): (क) जी हां ।

(ख) चयन का आधार उत्पादन कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर कृषि, पशु-पालन, सिंचाई, सहकारिता और पंचायतीराज संस्थाओं को बढ़ावा देने में मिली सफलतायें हैं ।

प्रत्येक खण्ड पहले अपना एक "सब से अच्छा" ग्राम सेवक चुनता है और फिर उन में से सारे इलाके का "सब से अच्छा" ग्राम सेवक एक समिति द्वारा चुना जाता है ।

मोतीहारी के जिला न्यायालय के निकट हाल्ट स्टेशन

†३०६. श्री विभूति मिश्र : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोतीहारी (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट एक हाल्ट स्टेशन बनाने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि यात्री सुविधाओं के आधार पर प्रयोगिक रूप में ठेकेदार द्वारा संचालित ट्रेन हाल्ट बनाया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण

†३०७. **श्री अंजनप्पाः** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार दिल्ली नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये इस भयंकर खतरे को दूर करने के लिये क्या कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) विश्लेषण करने के उपरान्त अपमिश्रित पाये गये नमूनों के प्रतिशत में अभी हाल के महीनों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बीकानेर रेलवे स्टेशन में विश्राम और अल्पाहार गृह

†३०८. **श्री कर्णी सिंह जीः** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बीकानेर रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) में विश्राम और अल्पाहार गृहों के अभाव में यात्रा करने वाली जनता को बहुत असुविधाओं का सामना करना होता है ; और

(ख) सरकार इसे दूर करने के लिये क्या करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). अभी हाल तक बीकानेर रेलवे स्टेशन में विश्रामगृहों और अल्पाहार गृहों की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई थी । नगर के महत्व तथा वहां कई सरकारी कार्यालयों के स्थित होने और उचित होटलों के अभाव को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि उपयुक्त राशि उपलब्ध होने पर १९६३–६४ में ८ विश्रामगृहों और एक अल्पाहार गृह की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

दिल्ली में यातायात की दुर्घटनायें

†३०९. **श्री वाडीवाः** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में दिल्ली में यातायात की कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) उनमें से कितनी दुर्घटनायें दिल्ली परिवहन प्राधिकार से हुई ;

(ग) इस अवधि में कितने मामलों में प्रतिकर दिया गया ; और

(घ) कितने यातायात अपराधियों को दण्ड दिया गया ; और

(ङ) इस अवधि में यातायात नियन्त्रण में क्या सुधार हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क): ६,४४८ ।

(ख) १,४८२ ।

---

†मू म

(ग) ५३ ।

(घ) साइकिल वालों, टांगा और रेड़ी चालकों, आदि सहित १,५१,६८६ । वर्ष में यातायात प्रवर्तन और नियन्त्रण में सुधार करने के लिए निम्न कार्यवाही की गई :—

(१) ११ अधिक चलने वाली सड़कों के चौराहे पर बिजली के यातायात सिग्नलों को लगाना ।

(२) कुछ अधिक चलने वाली सड़कों पर धीरे चलने वाली और भारी गाड़ियों पर प्रतिबन्ध

(३) कुछ अधिक चलने वाली सड़कों पर 'यू' मोड़ लेने पर प्रतिबन्ध ।

(४) सुबह व शाम दफ्तर के समय अधिक चलने वाली महत्वपूर्ण सड़कों पर मोटर साइकिलों पर घूमने वाली पुलिस तैनात करना कि यातायात नियमों के उल्लंघन का पता लगाये और रुके यातायात को निकालने में सहायता देने के लिए नियुक्त करना ।

(५) अधिक रफ्तार से चलाने, खतरनाक ढंग से चलाने, नशे की हालत में चलाने और चलाने का लाइसेन्स बिना चलाने की विस्तृत जांच पड़ताल ।

(६) सड़क तथा सड़कों की हालतों को सुधारना, अर्थात्, दिखाई न देने वाले मोड़ों पर सड़क को चौड़ा और हमवार बनाना, रोशनी का अच्छा इन्तजाम करना, अधिक चलने वाली सड़कों पर भीड़ रोकना और पर्याप्त सड़क-चिह्नों की व्यवस्था करना ।

(७) यातायात पुलिस बढ़ाई गई और आयोजन तथा प्रवर्तन में सुधार करने की बात ध्यान में रख कर यातायात पुलिस को कुछ अधिकारी प्रशिक्षण के लिए बम्बई भेजे गये ।

दूसरी योजना में नई रेलवे लाइनें

†*३१०. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में राज्यवार कितने मील लम्बी नई रेलवे लाइनें बनाई गई हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : रेलवे के आंकड़े रेलवे पर होते हैं, राज्यवार नहीं । फिर भी, दूसरी योजनाकाल में रेलवे वार और विभिन्न राज्यों में आने वाली बनाई गई नई रेलवे लाइनें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५१**]

खण्डवा-दोहद रेलवे लाइन का निर्माण

†३११. **श्री बड़े** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सन् १९६१–६२ में नई रेलवे लाइनों का निर्माण कहां कहां करने की योजना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या मध्य प्रदेश के पश्चिम नीमाड़ में खंडवा से खरगोन व्हाया बड़वानी से दोहद तक रेलवे लाइन का निर्माण करने के सम्बन्ध में पश्चिम नीमाड़ से प्रतिनिधिमंडल लेकर कोई महानुभाव १९६० या १९६१ में तत्कालीन रेलवे मंत्री जी से मिले थे ;

(ग) क्या १९६२–६३ में मध्य प्रदेश में पश्चिम नीमाड़ अर्थात् खरगोन जिले में रेलवे लाइन का निर्माण करने की योजना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) यदि ऊपर के भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इसका सर्वे कब तक किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) (१) ५४ मील लम्बी बौरीडंड-करौंजी नयी लाइन सभी तरह के यातायात के लिए खोली जायेंगी । इसका १७ मील लम्बा बौरीडंड-बरबासपुर खण्ड फरवरी, १९६२ में माल यातायात के लिए खोल दिया गया ।

(२) १२ मील लम्बी करौंजी-जयनगर शाखा लाइन माल यातायात के लिए खोली जायेगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रस्ताव रेलवे की तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल नहीं है ।

(ङ) निकट भविष्य में इस लाइन के बनाये जाने की आशा बहुत कम है, इसलिए अभी उसके सर्वेक्षण का कार्यक्रम नहीं बनाया गया है ।

दिल्ली में गर्मी में बिजली संकट

†३१२. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री महेश्वर नायक: }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक ऐसे चिह्न मौजूद हैं कि गर्मी में राजधानी में भारी बिजली-संकट रहेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) से (ग). दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम की बिजली बनाने की वर्तमान क्षमता राजधानी की बिजली की आवश्यकता की भलिभान्ति पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त है । जून १९६२ में मिलने वाली भाखड़ा नंगल की २०,००० किलोवाट बिजली मिलने पर स्थिति सुधर जायेगी । यदि इस बिजली के मिलने में किसी कारण देर हुई, तो आवश्यक मात्रा में बिजली का संभरण कम करके मांग की पूर्ति की जायेगी ।

हिसार और सिरसा में रेलवे बुकिंग एजेंसियां

†३१३. **श्री बागड़ी**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिसार और सिरसा नगरों में रेलवे बुकिंग एजेन्सियां (टिकट घर) खोलने का है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). नहीं, क्योंकि इन स्थानों में नगर टिकट घर खोलना न तो वित्तीय आधार पर उचित है और न ही सार्वजनिक आवश्यकता के आधार पर क्योंकि स्टेशन पर पर्याप्त सुविधायें हैं ।

हिसार रेलवे स्टेशन के पास पुल

†३१४. **श्री बागड़ी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिसार रेलवे स्टेशन के पास जनता के लिए रेलवे पुल न बनाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख) रेलवे लाइनों पर ऊपरी नीचे का पुल का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिये । रेलवेज ऐसे कार्य वहां करती हैं जहां उनकी सिफारिश राज्य सरकारें करती हैं और नियमों के अनुसार लागत का अपने अंश का धन देती है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब सरकार ने हिसार में ऊपरी पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है ।

रोहतक-भिवानी रेलवे लाइन का निर्माण

†३१५. **श्री बागड़ी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार निकट भविष्य में रोहतक-भिवानी रेलवे लाइन बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार का विचार उक्त लाइन को कब बनाने का है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नई लाइनों के निर्माण के रेलवे प्रोग्राम में यह प्रस्ताव शामिल नहीं है । वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण पर विचार करने की संभावना नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

धनबाद नगर में यातायात की समस्यायें

†३१६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद में व्यक्तियों तथा गाड़ियों के आने जानेमें बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि रेलवे लाइनों के कारण नगर को तत्काल जाना रुक जाता है और काफी देर तक यातायात की भीड़ हो जाती है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इस महान सार्वजनिक असुविधा को दूर करने के लिए सरकार का विचार निकट भविष्य में कोई उन्नत टेकनीक लागू करने का है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) धनबाद के नया बाजार के रेलवे फाटक पर सड़क यातायात अनिवार्य रूप से कुछ देर के लिए रुक जाता है।

(ख) ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव स्वीकार हो गया है और बिहार सरकार ने यह योजना अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली है। मुख्य पुल रेलवे बनायेगी और पुल तक जाने वाली ढलवां सड़कें राज्य सरकार बनायेगी। जहां तक कार्य में रेलवे के भाग का सम्बन्ध है, १९६२–६३ के निर्माण प्रोग्राम में राज्य सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है।

डाक तथा तार विभाग की प्रतियोगिता परीक्षायें

३१७. **श्री सरजू पाण्डेय:**
श्री ज० ब० सिंह बिष्ट :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग की प्रतियोगिता परीक्षार्थियों से अंग्रेजी में प्रश्नों के उत्तर मांगे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां।

(ख) विभाग का काम अंग्रेजी में होता है। अतः परीक्षार्थियों को इस योग्य होना चाहिए कि वे अपने विचार अंग्रेजी में व्यक्त कर सकें।

पोचमपाद और श्री सैलम परियोजनायें

†३१८. **श्री ई० मधुसूदन राव :**
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री वेंकटा सुब्बया :
श्रीमती यशोदा रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में पोचमपाद और श्री सैलम परियोजनाओं की स्वीकृति की घोषणा शीघ्र हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) इन परियोजनाओं की स्वीकृति की घोषणा करने का प्रश्न योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा टेक्निकल पहलू से स्वीकार किये जाने के बाद पैदा होता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मनीपुर द्वारा चावल का समाहार

†३१९. **श्री रिशांग किशिंग: क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन के राज्य व्यापार निगम ने आन्ध्र का कितना चावल प्राप्त किया है ;

(ख) परिवहन भार सहित यह चावल कितने रुपये प्रति मन खरीदा गया ;

(ग) आन्ध्र का कितना चावल नीलाम किया गया और कितने रुपये प्रति मन नीलाम किया गया ;

(घ) क्या यह पता लगा है कि आन्ध्र के चावल के स्थान पर स्थानीय (मनीपुर) चावल निर्यात किया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो निर्यातकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) मनीपुर प्रशासन ने प्रत्यक्ष रूप से आन्ध्र का चावल प्राप्त नहीं किया। फिर भी ५,४४२ मन आन्ध्र का चावल १९६०–६१ में राज्य क्षेत्र में वितरण के लिये अन्य चावल के साथ केन्द्रीय स्टाक से दिया गया।

(ख) केन्द्रीय स्टाक से दिये गये चावल का मूल्य १६ रु० प्रति मन, मनीपुर रोड रेलवे स्टेशन तक निःशुल्क था। सड़क भाड़ा और अन्य आकस्मिक व्यय को मिलाकर मनीपुर प्रशासन के गोदाम पर इसका मूल्य १९ रु० प्रति मन लगाया था।

(ग) ३,४०० मन आन्ध्र का चावल बिना बिका पड़ा था और वह खराब होने वाला था। अतः १९६१ में दो राशियों में नीलाम किया गया। एक राशि ८ रु० मन और दूसरी राशि ७.५५ रु० मन बेची गई।

(घ) और (ङ) ६०० मन चावल, जो आन्ध्र का न था, आन्ध्र के चावल के निर्यात के लिये दिये गये पर्मिटों के अन्तर्गत निर्यात किया गया पकड़ा गया। राशि अधिकार में ले ली गई और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे अधिकारियों को पेशगी वेतन-वृद्धि

†३२०. **श्री प्रिय गुप्त : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अधिकारियों को तीन पेशगी वेतन-वृद्धियां दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में दी गई हैं ; और

(ग) तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इस लाभ से क्यों वंचित रखा गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की स्थापना के कारण नई रेलवे में अन्य रेलों के कुछ चुने हुए गजेटेड अधिकारियों का नियुक्त करना आवश्यक हो गया था और वे यह नहीं समझते थे कि उनकी सेवा की जिम्मेदारी विशेषकर वर्तमान पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की सीमा तक ही रहेगी।

(ग) गैर गजेटेड कर्मचारी अब भी केवल समूचे आसाम में सेवा करते हैं। उन्हें प्रतिकरक और बुरा मौसम भत्ता मिलता है। अतः उन्हें यह लाभ नहीं दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगाई गांव (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के इंजीनियरिंग कारखाने में सामयिक श्रमिक

†३२१. **श्री प्रिय गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले रेलवे कारखानों मे सामयिक श्रमिकों को काम पर रखा जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ;

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में बंगाई गांव के रेलवे कारखाने में कई सालों से लगातार सामयिक श्रमिक क्यों रखे जाते हैं और उन्हें वेतन-क्रम में (सी० पी० सी०/ए० एस०) जो कि सामयिक श्रमिकों को दिया जाता है, क्यों नहीं रखा गया है ;

(घ) उनमें से अधिकतर, जो सालों से काम कर रहे हैं, स्थायी क्यों नहीं किये जा सके जब कि नियमित पदाली में रिक्त स्थान हैं ;

(ङ) इन सामयिक श्रमिकों के वेतन की दर क्या है ; और

(च) रेलवेवार, विभागवार, श्रेणीवार सामयिक श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है जो कई साल से सेवा में हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) हां।

(ख) ऐसी कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं जिनके अन्तर्गत रेलवे कारखानों में सामयिक श्रमिक रखे जा सकते हैं।

(ग) से (च). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

दार्जिलिंग में कर्मचारियों को शीतकालीन भत्ता

†३२२. **श्री प्रिय गुत :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग जिले की पहाड़ियों में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को शीतकालीन भत्ता स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां रेलवे कर्मचारियों और अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को शीतकालीन भत्ता देने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की खबर भारत सरकार को पिछले दिनों ही लगी है। वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस मामले पर उचित विचार किया जायेगा।

सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचे हुए रेलवे अधिकारी[1]

†३२३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष १५०० रु० से अधिक पाने वाले कितने रेलवे अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Superannuated Railway Officers.

(ख) रेलों ने कितनों को सेवा वृद्धि दी, कितनों को पुनः काम पर रखा, कितने सरकारी उद्योगों में और कितने गैर-सरकारी उद्योगों में पुनः नियुक्त किया गया ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) :

	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
(क)	३३	२९	३४
(ख) सेवा-वृद्धि की गई	१४	१३	१४
रेलवे ने पुनः रखे	१	१	..
सरकारी क्षेत्र में पुनः नियुक्त	५	९	६
गैर-सरकारी क्षेत्र में पुनः नियुक्त	३	३	३

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खंडवा और अजमेर के बीच सवारी गाड़ियों की रफ्तार

†३२४. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खण्डवा और अजमेर के बीच सवारी गाड़ियां किस रफ्तार पर चलती हैं;

(ख) १९०८, १९२४, १९४० और १९६० में इन गाड़ियों की रफ्तार क्या थी; और

(ग) इन गाड़ियों को चलाने के लिये जिन इंजनों का प्रयोग किया जाता है उनकी गति की क्षमता कितनी होती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). खंडवा-अजमेर सैक्शन पर, तेज सवारी गाड़ियों की वर्तमान निर्धारित गति प्रति घंटा १० से ३६ मील तक भिन्न भिन्न है और सवारी गाड़ियों की १० से २७ मील प्रति घंटा जब कि अधिकतम अनुज्ञेय गति प्रति घंटा १० से ४० मील है । १९६० में इन गाड़ियों को इसी रफ्तार पर बुक किया गया । इन गाड़ियों की १९०८, १९२४ और १९४० में क्या रफ्तार थी यह मालूम नहीं ।

(ग) वाई० पी० श्रेणी के इंजन खंडवा और अजमेर के बीच सवारी गाड़ियां चलाते हैं । ये इंजन निश्चित भार के अन्दर प्रति घंटा अधिक से अधिक प्राधिकृत ४० मील ट्रैक स्पीड पर गाड़ियां चला सकते हैं ।

गुजरात में नल कूप

†३२५. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में प्रयोगात्मक नलकूप खोदे गये थे;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने नलकूप जिलावार खोदे गये हैं या जो खोदे जा रहे हैं;

(ग) खोदे गये कितने नलकूप सफल रहे हैं;

(घ) असफल नलकूपों का क्या हुआ है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या नालियों की लागत लेकर राज्य सरकारों या दिलचस्पी वाले किसानों को असफल नलकप देने का सरकार का कोई विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सूचना नीचे दी जाती है :

जिला	खोदे गये सुराख	सफल सुराक	खोवे जा रहे सुराख
१. जामनगर . .	१०	—	—
२. जूनागढ़ . .	८	—	—
३. भावनगर . .	५	—	—
४. मध्य सौराष्ट्र . .	१	१	—
५. अहमदाबाद . .	४	—	—
६. झालावाड़/सुरिन्द्रनगर .	१३	२	—
७. मेहसाना . .	१०	४	४
८. बानसकंथा . .	१२	६	—
९. कच्छ . .	२२	८	—
योग . .	८५	२१	४

(घ) और (ङ). राज्य सरकारों को रियायती दामों पर जो (१) निश्चित लागत से विभागीय शुल्क निकाल कर या (२) नालियों की लागत मात्र में से उन को निकालने की लागत जो इस बात पर निर्भर होगा कि क्या वे १५,००० गैलन प्रति घंटा से कम पानी निकालते हैं या अधिक, आधारित होगी, विकल्प किया गया है। यदि वे पेशकश स्वीकार नहीं करते, तो नालियां निकाल ली जायेंगी और नलकूप छोड़ दिये जायेंगे। दिलचस्पी वाले किसानों को सीधे बेचना उचित नहीं समझा गया क्योंकि स्थान केन्द्रीय सरकार के नहीं हैं।

बीजापुर लोकल ट्रेन में जंजीर का खेंचा जाना

†३२६. **श्री पु० र० पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ मार्च, १९६२ को दूधियों ने बीजापुर लोकल ट्रेन को कालोल और सैज-शेरथा ोड स्टेशनों के बीच खतरे की जंजीर खेंच कर रोक लिया और यात्रियों पर पत्थर फेंके;

(ख) कितने यात्री घायल हुए थे;

(ग) क्या जंजीर खेंचने या यात्रियों पर पत्थर मारने के लिये किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाया गया है;

(घ) गाड़ी के गार्ड और गाड़ी की पुलिस ने यात्रियों का क्या बचाव किया; और

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या यह सही है कि दूधिये रेलवे भाड़ा दिये बिना बहुत से दूध के बर्तन ले जाते हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ऐसी किसी घटना के होने की सूचना नहीं मिली।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होते।

(ङ) जी नहीं।

केरल में मानसिक स्वास्थ्य

†**३२८. श्री प० कुन्हन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में केरल के लिये मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी किन योजनाओं का प्रस्ताव है;

(ख) केरल में तीसरी योजना में मानसिक स्वास्थ्य पर कुल कितना वित्तीय व्यय है;

(ग) केरल में इस समय मानसिक स्वास्थ्य के रोगियों के लिये कितने पलंग हैं; और

(घ) मानसिक रोगियों के कितने अनुमानित मामलों को हस्पताल में भरती करने की जरूरत है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) केरल की सरकार का, तीसरी योजना के अन्दर मानसिक अस्पतालों और मानसिक सेवाओं को उन्नत करने की योजना के अधीन तीन मानसिक अस्पतालों को उन्नत करने का विचार है।

(ख) तीसरी योजना में उपरोक्त योजना के लिये कुल वित्तीय प्रावंटन २० लाख रुपये का है।

(ग) ७२२।

(घ) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी तक मानसिक रोगों का सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया है।

केरल में कोढ़

†**३२९. श्री प० कुन्हन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना में कोढ़ को रोकने के लिये केरल की राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ने अब तक कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) तीसरी योजना में कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना के ऊपर केरल द्वारा ३० लाख रुपये व्यय करने का विचार है। तीसरी योजना के पहले वर्ष के अन्दर राज्य ने केवल २.९७ लाख रुपये के व्यय की प्रत्याशा की थी। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को विभिन्न वर्गों की योजनाओं के लिये इकट्ठी की जाती है, अर्थात् केन्द्र द्वारा पोषित योजनाएं और केन्द्र की

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायता द्वारा चलने वाली योजनाएं, न कि निजी योजनाएं। १९६१–६२ में नकदी और जिनस दोनों में ७२ लाख रुपये का कुल अनुदान केरल सरकार के लिये केन्द्र की सहायता वाली सभी योजनाओं के लिये दिया गया था, जिन में कुष्ठ ोग नियंत्रण की योजना भी शामिल है।

त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल स्टेशन

†३३०. **श्री प० कुन्हन : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम मध्य स्टेशन को उन्नत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). जी हां। त्रिवेन्द्रम मध्य स्टेशन पर जल संभरण व्यवस्था को सुधारने के लिये १,४२,३३९ रुपये की राशि का अनुमान मंजूर किया गया है।

रेलवे प्रशासन भी निम्न सुविधाएं देने का विचार कर रहा है :

(१) अतिरिक्त माल शैड

(२) पार्सल आफिस के लिये अतिरिक्त स्थान

(३) वर्तमान प्लेटफार्म के ऊपर शैड का विस्तार करना।

केरल में समुद्र कटाव रोक कार्य

†३३१. **श्री प० कुन्हन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तीसरी योजना अवधि में समुद्र कटाव रोक कार्यों के लिये अपनी समूची योजना पेश कर दी है;

(ख) उन्होंने कुल कितनी राशि मांगी है;

(ग) क्या भारत सरकार ने उन योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है;

(घ) उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) तीसरी योजना में कितनी राशि नियत की गई है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम) :** (क) जी नहीं।

(ख) ६०० लाख रुपये।

(ग) अभी तक राज्य सरकार से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

(ङ) ३६० लाख रुपये।

उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधाएं

†३३२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस ग्रीष्म ऋतु में उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधाएं बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). इस ग्रीष्म ऋतु में सभी स्टेशनों पर पीने के जल का संभरण करने के लिये कदम उठाये गये हैं। स्टेशनों पर अतिरिक्त स्थायी वाटरमैन रखे गये हैं और गाड़ियों में साथ चलने वाले वाटरमैनों की व्यवस्था की गई है। अधिक मटके और पानी की रेहड़ियां दी जा रही हैं। इस रेलवे की १८३९ वाटरमैनों की स्थायी संख्या में ग्रीष्म काल में १७४४ अधिक अस्थायी वाटरमैन जोड़ दिये गये हैं।

स्मृति टिकट

†३३३. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु देव के मान में विशेष डाक टिकट जारी करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने इस मामले में क्या फैसला किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां।

(ख) भारत के समाज सुधारकों के लिये विशेष टिकट निकालने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ रख लिया गया है। तथापि उन टिकटों के निकालने में कुछ समय लगेगा।

पंजाब को कोयले की ढुलाई

†३३४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब को कोयले की ढुलाई के लिये माल डिब्बों की कमी को ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : पंजाब को कोयले की ढुलाई, उस राज्य के लिये कोयला नियंत्रक द्वारा किये गये आवंटन के आधार पर बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से मुगलसराय के ऊपर की दिशा में होती है। पंजाब के लिये पृथक ढुलाई का कोई अभ्यंश निर्धारित नहीं है। सामान्य तौर पर कोयले की ढुलाई को बढ़ाने के लिये अपेक्षित इंजन डिब्बों आदि को बढ़ाने के अतिरिक्त, मुगलसराय तक ग्रांड कोर्ड के विद्युतीकरण के अलावा, मुगलसराय के उपर दिशा में लक्ष्य स्थानों तक कोयले की ढुलाई को अग्रतर बढ़ाने के लिये निम्न उपाय किये जा रहे हैं :—

(१) माल यातायात के लिये मुगलसराय-सहारनपुर सैक्शन पर डीज़ल गाड़ियों का चलाया जाना ;

(२) तीसरी योजना में मुगलसराय-कानपुर सैक्शन का विद्युतीकरण;

(३) गाजियाबाद-टूंडला, मुरादाबाद-सहारनपुर और कानपुर-इलाहाबाद सैक्शनों को पूर्णतया दोहरा बनाना।

नंगल बांध को पोंग बांध से मिलाने वाली रेलवे लाइन

†३३५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल बांध को पोंग बांध से मिलाने के लिये एक नई रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

बेलनगंज (आगरा) माल स्टेशन से माल का बुकिंग

†३३६. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में बेलनगंज (आगरा) माल स्टेशन से बाहर के स्टेशनों को माल का बुकिंग कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ के आंकड़े क्या हैं;

(ग) कमी के कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या अन्य स्टेशनों पर उपलब्ध होने वाली निम्न सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं हैं :

(१) दक्षिण रेलवे के स्टेशनों पर मीटर गेज द्वारा सीधी बुकिंग जैसा कि हाथरस और अचनेरा से किया जाता है;

(२) (बेलनगंज के बजाए) मिधाकूर और किरौली के 'वे साइड स्टेशनों' से पश्चिम रेलवे के लक्ष्य स्थानों के लिये माल डिब्बों का तैयार मिलना; और

(३) आसाम के व्यापार आयुक्त द्वारा हाथरस और कानपुर से (आगरा से नहीं) प्राथमिकता दिया जाना ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (घ). सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है । यह रेलवे से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे बोर्ड के अधीन 'विजिलेंस इन्स्पेक्टरों' का स्थानान्तरण

†३३७. **श्री फ० गो० सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के अधीन सभी 'विजिलेंस इन्सपेक्टरों' को उनके मूल पदों पर स्थानान्तरित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी, नहीं । जिन कर्मचारियों ने 'इन्वेस्टिगेटिंग इन्स्पेक्टर' के रूप में ३ वर्ष से अधिक की सेवा की है, उनके मामलों पर समय समय पर विचार किया जाता है और जहां आवश्यक समझा जाता है, उनको बदल दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चिनाब नदी में बिजली की संभाव्यता का सर्वेक्षण

†३३८. { श्री श्याम लाल सर्राफ :
बख्शी अबदुल रशीद :
श्री अब्दुल गनी गोनी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिनाब नदी में सलाल और ध्यानगढ़ में बिजली की संभाव्यता का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों का विदोहन करने के लिये इस क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने के लिये सरकार और क्या कदम उठायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम) :** (क) और (ख). अभी सर्वेक्षण और जांच-कार्य पूरे नहीं हुए हैं। विस्तृत रूप से जांच पूरी होने पर योजना के क्रियान्वयन के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

लखनऊ की आलम बाग वर्कशाप के भीतर पार्क

३३९. { श्री सरजू पाण्डेय :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या रेलवे मंत्री २१ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आलम बाग में जिस पार्क का निर्माण होने वाला था उसमें इस बीच क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त बाग के लिए धन उपलब्ध कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके बनने में कितना समय लगेगा और कितनी धन राशि खर्च होगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) २९-११-६१ को अतारांकित प्रश्न सं० ८५१ के उत्तर में यह बताया गया था कि १९६१-६२ में आलमबाग, लखनऊ की रेलवे कालोनी (न कि रेल कारखाने) में एक पार्क बनाने का प्रस्ताव है। माननीय सदस्य का मतलब शायद आलमबाग, लखनऊ की रेलवे कालोनी के अन्दर वाले पार्क से है।

(ख) और (ग). काम हो रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक उसके पूरा हो जाने की आशा है। पार्क बनाने पर लगभग ५,००० रुपये खर्च का अनुमान है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रंक टेलीफोनों में खराबी

†*३४०. { श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विभिन्न स्थानों और विशेषत: कलकत्ता-दिल्ली, कलकत्ता-बम्बई, कलकत्ता-पटना, और कलकत्ता-गोहाटी लाइनों पर ट्रंक टेलीफोनों के लगातार खराब हो जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस खराबी के क्या कारण हैं; और

(ग) उस को सुधारने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, हां ।

(ख) खराबी भारी वर्षा, तूफान, बाढ़ और अन्य कारणों से लाइन में बाधा पड़ने और बड़े पैमाने पर तांबे के तारों की चोरी हो जाने से होती है ।

(ग) कई उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं, जैसे

(१) प्रमुख ट्रंक मार्गों पर ऊपरी लाइन सर्किट को भूमिगत केबिल में बदलना;

(२) तांबे के तारों की चोरी के मामलों को (क) चोरी के मामलों में राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ सरगर्मी से जांच पड़ताल करके और (ख) चोरी हुए क्षेत्रों में तांबे के तारों के स्थान पर तांबे के वेल्ड तार लगा कर, कम करना ।

'चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति समिति' की सिफारिशें

†३४१. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति समिति" की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का पालन किया जा रहा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे बोर्ड ने सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये रेलवे प्रशासन को आदेश जारी किये हैं । इन आदेशों के क्रियात्मक रूप में क्रियान्वयन को देखने के लिये रेलवे में एक विशेष व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) अभ्यावेदनों पर विचार किया जाता है और आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय काजू तथा मसाला समिति

†३४२. श्री मणियंगाडन: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "केन्द्रीय काजू तथा मसाला समिति" नामक एक समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या इसके गठन के बाद से समिति की कोई बैठक हुई है;

(घ) यदि हां, तो कितनी बार; और

(ङ) यदि समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल: (क) और (ख). जी, हां। भारत सरकार द्वारा भारतीय केन्द्रीय मसाला और काजू समिति के गठन को ७ सितम्बर, १९६१ को एक संकल्प द्वारा अनुमति दी गयी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) समिति बनाने के लिये ७ सितम्बर, १९६१ के संकल्प के उपबन्धों के अनुसार समिति के सदस्यों की नियुक्ति का कार्य राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से हाल ही में पूरा किया गया है। समिति की पहली बैठक हाल ही में की जायेगी।

नदी परियोजनाओं की सिंचाई और विद्युत् क्षमता

†३४३ श्री महेश्वर नायक: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा और केन्द्रीय सरकार के कहने पर बनायी गयी नदी परियोजनाओं की सिंचाई और विद्युत् क्षमता का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) क्या उनका पूरा उपयोग किया गया है; और

(ग) तृतीय योजना काल के अन्त तक कितनी अतिरिक्त बिजली पदा की जावेगी ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के आयोजन और क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। बड़ी सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें प्रावस्थानुसार लाभ देती हैं। सिंचाई और विद्युत् के लिये शक्ति के बनाये जाने और उपयोग का व्योरा निम्न प्रकार है :

सिंचाई

योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा मूल्यांकन के अनुसार दूसरी योजना के अन्त में कुल क्षमता १२२.४ लाख एकड़ और ८६.८ लाख एकड़ के कुल सिंचाई के क्षेत्र की थी। तीसरी योजना के दौरान सभी योजना परियोजनाओं से १६२ लाख एकड़ की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता होने की आशा है और तृतीय योजना में १२८ लाख एकड़ की सिंचाई की जायेगी जिससे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं में कुल मिला कर २१४.८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

†मूल अंग्रेजी में

विद्युत्

दूसरी योजना के अन्त तक देश में कुल निर्धारित जल-विद्युत् उत्पादन क्षमता १८.५ लाख किलोवाट थी। इस समूची बिजली का उपयोग किया जा रहा है।

दूसरी योजना के अन्त तक देश में कुल निर्धारित उत्पादन क्षमता ५७ लाख किलोवाट थी जिसमें १६ लाख किलोवाट जल-विद्युत् संयंत्र से और बाकी तापीय संयंत्र से थी। तृतीय योजना के अन्त में निर्धारित क्षमता को १३० लाख किलोवाट आंका गया है जिसमें से लगभग ५० लाख जल-विद्युत् संयंत्र से और बाकी तापीय संयंत्र से प्राप्त होगी।

उड़ीसा में विकास खंड

†३४४. **श्री महेश्वर नायक :** क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में अब तक कुल कितने विकास खंड चालू किये गये;

(ख) समूचे राज्य में यह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी;

(ग) क्या खंड के कार्यकरण के दौरान की अवधि में खंड क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार का कोई पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :** (क) २५६।

(ख) समूचे राज्य के लिये अक्तूबर, १९६२ तक पूर्व-विस्तृत खंड आवंटित कर दिये जायेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खेतरी-चिरावा रेलवे लाइन

†३४५. **श्री मुरारका :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतरी-चिरावा रेलवे लाइन के बारे में अभी तक क्या प्रगति की गयी है; और

(ख) वास्तविक-कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) लोहारू-सीकर लाइन पर खेतरी को चिरावा से मिलाने के लिये प्रावेक्षण इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है और परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं। रिवाड़ी-रीनगस लाइन पर खेतरी को डाबला अथवा निजामपुर से मिलाने के लिये एक वैकल्पिक लाइन के लिये भी सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी लाइन अधिक उपयुक्त और सस्ती पड़ेगी।

(ख) इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है कि खेतरी से चिरावा तक अथवा खेतरी से डाबला तक लाइन बनाने का काम कब से आरम्भ किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

नजफगढ़ और नरेला के बीच सीधी टेलीफोन लाइन

३४६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहली के नजफ़गढ़ एवं नरेला में सीधा टेलीफोन संबंध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सीधा संबंध कब तक सम्भव हो सकेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। नरेला एक सीधे परिपथ द्वारा दिल्ली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और नजफ़गढ़ दिल्ली क्षेत्र का ही एक भाग है।

चेचक के टीके

३४७. **श्री बाल कृष्ण बासनिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि बड़े पैमाने पर चेचक के टीके लगाने से इस रोग की अपेक्षा अधिक मृत्यु हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तथ्यों का पता लगाया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खुर्जा के सहकारी घी विक्रेता

†३४८. **श्री हेम बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खुर्जा के सहकारी घी विक्रेता संघ ने पिछली जनवरी में सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विक्रेता संघ की मांगें क्या थीं ; और

(ग) मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (ग). खुर्जा के सहकारी घी विक्रेता संघ ने अभ्यावेदन किया कि खुर्जा क्षेत्र में दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में दूध ले लिये जाने के कारण उस क्षेत्र में घी के कुटीर उद्योग पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है। संघ को सूचित कर दिया गया कि यह ठीक नहीं है क्यों कि उस क्षेत्र में दूध के निजी क्रेताओं की अपेक्षा योजना को कोई विशेष सुविधायें प्राप्त नहीं हैं।

कम्बडोकोडा और हरंगी बांध परियोजनायें

†३४९. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री प० कुन्हन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य मे कुर्ग में कम्बडोकोडा और हरंगी उच्च बांध परियोजनाओं के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम):** (क) और (ख). मैसूर सरकार ने अभी यह निर्णय नहीं किया है कि वे तृतीय योजना में इन दोनों में से कौन सी योजना आरम्भ करेंगे ।

विंझिजाम फिशिंग हार्बर

†३५०. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में विंझिजाम मछली पकड़ने का बन्दरगाह बनाने के लिये अतिरिक्त धन आवंटित करने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की आवश्यकता है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) और (ख). केरल की तृतीय पंचवर्षीय योजना में विंझिजाम समेत मछली पकड़ने के छ : बन्दरगाहों के विकास के लिये १०० लाख रुपये की व्यवस्था की है । इस कार्य के लिये किसी अतिरिक्त आवंटन के लिये केरल सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ?

ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल–एवं–सड़क पुल

†३५१. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमीनगांव और पांडु के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल-एवं-सड़क पुल बनाने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस पुल पर यातायात कब से आरम्भ हो जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** नींव रखने और पुल के स्तम्भ बनाने का कार्य पूरा हो गया है । पहले सात भाग बन कर पूरे हो गये हैं और आठवां भाग बन रहा है । उपागमन किनारों का लगभग ९८ प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है । इस पुल के निर्माण में कुल प्रगति ८५ प्रतिशत हुई है ।

(ख) वर्ष १९६२ के अन्त तक ।

चक्रधरपुर (बिहार) में माल–डिब्बा कारखाना

†३५२. **श्री ह० च० सौरा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के चक्रधरपुर में एक माल डिब्बा कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की क्रियान्विति के लिए अब तक क्या प्रगति की गई है ; और

(ग) इसकी क्रियान्विति में यदि कोई है तो मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सुकिन्दा परादीप एक्सप्रेस हाइवे

†**३५३. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार के सुकिन्दा देतारी खानों में परादीप बन्दरगाह तक एक एक्सप्रैस हाइवे बनाने के निर्णय की जानकारी है ;

(ख) क्या इस योजना को आरंभ करने से पूर्व भारत सरकार से उन्होंने कोई बातचीत की थी तथा क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए कोई रक़म दी है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि यदि इस हाइवे का निर्माण कर दिया गया तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में परादीप को बड़ा बन्दरगाह बना दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). कुछ समय पूर्व उड़ीसा सरकार ने परादीप पत्तन के विकास के संबंध में क्या उस क्षेत्र से लौह अयस्कों की खदान के संबंध में सुकिन्दा-देतारी खानों से परादीप बन्दरगाह तक एक एक्सप्रैस हाइवे बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। परन्तु उस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है। भारत सरकार को उड़ीसा सरकार के ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है कि वह इस एक्सप्रैस वे को बनायेगी अथवा केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई रक़म दी है।

(ग) जी नहीं। परादीप के सभी ऋतुओं का बन्दरगाह बनाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव था उस बन्दरगाह से लौह अयस्कों का निर्यात करने के प्रस्ताव पर योजना आयोग सभी मंत्रालयों के परामर्श से विचार कर रहा है। खान से बन्दरगाह तक लौह अयस्कों के परिवहन के लिए उपयुक्त सुविधाओं के प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है।

छपरा (मध्य प्रदेश) में आउट एजेन्सी

†**३५४. श्री वाडीवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की ओर से किसी नगर में आउट एजेन्सी बनाने के लिए क्या बातें होना आवश्यक हैं ; और

(ख) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने मध्य प्रदेश के सियोनी जिले में छपरा नगर में इसको खोलने पर विचार किया है क्योंकि यह एक वाणिज्यिक नगर है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सामान्यत: नगर के वाणिज्यिक महत्व, जनसंख्या, नगर और निकटस्थ स्टेशन के बीच दूरी तथा उपयुक्त ठेकेदार मिलने की संभावना पर विचार किया जाता है।

(ख) जी हां। छपरा में आउट एजेन्सी बनाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश राज्य परिवहन सेवाओं को दिया गया था परन्तु प्रस्ताव को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया था।

परन्तु दक्षिण पूर्व रेलवे मामले की पुनः जांच कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण पूर्व रेलवे पर सियोनी गंज साइडिंग को बन्द कर देना

†३५५. **श्री वाडीवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के नागपुर–नैनपुर अनुभर गध सियोनी रेलवे स्टेशन की सियोनी गंज साइडिंग को १५ अप्रैल १९६१ से बन्द कर दी गई है ;

(ख) इस साइडिंग को बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) १९५७, १९५८, १९५९, १९६०, १९६१ के वर्षों में इस साइडिंग से कितनी आय हुई थी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) साइडिंग से १९६१ में अनुमानतः २,४०० रुपये की आय हुई थी । अन्य वर्षों के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है तथा इकट्ठे किए जा रहे हैं ।

खाद्य पदार्थों का आयात

†३५६. **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में कितने तथा कितने मूल्य के खाद्य पदार्थों का आयात किया गया था ;

(ख) इसी वर्ष के इसमें से कितना तथा कितने मूल्य का सरकार द्वारा खरीदा गया था ;

(ग) इसी वर्ष में इसमें से कितना तथा कितने मूल्य का जनता को बेचा गया ; और

(घ) इस समय सरकार के पास कितना भंडार है तथा इस वर्ष में आयात के द्वारा कितनी कमी पूरी करने की आशा है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) लगभग १२० करोड़ रुपये की लागत के लगभग ३२ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न।

(ख) लगभग १५.६१ करोड़ रुपये की लागत के लगभग ३२४ हजार मीट्रिक टन चावल ।

(ग) यह बताना संभव नहीं है कि १९६१–६२ के संभरणों में से कितना बेचा गया था परन्तु वर्ष १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय भांडा ों से जारी गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों की अनुमानित मात्रा नीचे दी जाती है :––

	('००० मीट्रिक टनों में)
गेहूं	२,८५८
चावल	६८६
अन्य खाद्यान्न	३४
जोड़	३,५७८

†मूल अंग्रेजी में

जारी किये गये गेहूं का मूल्य लगभग १०७ करोड़ रुपये था तथा कोदो (मिलों) का मूल्य लगभग १ करोड़ रुपये था। इस समय केन्द्रीय भंडार से जारी किये गये चावल का अनुमानित मूल्य बताना संभव नहीं है क्योंक चावल के मूल्य चावल की किस्म के अनुसार १६ से ३० रुपये प्रति मन होते है।

(घ) भारत सरकार के पास मार्च, १९६१ के अन्त तक लगभग २१ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का भंडार था। १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष में लगभग ४० लाख टन का आयात हुआ था। इस में उपभोग आवश्यकतायें तथा बफर स्टाक व्यवस्था दोनों शामिल हैं।

बरना परियोजना

†३५७. **श्री ज्वाला प्र० ज्योतिषी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बरना परियोजना में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या प्रगति अनुसूची अनुसार हो रही है; और

(ग) इस के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) परियोजना की जांच हो रही है।

(ख) परियोजना का निर्माण अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(ग) आशा है कि परियोजना तीसरी योजना के अन्त तक आरम्भ होगी तथा चौथी योजना में पूरी होगी।

डाक तथा तार घरों के लिये भवन

†३५८. **श्री मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाजपुर नगर तथा पट्टा मंडाई में डाक तथा तार घरों के नये भवन बन गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन भवनों के निर्माण में विलम्ब हो रहा है; और

(ग) नये भवनों का खोलना कब संभव होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी नहीं। जाजपुर डाकखानों के भवन का विस्तार तथा पट्टा मंडई डाकखाने का पुनर्निर्माण हो रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) निश्चित तिथि बताना बड़ा कठिन है परन्तु आशा है कि भवनों का शीघ्र ही उपयोग होने लगा।

दक्षिण रेलवे पर विभागीय भोजन व्यवस्था

†३५९. **श्री सिद्दय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ वर्ष में दक्षिण रेलवे के जिन स्टेशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था लागू की जायेगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या बंगलौर मैसूर अनुभाग के मदुर स्टेशन पर विभागीय भोजन व्यवस्था होगी ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). दक्षिण रेलवे के अतिरिक्त स्टेशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दक्षिण रेलवे पर श्रम कल्याण निरीक्षक

†३६०. **श्री सिद्दय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे प्रशासन ने श्रम कल्याण निरीक्षकों के पदों को बढ़ाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण रेलवे से पुनः जांच करने के लिये तथा नये प्रस्ताव भेजने के लिये कहा गया है ।

आलू की पौध

†३६१. **श्री बालकृष्णन्** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में ब्रिटेन तथा अन्य देशों से आलू की कितनी पौध का आयात किया गया था;

(ख) इसी वर्ष में मद्रास राज्य को कितनी पौध की जरूरत थी; और

(ग) कितनी मात्रा का संभरण किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) ६३० पौध तथा १३ क्रास तथा सोलानम किस्म के ६४ हजार बीज ।

(ख) और (ग). मद्रास सरकार में स्काटलैंड में उत्पादित ग्रेट स्काट किस्म का एक हजार टन आलू का बीज मांगा था तथा पौध नहीं मांगी थी। परन्तु उन को ग्रेट स्काट किस्म का ५३ टन तथा १३ हंडरवेट आलू का बीज मिल सका क्योंकि ब्रिटेन से इस किस्म की और मात्रा नहीं मिल सकी थी ।

थाना 'क्रीक' पर पुल

†३६१. **श्री नाथ पाई** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने थाना 'क्रीक' पर पुल बनाने के लिये भारत सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गयी थी तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (क). जी हां। कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने थाना 'क्रीक' पर पुल के निर्माण के लिये एक प्रस्ताव

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्तुत किया था। परन्तु वित्तीय सीमाओं के कारण इस परियोजना के लिये केंन्द्रीय सहायता की व्यवस्था व्यवस्थ करना संभव नहीं था। यह मालूम हुआ है कि राज्य सरकार ने इस काम को राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** एक ही विषय से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की मुझे सूचना मिली है। इसलिये मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति तो नहीं देता केवल ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के लिये अनुमति देता हूं। अतः अब हम उस की चर्चा करेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : यह तो ठीक है किन्तु अगर हमें और आगे चर्चा करने की आवश्यकता हुई तो हम इस प्रस्ताव पर उतनी चर्चा नहीं कर सकते जितनी कि हम स्थगन प्रस्ताव पर कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** हर चीज उस की गुणिता के आधार पर तय की जायेगी। हमें अभी से कोई सामान्य नियम नहीं बना लेना चाहिये।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी

†**श्रीमती विमला देवी** (एलुरु) : नियम १९७ के अधीन मैं सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री का ध्यान आन्ध्र प्रदेश में २० प्रतिशत बिजली की कटौती की ओर तथा उस परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा एकत्रित करने में हुई असफलता की ओर आकर्षित करती हूं और निवेदन करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

†**सिंचाई तथा विद्यूत् मंत्री (हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)** : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस समय आन्ध्र प्रदेश में बिजली की सप्लाई की स्थिति अच्छी नहीं है। इसका कारण बिजली की मांग में असाधारण वृद्धि और विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण दूसरी योजना में सम्मिलित की गई कुछ परियोजना का पूरा न हो सकना है। बिजली के क्षेत्र को विदेशी मुद्रा की जितनी सीमित राशि मिली वह दूसरी योजना में केवल 'अत्यावश्यक' परियोजनाओं के काम में लाई गई। १९५९ में हमने सारी स्थिति की जांच की और तुंगभद्रा-वेलोर परियोजना के लिये जापान से मिलने वाली सहायता को दिया। ऊपर सिलेरू जल विद्युत परियोजना प्रक्रम १ के लिये स्विस सहायता का प्रबन्ध किया गया और अब वर्तमान स्थिति यह है कि तुंगभद्रा नेल्लोर परियोजना के लिये समस्त संयंत्र और उपकरण और ऊपर सिलेरू स्टेज – १ योजना के लिये मुख्य प्रजनन संयंत्र और उपकरणों के लिये व्यादेश भेजे जा चुके हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, अमरीका के प्राधिकारियों तथा अन्त र्ष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक से बातचीत करने के पश्चात् हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि रामगुण्ड्म और कोठागुण्डम के लिये हमें उनसे सहायता मिल सकती है।

तीसरी योजना के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश में कुल ६३८ एम डब्ल्यु विद्युत प्रजनन की क्षमता हो जायेगी जब कि मांग केवल ४२८ एम डब्ल्यु की है। फिर भी आन्ध्र प्रदेश में बिजली की

---

†मूल अंग्रजी में

मांग है उसको अपेक्षा यह कुल क्षमता थोड़ी कम अवश्य रहेगी इसी कमी के बारे में मेरा मंत्रालय काफी विचार कर रहा है। वह सोच रहा है कि यह कमी या तो पड़ौसी राज्यों से मांग कर पूरी की जाये अथवा वहां और जेनरेटर लगाया जाये। किन्तु यह तभी संभव है जब कि हमें विदेशी मुद्रा मिल सकी। और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये मेरा मंत्रालय चिन्तित है। अधिक विस्तृत जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट, १, अनुबन्ध संख्या ५२]।**

†**श्रीमती विमला देवी :** दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी विदेशी मुद्रा निर्धारित की गई थी और वास्तव में कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

†**हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम :** मेरे पास इस समय आंकड़े तो नहीं हैं। मेरा विचार था कि मेरे वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह स्वाभाविक है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के प्रस्ताव के बाद माननीय सदस्य स्पष्टीकरण के लिये एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं। अतः माननीय मंत्री महोदय भविष्य में इसका ध्यान रखें।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** मैं पहले ही अपनी भूल स्वीकार कर चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को यह जानकारी पत्र द्वारा अथवा किसी अन्य तरह दी जा सकती है।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** अच्छी बात है।

†**श्रीमती विमला देवी :** समाचारपत्रों में छपा है कि जेकोस्लोवेकिया तथा पोलैंड भी आन्ध्र प्रदेश में संयंत्र लगाना चाहते हैं। जेकोस्लोवेकिया ५०,००० किलोवाट का तथा पोलैंड ६,००० किलोवाट का संयंत्र लगाना चाहते हैं। क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का उत्तर भी पहले प्रश्न के साथ दे दिया जाय।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** बहुत अच्छी बात है।

पाकिस्तान उच्च आयोग द्वारा एक ऐसे मानचित्र का परिचालन जिस में भारत के कुछ राज्यक्षेत्रों को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है

†**अध्यक्ष महोदय :** भारतीय राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान का भाग दिखाने वाले नकशे का पाकिस्तान उच्च आयोग द्वारा परिचालन करने के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। क्या प्रधान मंत्री इस बारे में कोई वक्तव्य देंगे।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** (भोपाल): नियम १९७ के अनुसार मैं प्रधान मंत्री का ध्यान भारतीय राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान का भाग दिखाने वाले नकशे का पाक उच्च आयोग द्वारा परिचालन

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती मैमूना सुल्तान]

करने की ओर आकर्षित करती हूं और निवेदन करती हूं कि प्रधान मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य भी दें ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** हमने अभी तक वह नकशा नहीं देखा है केवल अखबारों में ही इसके बारे में पढ़ा है । किन्तु यह बात सही मालूम होती है । पाकिस्तानी अधिकारियों को शायद सही बात मालूम नहीं है । हम इस बारे में जांच करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे । पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस ओर ध्यान दिलाने के अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया होगा तो दंड दिया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : असल बात यह है कि यह नकशा पाकिस्तान जाने वाले पर्यटकों को दिया जाता है । पश्चिम बंगाल में भी इस नकशे की प्रतियां बाँटी गई हैं । मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई सूचना भेजी है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं समझता कि यह बात ठीक है । यह तो एक नई बात है । कलकत्ता में किसी के पास यह नकशा डाक द्वारा आया था । हो सकता है कुछ और व्यक्तियों के पास भी आया हो । पश्चिम बंगाल सरकार के पास इस बात के बारे में लिखने का समय ही नहीं था । यह बात तो कल के समाचारपत्रों में ही छपी है । हो सकता है कि वे हमें लिखें, इसका विरोध भी करे । वे स्वयं भी इस बारे में कोई कार्यवाही करें ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : कानून के अनुसार तो ऐसे कार्य करने वाले को जेल की सजा दी जाती है । ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान स्थित उच्चायुक्त ने यह नकशा छपाया हो । चूंकि यह कूटनीतिज्ञता का मामला है उनको सजा देना असंभव है । तो भी सरकार इस बारे में क्या गम्भीर कार्यवाही करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या सज़ा दी जायेगी यह अनुमान इस समय लगाना संभव नहीं है । किन्तु इतना सत्य है कि अपराधी को दण्ड दिया जायेगा । सरकार इस बारे में जांच करेगी कि क्या कार्यवाही की जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अभी कुछ कहना संभव नहीं है । हम इस बारे में अच्छी तरह जांच करेंगे ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** (होशंगाबाद) : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह खबर सही है तो क्या सरकार उन सभी नकशों को जब्त करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इस समय यह कैसे बता सकता हूं कि सरकार इस बारे में क्या करेगी । सरकार इस बारे में जांच कर रही है और पुलिस ही कुछ करेगी । अगर वह जब्त करना चाहे तो करेगी और इसके लिये उसे सरकार के आदेश की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** (भोपाल) : क्या यह सच है कि हैदराबाद को भी उस नकशे में पाकिस्तान का अंग दिखाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने वह नकशा देखा नहीं है। अतः उस नकशे में क्या है वह मेरे लिये बताना कठिन है।

पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर मुसलमानों का कथित जमा होना

†श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर): नियम १९७ के अधीन मैं प्रधान मंत्री का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान सीमान्त पर मुसलमानों के बड़े पैमाने पर जमा होने के सम्बन्ध में आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): माल्दा में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई थीं जिनका पाकिस्तान के तथा कुछ अन्य विदेशी समाचार-पत्रों में बहुत बढ़ा चढ़ा कर वृतान्त प्रकाशित हुआ है। वहां वास्तव में क्या हुआ उस बारे में संक्षेप में बताना तो मुश्किल है। किन्तु फिर भी हम सारे तथ्यों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु फिर भी मृतकों, घायलों तथा माल्दा छोड़ कर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है।

ढाका और राजशाही में भी कुछ मार काट और लूट की घटनायें हुई। असली आंकड़े पाना तो बड़ा कठिन है क्योंकि एक ओर तो बढ़ा चढ़ा कर संख्या बताई जा रही हैं तथा दूसरी ओर उनकी संख्या घट कर बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम बढ़ा चढ़ा कर कोई बात नहीं कहना चाहते। हम सही आंकड़े प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक पूरी जानकारी हमें नहीं मालूम हो जाती हम कुछ नहीं कह सकते।

समितियों के लिये निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"कि खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के दिनांक १७ सितम्बर, १९५५ के संकल्प संख्या एफ ४–१३/५३––क्रम––२ द्वारा संशोधित भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक २८ मई, १९३६ के संकल्प संख्या एफ० २५४/३४-ए के पैराग्राफ ३ के खण्ड (९) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निर्देश दें, भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के सदस्यों के रूप मे काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।

†अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है:

"कि खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के दिनांक १७ दिसम्बर, १९५५ के संकल्प संख्या एफ ४–१३/५३––क्रम––२ द्वारा संशोधित भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक २८ मई, १९३६ के संकल्प संख्या एफ० २५४/३४-ए के पैराग्राफ ३ के खण्ड (९) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निर्देश दें, भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने मे से दो सदस्य चुनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समय-समय पर संशोधित भारतीय तिलहन समिति, अधिनियम १९४६ की धारा ४ की उप-धारा (एस०) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निर्देश दें, भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समय-समय पर संशोधित भारतीय तिलहन समिति, अधिनियम १९४६ की धारा ४ की उप-धारा (एस०) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निर्देश दें, भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि कृषि उत्पाद तथा कुछ अन्य वस्तुओं का सहकारिता के सिद्धान्तों के आधार पर विकास करने और तत्सम्बन्धी विषयों के लिये एक निगम के निगमन तथा विनियमन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।'

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि कृषि उत्पाद तथा कुछ अन्य वस्तुओं का सहकारिता के सिद्धान्तों के आधार पर विकास करने और तत्सम्बन्धी विषयों के लिये एक निगम के निगमन तथा विनियमन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री सु० कु० डे०** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री हरिश्चन्द माथुर द्वारा २६ अप्रैल, १९६२ को प्रस्तुत तथा श्री भगवत झा आजाद द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों मे समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस अधिवेशन में समवेत लोक-सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राष्ट्रपति महोदय के अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १८ अप्रैल, १९६२ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है'।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० कृ० ल०** (हतकंगले) : मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का रहन-सहन ऊंचा उठाने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ।

तीसरी योजना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया है । तथा सिंचाई पर किये जाने वाले व्यय में भी वृद्धि की गई है । इस प्रकार अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी । लेकिन महाराष्ट्र के कुछ भागों में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है जिसका प्रमुख कारण कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश से विवाद है । भारत सरकार को हस्तक्षेप करके उस विवाद को हल कराना चाहिये । हालांकि गुलाटी आयोग की नियुक्ति इस सम्बन्ध में कर दी गई है किन्तु मुझे डर है कि शायद यह आयोग अपना काम तीसरी योजना के दौरान मे भी समाप्त न कर सके ।

मराठी भाषी क्षेत्र जैसे निपाली, बेलगांव, और करवार को महाराष्ट्र राज्य में मिला देना चाहिये । इनको मिलाने का मामला पिछले सात वर्षों से अभी तक निलम्बित चला आ रहा है । आशा है कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

बेरोजगारी को भी यथाशीघ्र समाप्त करना चाहिये । राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में इस समस्या का उल्लेख किया है । मेरा निवेदन है कि बेरोजगार लोगों को उनकी बेरोजगारी के दिनों में सहायता देने के लिये सरकार को २५ करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी चाहिये ।

प्रत्येक जिले में उद्योगों के विकास के लिये औद्योगिक एस्टेट तथा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तुरन्त करनी चाहिये ।

इन सुझावों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तमा (खम्मम) : विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने यह कहा है कि कांग्रेस के शासन काल में जो प्रगति हुई है उसमें पहिला दर्जा इस बात को दिया जाना चाहिये कि हमारे ऋणों की राशि बहुत बढ़ गयी है और दूसरे कि करों में वृद्धि हो रही है । मेरे विचार से इस प्रकार की बातें कहना अनुत्तरदायित्वपूर्ण है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया है कि कई विरोधों के बावजूद भी अमेरिका ने अणु परीक्षण करना आरम्भ कर दिया है । मेरे विचार से इस प्रकार के आरोप के पीछे उनके पक्षपात का आभास मिलता है उन्हें रूस पर यह आरोप लगाना चाहिये था जिसने इस प्रकार के परीक्षणों की शृंखला कायम की ।

विरोधी सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रतिक्रियात्मक और सामन्तवादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया है । आन्ध्र में स्वयं साम्यवादियों ने एक बहुत बड़े जमींदार को लोक-सभा के लिये खड़ा किया ।

विरोधी पक्षों ने कांग्रेस में आपसी फूट का भी जिक्र किया है तथापि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जहां मतभेद होने पर भी साथ साथ रहने की गुंजायश है, जबकि साम्यवादी दल में तो विरोधी सदस्यों को चुप कर दिया जाता है । आन्ध्र में जब एक उच्च श्रेणी के साम्यवादी नेता को टिकट नहीं मिला तो वह एक साम्यवादी दल के सदस्य के विरुद्ध खड़ा हो गया और साम्यवादी दल के सदस्य की जमानत जब्त हो गयी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समाजवादियों का काम मजदूरों में फूट डलवा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। यदि यह दल लोकतन्त्र में विश्वास रखता है तो उन्हें चुनावों के बाद इस प्रकार मजदूरों को नहीं उभाड़ना चाहिये था।

यद्यपि साम्यवादियों ने चुनावों में हुए कदाचार के सम्बन्ध में कांग्रेस पर बहुत आरोप लगाये हैं सच्चाई यह है कि इन्होंने अपने कार्यों से इस बात का सबूत दिया है कि वे लोकतन्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिये गड्ढे खोदे गये और फल यह हुआ कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष उसमें गिर गये।

हमें उन मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने कट्टर प्रतिगामियों तथा समाजवादियों के गठबन्धन के बावजूद भी कांग्रेस को सफलता प्रदान की।

एक सदस्य ने यह प्रस्ताव किया है कि कांग्रेसियों की आस्तियों तथा दायित्वों की जांच की जानी चाहिये। ऐसा सुझाव पहिले भी दिया गया था। मेरे विचार से इसके स्थान पर राजनैतिक और देश के प्रति सच्चाई की जांच की जानी चाहिये।

योजना आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के सन्तुलित विकास पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उस पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये।

नदी पानी विवादों का इस प्रकार चलते रहना देश के हित में नहीं है अतः सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलायी जाये और उसमें इसका निपटारा किया जाये।

मेरे विचार से कोचमपाद और श्री सैलम परियोजना पर कार्य गुलाटी परियोजना के प्रतिवेदन के आने के पूर्व ही आरम्भ हो जाना चाहिये।

जहां तक इस्पात के निर्माण का प्रश्न है नये एकक इस क्षेत्र में तभी स्थापित किये जायें जबकि वर्तमान एककों की क्षमता का पूरा उपयोग किया गया हो।

बख्शी अब्दुल रशीद (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब स्पीकर साहब, जनाब सद्र साहब जम्हूरिया के ऐड्रेस पर परसों से इस ऐवान में बहस हो रही है। मैं उस शुक्रिया की करारदाद की, जिस को श्री माथुर ने इस हाउस में पेश किया है, मैं ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जहां तक साहबे सद्रे जम्हूरिया के ऐड्रेस का ताल्लुक है, अगर्चे इस दफा ऐड्रेस मुख्तसर है लेकिन उस में उन तमाम बातों की तरफ इस ऐवान के मोअज्जिज मेम्बरान की तवज्जह दिलाई गई है जो आने वाले पांच सालों में इस हाउस के सामने दरपेश आयेंगी और जिन को इस हाउस को निभाना है। जहां तक साहबे सद्रे जम्हूरिया के उन नुक्तों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इस हाउस के तमाम मोअज्जिज मेम्बरों को उन पर गौर करना है और उन्हें मुल्क की खुशहाली के लिये आगे बढ़ाना है।

सब से बड़ा और अहम मसला जो कौम और मुल्क के सामने इस वक्त है वह कौमी एकजहती है। जहां तक इस मसले का ताल्लुक है, पिछले साल वजीर आजम ने इस सिलसिले में तमाम प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर और अपोजीशन के लीडरों की एक कांफ्रेंस दिल्ली में मुनक्किद की, और उस में ऐसे मसलों के ऊपर काफी विचार हुआ। मगर उस के बाद आज तक मुल्क के सामने कोई ठोस कदम या इस बारे में नहीं आये कि नेशनल इंटेग्रेशन कांफ्रेंस बुलाने से मुल्क और

कौम को किस तरह से एक दूसरे के नजदीक लाया जा सकता है और मुल्क के इस बड़े मसले को हल किया जा सकता है। आज तक इस मसले के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। तीसरा एलेक्शन मुल्क में खत्म हुआ है और तमाम हिन्दुस्तान के सामने और दुनियां के सामने उस के नतायज आये हैं कि किन किन जमातों ने एलेक्शन में हिस्सा लिया और उन जमातों के एलेक्शन मैनिफेस्टो मुल्क के सामने क्या रहे और किस तरीके से इस दफा भी, हालांकि देश का आईन मजहबी सूबापरस्ती और फिर्कापरस्ती की इजाजत एक दूसरे के खिलाफ नहीं देता, इन को उठाया गया और दोहराया गया, महज अपने अगराज हासिल करने के लिये, जिस से कि मुल्क की एकजहती को बड़ा नुक्सान पहुंचा है। मुझे उम्मीद है कि एलेक्शन कमीशन उन तमाम वाकयात को सामने रक्खेगा, जो इस एलेक्शन के दौरान हुए। वह देखे कि आइन के तहत और आइन के बाहर किस तरीके से एलेक्शन में ऐसी चीजें उठाई गईं, जिन के उठाये जाने से कौम की एकजहती को बहुत बड़ा नुक्सान पहुंचा और किस तरीके से आइन की खिलाफवर्जी हुई।

इस सिलसिले में मेरी अर्जदाश्त यह है कि जहां तक इस मसले का ताल्लुक है, अगर वजीरे आजम ने पिछली बार इस मसले को उठाया और तमाम अपोजीशन पार्टीज के लीडरों ने उस में शमूलियत की, जिन लोगों ने इस मसले को एक कौमी मसला समझ कर इस को आगे ले चलने का तहैया किया है, मैं उन तमाम बुजुर्गों से इस्तदुआ करूंगा कि वे बैठें और इस बारे में सोचें और पार्टी लेवेल से इस मामले को ऊपर रख कर और मुल्क को सामने रख कर ठोस कदम उठायें, ताकि एकजहती हो सके और मुनाफरत और दूसरी तीसरी चीजें जो हमारे भारतवर्ष के लिये बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं, वह दूर हो सकें।

इस के अलावा साहब सद्र ने कुछ और बातों की तरफ भी ऐड्रेस में तवज्जह दिलाई है। उस में मुझे इतना कहना है कि जहां तक इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का ताल्लुक है, अगर्चे उस हिस्से में, जहां से मैं इस ऐवान में आया हूं, कुदरती जराय मौजूद हैं, एक प्लैन खत्म हुई दूसरी प्लैन खत्म हुई और तीसरी प्लैन भी इस वक्त एक साल से चल रही है, आज तक उस हिस्से में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कारखाना वजूद में नहीं आया। बावजूद इसके कि जूनअत के लिए सब चीजें और कुदरती जराए मौजूद हैं।

इसके अलावा जनाब वाला, सबसे बड़ी चीज जो है वह थर्ड फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट है। हम एक तरफ तो मुल्क को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं और उसके लिए उसको सरमाए की जरूरत है। लेकिन तीसरे प्लान में फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों की वजह से हमारी रियासत का बहुत ज्यादा रुपया कम हुआ है और पांच साल में वह बहुत बड़ी रकम बनती है। उस रकम के कम होने से रियासत को इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को बढ़ावा देने के सिलसिले में बहुत बड़ा धक्का लगेगा और मुझे उम्मीद है कि उस मसले पर फिर से गौर किया जाएगा और इस रियासत की बैकवर्डनैस और पसमांदगी को सामने रखा जाएगा क्योंकि वही एक हिस्सा है जो आज तक मुल्क के दूसरे हिस्सों से रेलवे के ज़रिए नहीं मिलाया गया है। जहां तक रियासती सरकार का ताल्लुक है इन्तहाई कोशिश की गयी है हर एक हिस्से को एक दूसरे से मिलाने की। चुनांचे लेह जैसे सरहदी इलाके को सड़क के ज़रिए बाकी हिस्सों से मिलाया गया है और किश्तवाड़ आदि जैसे दूसरे हिस्सों को सड़क के ज़रिए दूसरे हिस्सों से मिलाया गया है। लेकिन वह रियासत आज तक इतने सालों के बाद भी देश के रेलवे के नक्शे में नहीं आ सकी। और जहां तक आयन्दा पांच सालों का ताल्लुक है उसमें भी हम इस सिलसिले में मायूस हैं क्योंकि इन पांच सालों में भी रेलवे का नक्शा उस तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि पसमांदगी को दूर करने के लिए

और इक्तसादी तरक्की करने के लिए देश के दूसरे सूबों की तरह इस रियासत के लिए भी रेलवे निहायत जरूरी है यह महसूस किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि केन्द्रीय सरकार इस मसले की तरफ खास तवज्जह देगी ताकि यह हिस्सा भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ सके।

साथ साथ यह इन्तहाई खुशी की बात है कि सदर जम्हूरिया ने अपने एड्रेस में रूरल पापुलेशन की तरफ इस ऐवान की तवज्जह दिलायी है, पंचायतों, कोआपरेशन और इंडस्ट्रीज़ वगैरह की तरफ। जहां तक पंचायत राज्य और कोआपरेशन का ताल्लुक है, जनाब वाला, मुझे निहायत खुशी है कि सदर जम्हूरिया ने इस ऐवान के मेम्बरों के सामने इस मसअले को रखा है और बतलाया है कि इस सिलसिले में बहुत से पाइलट प्राजेक्ट मुल्क के सामने आने वाले हैं। बहुत अच्छे प्राजेक्ट बने हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। लेकिन जहां तक कोआपरेशन का ताल्लुक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक देहाती दुनिया को सारी सहूलियतें नहीं दी जायेंगी देहाती दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है और कसबों के साथ और शहरी दुनिया के साथ में नहीं आ सकती। इस सिलसिले में सालहासाल कान्फ्रेंस तो बहुत होती और बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं देहाती दुनिया को उठाने के लिए ऐसे डिसीशन लिए गए मगर उन पर आज तक कोई अमल नहीं हो सका। अगर देहाती लोगों को शार्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लांग टर्म लोन दिए जाएं तो वे इक्तसादी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं।

आखिर में मैं इस ऐवान का ज्यादा वक्त न लेते हुए यह अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने सीक्योरिटी काउंसिल में काश्मीर का मसला उठाया है। जहां तक इस मसअले का ताल्लुक है इस ऐवान के मेम्बर और इस देश के अवाम इस बारे मे मुझे से ज्यादा जानते हैं। यह मसला कोई मसला नहीं है। महज़ पाकिस्तान के चन्द हुक्काम और कुछ ताकतें इसको इसलिए जिन्दा रखना चाहती हैं क्योंकि उन्हें अपनी परेशानियां हैं, अपनी इक्तसादी बदहाली है, मुल्क में हल्लड़बाजी और डिकटेटरशिप है। इसलिए वह अपने लोगों की तवज्जह को बदलने के लिए मसला काश्मीर को उठा रहे हैं। जहां तक काश्मीर के मसले का ताल्लुक है, जिस तरह और ६०५ रियासतें हिन्दुस्तान में शामिल हुई उसी तरह काश्मीर भी उसमें शामिल हुआ। मैं समझता हूं कि जब ६०५ रियासतों के बारे में कुछ न कह कर सिर्फ काश्मीर का नाम लिया जाता है तो यह सिवा शरारत के और कुछ नहीं है। जहां तक हकीकत का ताल्लुक है सीक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान नहीं गया था बल्कि हिन्दुस्तान गया था यह शिकायत ले कर कि एग्रेशन को वेकेट किया जाए। जो हिस्सा पाकिस्तान ने फौजी ताकत के बलबूते पर हासिल कर लिया है उसको वापस दिलाया जाए। शिकायत यही थी और कोई शिकायत नहीं थी। मगर यह मसला १५ साल से इसी तरह पड़ रहा और उन्होंने इस मसले को दुनिया के सामने दूसरे तरीके से रखने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि १४ बरस के बाद इस दफा यूनाइटेडनेशन उस असली शिकायत पर गौर करेगी और पाकिस्तान से उस इलाके को खाली कराएगी जो उन्होंने करीब १४ साल से अपने हाथ में लिया हुआ है।

इसी तरह जहां तक चाइनीज एग्रेशन का ताल्लुक है हमारा बार्डर उसमें भी फंसा हुआ है और काफी इलाका उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया का ताल्लुक है उसने सरहदों को काफी मजबूत किया है। लेकिन इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूंगा कि हिन्दुस्तान के फौजी जवानों को २१ हजार, २० हजार और १८ हजार फीट की ऊंचाइयों पर काम करना पड़ रहा है। मैं अर्ज करूंगा कि जिन लोगों को अब तक ५००० फीट की ऊंचाई पर काम करने का मौका मिला है उनको अगर बयकवक्त १८ हजार या १७ हजार फीट की ऊंचाई पर काम करना

पड़े तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि उनको खास मराआत मिलनी चाहिए ताकि वह वहां रह सकें और दुश्मन का मुकाबला कर सकें।

इन चन्द अल्फाज के साथ में साहिबे सदर जम्हूरिया के उस ऐड्रेस के लिए शुक्रिया अदा करता हूं और जनाब माथुर की उस तजवीज की ताईद करता हूं जो उन्होंने हाउस के सामने रखी।

†**श्री मा० श्री० अणे** (नागपुर) : राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के बहाने हमें यह अवसर मिला है कि हम उस महान व्यक्ति के द्वारा देश और राष्ट्र के प्रति की गयी सेवाओं के प्रति आभार प्रगट करें। उन्होंने पिछले बारह वर्षों से देश की अत्यंत सेवायें की हैं।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में डा० राजेन्द्रप्रसाद को गंगा की धारा कहा जा सकता है जिसमें प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू, श्री बल्लभ भाई पटेल और श्री अबुल कलाम आजाद जैसे लोग मिल गये इन्हें हम जमुना कह सकते हैं डा० राधाकृष्णन सरस्वती की धारा की तरह हैं जो सबको दिखलायी नहीं देती है तथापि जिसका जल अन्दर ही अन्दर मिलता है और त्रिवणी को और पुनीत बना देता है।

राष्ट्रपति ने अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए भी महात्मा गांधी के उच्च आदर्शों को सामने रखा वस्तुतः उन्होंने अपने कार्यों से नहीं बल्कि अपने जीवन और व्यवहार से वह उदाहरण प्रस्तुत किया कि वह भारत की जनता के लिये आदर्श हैं।

जब वे अपना अंतिम अभिभाषण पढ़ रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे और मुझे वह पिता याद आ रहा था जो बड़े प्यार से पाली हुई पुत्री को अपने जामाता के हाथों में सौंप देता है। उनकी समस्त चिन्ता लोकतंत्र के भविष्य के विषय में थी जिसे उन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है।

निसंदेह लोगों में यह भ्रांति हो गयी है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें जमती जा रही हैं। इसके प्रमाणस्वरूप उनका यह कहना है कि देश में तीन चुनाव हो चुके हैं और तीनों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है।

तथापि मेरे विचार से लोकतंत्र के दो रूप हैं। एक वाह्य रूप दूसरी उसकी आत्मा। जहां तक वाह्य रूप का ताल्लुक है लोग इस बात के प्रयत्न में रहते हैं कि इस प्रणाली पर उनका अधिकार रहे। तथापि हमें यह देखना है कि लोकतंत्र को भावना कहां तक निभायी जा रही है।

इस संबंध में यह कहा जाता है कि यद्यपि चुनावों का व्यय हमें भेजना होता है तथापि वे विवरण अधिकांश झूटे होते हैं और विभिन्न राजनैतिक दल जो लाखों रुपया चन्दे के रूप में इकट्ठा करते हैं उसे चुनावों में व्यय किया जाता है। इस प्रकार बाहर से हम कुछ भी कहें तथापि अन्दर से हम लोकतंत्र के सच्चे सिद्धान्तों से दूर हटते जा रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनने और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राष्ट्रपति ने देश की तरक्की के बारे में जो चित्रण किया है, वह सही नहीं है। इस के अलावा उस में देश की बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं की चर्चा भी नहीं है।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य है लोकतंत्रात्मक समाजवाद की स्थापना। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसेवक यादव]

सरकार ने पिछले पंद्रह वर्षों में जो कार्य किये हैं। उनको देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस सम्बन्ध में प्रगति अच्छी नहीं हुई है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करना और सामाजिक तथा आर्थिक समता को स्थापित करना। अगर हम इस कसोटी पर सरकार के कार्यों को कसें, तो हम पाते हैं कि आर्थिक विषमता घटी नहीं है, बल्कि बढ़ी है। जब हम एक ओर इस देश के सब से छोटे सरकारी कर्मचारियों---गांव के चौकीदार, स्कूल के अध्यापक और कार्यालयों के बाबुओं ---को तन्खवाहों और आवास आदि की सुविधाओं को देखते हैं और दूसरी ओर उच्च सरकारी अधिकारियों, केन्द्र के मंत्रियों और खास तौर पर प्रधान मंत्री के वेतन, भत्ते, आवास, और सुरक्षा आदि पर किये जाने वाले भारी धन पर नज़र डालते हैं, तो पता चलता है कि विषमता दूर नहीं हुई है---वह घटी नहीं है, बल्कि बढ़ी है। आज गांव के एक चौकीदार को पांच रुपये मासिक और दफ्तर के बाबू को सौ रुपये मासिक वेतन मिलता है, जब कि इसकी तुलना में प्रधान मंत्री के भत्ते, सुरक्षा और आवास आदि पर लगभग पच्चीस हजार रोज़ का खर्च होता है,। मैं नहीं समझता कि यह किस तरह का समाजवाद है और किस प्रकार की बराबरी है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अगर हम व्यापार में लगे लोगों की आमदनी को देखें और उस के मुकाबले में मज़दूरी करने वालों की आमदनी को देखें तो हम पाते हैं कि आज एक खेत मज़दूर आठ, बारह आने या रुपया, ड़ेढ़ रुपया रोज़, पाता है, जब कि बिड़ला सेठ की आमदनी लगभग एक लाख रुपया रोज़ है। यह किस प्रकार का समाजवाद है ?

हमारे बीच में जो सामाजिक विषमता है, यदि हम उस की ओर ध्यान दें, तो हम इस नतीजे पर पहुचेंगे कि जहां तक भाषणों का सवाल है, सामाजिक विषमता अवश्य दूर हुई है, लेकिन व्यवहार में, सरकारी नौकरियों में वह अभी तक मौजूद है। उदाहरण के तौर पर मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश का राष्ट्रपति कोई हरिजन होगा। राष्ट्रपति कोई हरिजन हुआ या नहीं हुआ लेकिन मैंने यह जरूर देखा है कि बाबू जगजीवनराम जी के पास रेल विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग था और उसको भी उन से ले लिया गया है। सारे देश में किसी राज्य का हरिजन मुख्य मंत्री नहीं, है, कोई राज्यपाल नहीं है। विदेशों मे कोई भी राजदूत के पद पर हरिजन या पिछड़ी जाति में से नहीं लिया गया है। मैं नहीं कह सकता हूं कि हरिजनों को उच्च पद देने में कहां तक प्रगति हुई है और कहां तक इनकी बात सत्य है।

सरकार ने एक आयोग गठित किया था जिसको पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। उस ने कई एक साल पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी। सदन के माननीय सदस्यों के बार बार कहने के बावजूद भी आज तक उस प्रतिवेदन पर बहस नहीं हुई है और उसकी सिफारिशों

को लागू करने की बात तो बाद की है। सिफारिशों को लागू करने की बात तो दूर की है, उस के प्रतिवेदन पर आज तक बहस करने का मौका सदस्यों को नहीं दिया गया है । सारी बातें जो राष्ट्रपिता गांधी जी कहा करते थे, उन सबको यह सरकार आज छोड़ चुकी है और अब तो वह केवल उन के नाम पर ही सरकार चलाना चाहती है । उनकी बातों का जो मतलब था, उन के पीछे जो भावना थी, उस सब से इस सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है ।

आज राष्ट्रीय एकता पर बहुत जोर दिया जाता है । सदन के अन्दर और बाहर मैं आज समझता हूं कि कोई भी महानुभाव नहीं होंगे जो राष्ट्रीय एकता पर ज़ोर न देते हों । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किन लोगों की राष्ट्रीय एकता आप करना चाहते हैं। क्या आप देश के उन ५०—६० लाख लोगों की राष्ट्रीय एकता चाहते हैं जो भाषा में, भूषा में, भवन में और भोजन के मामले में साधारण जनता से बिल्कुल भिन्न हैं या करोड़ों नर नारियों जिनकी भाषा भूषा, भोजन इत्यादि एक हैं, उनकी राष्ट्रीय एकता चाहते हैं। इन लोगों की ये सब चीजें उन पचास साठ लाख लोगों से बिल्कुल भिन्न है । मैं पूछना चाहता हूं कि आप किन की एकता चाहते हैं। आज देश की एकता की जरूरत है और यदि हम यह एकता चाहते हैं और यदि आप वास्तव में देश हित से प्रेरित हैं तो आपको इन लोगों की तरफ ध्यान देना होगा न कि उन पचास साठ लोगों की तरफ जिन का भोजन, भवन भाषा इत्यादि इन से बिल्कुल भिन्न है । लेकिन आज हो इस से बिल्कुल उल्टा रहा है । आज सारे काम उन्हीं के लिये किये जाते हैं । हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में, खास तौर से गजेटेड नौकरियों में जो इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं, विशेषतः जो हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, और खास तौर से दबे पिसे अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको कोई स्थान नहीं दिया जाता है । जब तक आप उनको आगे लाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, देश की एकता का नारा चाहे वह कितना ही जरूरी क्यों न हो, कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है और उसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता है ।

राष्ट्रपति जी ने तृतीय पंचवर्षीय योजना का भी जिक्र किया है । तृतीय योजना का एक वर्ष बीत गया है और कहा गया है कि इस एक साल में काफी अच्छे नतीजे निकले हैं। दो योजनायें पूरी हो गई और तीसरी का भी एक वर्ष बीत गया लेकिन अगर आप औसत आमदनी एक व्यक्ति की देखें तो आपको पता चलेगा कि वह मौजूदा आंकड़ों के अनुसार ३२७ रुपये वार्षिक है । इस स्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि तरक्की हुई है । इस में छोटे और बड़े दोनों लोगों की आमदनियां शामिल हैं। अगर आप अमीर और गरीब लोगों की आमदनियां का अलग अलग से हिसाब लगायें तो यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा नीचे चला जाएगा।

पंचवर्षीय योजनाओं में पैसा किन किन जगहों पर खर्च होता है, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं । अधिकतर पैसा खर्च होता है भवनों के आधुनिकीकरण पर, पैसा खर्च किया जाता है बड़े बड़े सचिवालयों की इमारतें बनाने पर और उन इमारतों को शीतताप नियंत्रित रखने पर । आज ध्यान इस तरफ दिया जाता है कि

[श्री रमसेवक यादव]

बड़े बड़े सरकारी नौकर जो हैं, जो मंत्री हैं, उन के लिए ऐश और आराम की सामग्री कैसे उपलब्ध की जाए, उनको अधिक से अधिक सुविधायें कैसे प्रदान की जायें। यही चीजें हैं जिन पर पैसा खर्च होता है । आज जो योजना चल रही है वह केवल पचास लाख लोगों की योजना है और हर पांच साल के बाद एक दो लाख आदमी और कुछ थोड़ासा इन योजनाओं से लाभान्वित हो जाते हैं और उनको कुछ थोड़ीसी सुविधायें मिल जाती हैं। योजना से सारा देश एक साथ उठे, इस तरह की इस में कोई चीज़ नहीं है । इस योजना में जो बुनियादी दोष हैं उनको आज दूर करने की आवश्यकता है । जब तक इन दोषों को दूर नहीं किया जाता, योजना में परिवर्तन नहीं किया जाता, ग्राम और जिला स्तर से इसकी शुरुआत नहीं की जाती तब तक योजना से बहुसंख्यक नागरिकों को अधिक लाभ नहीं हो सकता । आज देश के जो मालिक हैं , जो सत्ता में हैं, जो शक्ति में हैं उन्हें ही इस योजना से लाभ पहुंचा है । अगर वास्तव में गरीब लोगों के लिए कोई चीज़ की गई होती तो उन में उल्लास होता, उन में जोश होता । योजना के प्रति गांवों में, शहरों में, सिवाय इन पचास लाख लोगों के किसी में भी उल्लास नहीं है, जोश नहीं है, और न ही इस योजना की कोई चिन्ता है कि यह पूरी होती है या नहीं होती है ।

प्रधान मंत्री जी ने बड़ी चिन्ता के साथ एक बार कहा था कि राष्ट्रीय आय तो बढ़ी है, लेकिन वह कहां चली गई, इसका उनको इल्म नहीं है और शायद उसका पता लगाने के लिए , उसकी छानबीन करने के लिए कोई कमेटी नियुक्त की गई है । प्रधान मंत्री जी तो ऐसी भाषा में बोलते हैं, जैसे कोई विरोधी आदमी बोल रहा हो । बहुत मासूमियत के अंदाज़ में उन्होंने कहा कि आय चली कहां गई। सरकार के पास मशीनरी है और वह इसका बड़ी आसानी से पता लगा सकती है। इसका बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि लम्बी लम्बी रकमें कर्ज़ के रूप में किन को दी गई हैं, दूसरे ढंग से सुविधायें कल कारखाने चलाने की किन को दी गई हैं। यह सारी जानकारी तो प्रधान मंत्री जी और सरकार के पास होनी चाहिये। उनको इतने मासूम ढंग से सवाल नहीं पूछना चाहिये कि पैसा कहां चला गया।

सरकारी आंकड़ों से प्रगति का पता चलता है । माना कि ४.८ रुपये प्रति व्यक्ति प्रगति हुई है । लेकिन इस प्रगति का आप पड़ोस के अन्य देशों में हुई प्रगति से मुकाबला करें। चीन के साथ मुकाबला करें, घाना के साथ करें। चीन में ६०--७० रुपये प्रतिव्यक्ति और घाना में २५ रुपये प्रति व्यक्ति और हमारे यहां ४.८ ही यह है। इसको क्या हम कहें कि प्रगति हुई है या कि हम अधोगति की ओर जा रहे हैं।

हमारी जो योजना है वह नौकरशाही पर आधारित है । जब तक इस में आमूल परिवर्तन नहीं किया जाता है, हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं निकल सकता है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खाद्य समस्या का भी जिक्र किया है और एक जुमला उन्होंने कहा कि आम तौर पर से खाद्य समस्या बिल्कुल सन्तोषजनक है । इस सदन के माननीय सदस्य अपने अपने गांवों और शहरों के रहने वाले लोगों को देखें और देखें कि वे कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और उस के साथ इस जुमले की तुलना

करें तो यह कहा गया है कि बिल्कुल सन्तोषजनक है, यह सत्य है कि या असत्य, इसका पता उनको चला जाएगा, पचास साठ लाख लोग जिनका मैंने जिक्र किया कि वे दूसरे लोगों से भिन्न भिन्न हैं, उनका भोजन, भवन भाषा, आदि भिन्न है, उनके लिये अगर इस जुमले का प्रयोग किया गया हो तो मैं कहता हूं कि यह बिलकुल सत्य है लेकिन अगर इस देश की ४३ करोड़ आबादी के बारे में कहा गया हो तो इस में सच्चाई नहीं है । इस देश में दस करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनको केवल एक बार भोजन करने को मिलता है । दो बार भोजन वाले जो लोग हैं, वे भी क्या खाते हैं, उस भोजन की शक्ति और मात्रा के हिसाब से देखा जाय तो उनको भी दाल भात, भात दाल ही मिलता है तथा दूसरी जिन्दगी की आवश्यक वस्तुयें नहीं मिलती हैं। राष्ट्रपति जी इसको सन्तोषजनक बताते हैं। पंद्रह वर्ष बीत चुकने पर भी इस बारे में कोई सही कदम नहीं उठाया गया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गए प्रयासों की अकसर चर्चा होती रहती है । मगर मैं निवेदन करना चाहत हूं कि अगर आप समस्या हल होते देखना चाहते होते, तो आपको चाहये था कि जमीन का आप वितरण कर दें दे, जो गलत ढंग से भूमि का वितरण हुआ है, फर्जी बटवारे किये गए हैं, उनको आप रद्द करते, बंजर जमीन को तोड़ा जाता और इस देश में बेकार जो व्यक्ति हैं और जिनकी संख्या काफ़ी बड़ी है, उनको उस जमीन को दिया जाता , उन के परिश्रम का लाभ उठाया जाता, सिंचाई की छोटी योजनायें चालू की जातीं। सस्ता पानी दिया जाता और जो अलाभकर जोते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होता है, उन को लगान से मुक्त किया जाता। यदि ऐसा किया गया होता तो मेरा निश्चित मत है कि इस देश की खाद्य समस्या हल हो गई होती और इस समय योजना की जो स्थिति है वह हमारे सामने न होती। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गोंडा जिले का कुछ इलाका आता है । घाघरा नदी के किनारे का वह इलाका है । मैं यकीन दिला कर आपको कहना चाहता हूं कि और सदन के माननीय सदस्यों और खुद प्रधान मंत्री जी को जिन्होंने देश का और गांवों का अपने दिमाग में बहुत अच्छा नक्शा बना लिया है और समझते हैं कि नक्शा बहुत अच्छा बन गया है, कहना चाहता हूं कि वे मेरे साथ चलें और देखें कि किस तरह से लोग वहां पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह के उनके मकान हैं, क्या वे खाते हैं। जब वे इस चीज़ को देख लेंगे तो उनको पता चलेगा कि खाद्य समस्या का हल निकल आया है या नहीं ।

आज सब से बड़ी समस्या, मुख्य समस्या, जिसको हमें हल करना है, महंगाई की है । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसकी कोई चर्चा नहीं है । महंगाई को रोकने की कोई कार्रवाई भी सरकार की तरफ से नहीं की गई है । आज हिन्दुस्तान के जनसाधारण, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग यह सभी लोग महंगाई से त्रसित और पीड़ित हैं । महंगाई सब से बड़ी राक्षसी है, इस देश की । लेकिन राष्ट्रपति ने इस की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया । शायद उन्होंने इस को जरूरी नहीं समझा होगा । लेकिन महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इस के लिये मैं कोई दूसरी मिसाल नहीं दूंगा, अलावा इस के कि मैं सरकार का ध्यान सरकार के मंत्रियों के निर्णयों की ओर खींचूं। जब सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया तो उस ने यह मान लिया कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन उस को रोकने का कोई प्रयास नहीं है । दाम कैसे स्थिर किये जायें या निश्चित दाम नीति कैसे अपनाई जाय, इस की चर्चा राष्ट्रपति जी ने नहीं की ।

मैं केवल इतनी ही बात नहीं कहूंगा कि महंगाई को दूर किया जाना चाहिये, मैं कुछ सुझाव भी रखना चाहूंगा। अगर सरकार चाहती है कि निश्चित दाम नीति चले तो मैं उस के सामने तीन बातें

[श्री रामसेवक यादव]

रखना चाहूंगा । अगर वे चीजें हो जायें तो इस देश के अन्दर जो राक्षसी कीमतें बढ़ रही हैं उन से छुटकारा मिल सकता है (१) अनाज का मूल्य क्या हो ? किसी भी अनाज के मूल्य में दो फसलों के बीच में १ आ० सेर से अधिक फर्क नहीं होना चाहिये । (२) कारखाने में बनी जनोपयोगी वस्तुओं का मूल्य लागत खर्च से डेढ़ गुने से अधिक किसी दशा में न हो । उदाहरण के लिए चीनी, कपड़ा, मिट्टी का तेल आदि । तपेदिक की दवा स्ट्रेप्टोमाइसीन है जो कि सरकारी कारखाने में बनती है, उसकी लागत २ आ० के करीब पड़ती है, लेकिन बाजार में वह १२ आना, या १ रु० ४ आ० की बिकती है और चोरबाजारी से १ रु० ८ आ० तक बिकती है । इस को ठीक करना चाहिये । (३) इसी तरह से कच्चे माल और अनाज की कीमत क्या है, साथ साथ मुनाफा भी इतना मिले कि लागत खर्च निकल आये और बनाने वालों का जीवन निर्वाह हो सके । अगर यह तीन बातें कर दी जायें तो इस देश को महंगाई से छुटकारा मिल सकता है ।

श्री बु० र० पटेल (पाटन) : क्या आपने इसका अनुमान लगाया है कि किसान को कितनी लागत आती है ?

श्री राम सेवक यादव : बतलाऊंगा, घबराइये नहीं । फर्क पड़ गया है । और दूरी हो गई है हमारे और आप के बीच में ।

एक माननीय सदस्य : आप दूर हो गये या यह दूर हो गये ?

श्री राम सेवक यादव : अब मैं दूसरी बात की ओर आप का ध्यान खींचना चाहूंगा । मैं यह कह सकता हूं कि हमारे इस सदन के माननीय सदस्य, मंत्री और खास तौर पर उपराष्ट्रपति जी जब पद ग्रहण करते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं । हम सदस्यों ने भी शपथ ली है । उस में जो आर्टिकल ३५१ है उस के सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, मैं इस का लेखा जोखा नहीं चाहूंगा, न उस पर विचार करूंगा । लेकिन सदन के सामने विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि क्या कभी उपराष्ट्रपति जी ने यह प्रयास किया कि वे हिन्दी में बोलें ? मैं समझता हूं कि आज १० या १२ वर्षों से वे इस पद पर हैं । अब तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ?

इसी तरह से संविधान का अनुच्छेद ४५ है जिस में १४ तक के लड़कों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है । आज हम देखते हैं कि इस की ओर भी कुछ नहीं हो पा रहा है । जब तक इस देश के नागरिकों को शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक लोकतन्त्रात्मक समाजवाद स्थापित हो पायेगा या नहीं, इस में सन्देह है । जहां तक शिक्षा नीति का प्रश्न है, आज इस देश में दोहरी शिक्षा चलती है । एक तरफ देहरादून, ऊटी और नैनीताल में पब्लिक स्कूल हैं और दूसरी तरफ म्यूनिसिपैलिटी, कारपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल हैं । एक तरफ १००, १५०, २००, ५०० रु० तक लेने वाले स्कूल और दूसरी तरफ १ रु० ४ आ० लेने वाले स्कूल । इस तरह से दो तरह के नागरिक गढ़े जा रहे हैं । एक तरफ मालिक लोगों का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ गुलाम लोगों का निर्माण हो रहा है । क्या हम इस तरह से दोहरी शिक्षा के माध्यम से देश को उठा सकते हैं ? क्या इस रास्ते पर चल कर हम मुल्क को आगे बढ़ा सकेंगे ? इसमें मुझ को सन्देह है । मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की प्रणाली को समाप्त किया जाय । प्रधान मंत्री की बेटी के बेटे, मंत्रियों के लड़के और बड़े बड़े आदमियों के बेटे आज बैठें गरीब से गरीब आदमियों के बच्चों के साथ । जब इस तरह से होगा तभी भावनात्मक एकता पैदा होगी,

†मूल अंग्रेजी में

तभी नैशनल इंटेग्रेशन होगा। आज जो धारा चल रही है, जो कुछ आज सरकार की नीति है उससे देश में एकता नहीं होगी। एक जगह पर मालिक लोगों को आप बनायेंगे और दूसरी जगह पर गुलामी हिन्दुस्तान में बनी रहेगी।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पंचायती राज के निर्माण के बारे में कहा था। इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद ४० में कहा गया है कि: राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों। सारे देश के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पंचायत राज कानून और उस की जो कार्य विधि है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यह जो पंचायतें हैं वह सेल्फ गवर्न्ड बन सकती हैं या नहीं। मैं इसका उदाहरण रखना चाहता हूं। गांव का सब से छोटा सरकारी कर्मचारी होता है चौकीदार। जो जमीन इत्यादि के आंकड़े रखता है, लोगों के कब्जे का इन्द्राज रखता है, उसे कहते हैं लेखपाल। लेकिन गांव की पंचायत का प्रधान जो है उसको कोई अधिकार नहीं है कि वह लेखपाल या चौकीदार को स्थानांतरित कर सके, या उस पर कोई कार्रवाई कर सके। मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप पंचायतों को किस तरह से शासन की इकाई बना रहे हैं। उनको अपने गांव के बारे में कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं। वह सारे अधिकार राज्य सरकार के हाथ में हैं। न खजाने में उनका कोई हिस्सा, न सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण और न कानून बनाने में उनको हां या ना का कोई अधिकार। यही नहीं कि उनको कोई अधिकार नहीं है, उनकी स्थिति आज वैसी ही है जैसे कि हमारे देश में वर्णाश्रम है। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शुद्र जिस तरह से होते हैं उसी तरह से हमारे लोक सभा के सदस्यों का सम्मान अधिकार ज्यादा, विधान सभा के माननीय सदस्यों का सम्मान अधिकार ज्यादा। यह द्विज पंच हैं। जिला परिषद् जो है उसके पंच प्रधान शूद्र और गांव पंचायत के पंच और प्रधान हरिजनों की तरह से हैं जिन के साथ सरकारी नौकरों का व्यवहार वैसा ही है। यह है जिस तरह हम शासन की इकाई उनको बना रहे हैं।

इसी तरह से निःशस्त्रीकरण की बातचीत का भी राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया। मैं समझता हूं कि ईसा से महात्मा गांधी तक के हथियार बूढ़े रहे हैं, और अब उद्जन बम बनाने के बाद तो वह बिल्कुल बेकार हो गये हैं। अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाय तो उनका इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा, खास तौर से रूस और अमरीका की जनता शायद उन के खिलाफ विद्रोह भी करेगी क्योंकि वह बहुत खर्चीले और बेमतलब हैं। मैं प्रधान मंत्री और भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ख्रुश्चेव और कैनेडी को शिखर वार्ता के लिये तैयार करें ताकि संसार में जो सब से बड़ा अन्याय गरीबी है उस गरीबी को कैसे दूर किया जाय इस पर विचार किया जा सके और किसी सच्ची व्यवस्था और आजादी का निर्माण हो सके तथा प्रगति हो सके।

श्री चन्द्रिकी (रायचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पहली बार मैं इस संसद् में अपने विचार रख रहा हूं इसलिये इस अवसर पर मैं उचित समझता हूं कि जिन मतदाताओं ने मुझे चुन कर यहां भेजा है, मैं उनका हृदय से अभिनन्दन करूं।

दूसरी बात यह है कि हमारे राष्ट्रपति ने पहले अपना अभिभाषण हिन्दी में पढ़ा। इसी लिये साउथ का होते हुए मैं भी इस में अभिमान पाता हूं कि अपने विचार मैं पहली मर्तबा इस संसद् में हिन्दी में रखूं।

मुझे बहुत से माननीय सदस्यों के विचार सुनने का अवसर मिला है। इस अभिभाषण को जब मैं देखता हूं तो इस के तीन विभाग हो सकते हैं। एक है, इस भारत सरकार की नीति अन्तर्राष्ट्रीय

[श्री चन्द्रिकी]

रंगमंच में, दूसरा है राष्ट्रीय दृष्टि से भारत सरकार की जो नीति देश के अन्दर चलती है और तीसरा विभाग है जो कि राष्ट्रपति जी ने अपनी निजी बात के सम्बन्ध में कही है । पहले मैं कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच में जो भारत सरकार की सेवायें रही हैं पिछले १४ सालों से उनपर हम सब को गर्व है, अभिमान है । और इस के कर्ता धर्ता भारत के महान् नेता हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी हैं । इस का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है । आज हम किसी दृष्टि से भी देखें, सारी दुनिया में शान्ति स्थापन करने के सम्बन्ध में भारत ने अपनी शक्ति से बढ़ कर सेवा की है ।

कामन वैल्थ की दृष्टि से देखें, जहां कि गोरे और काले का प्रश्न आता है, वहां भी भारत सरकार और भारत के प्रधान मंत्री ने बड़ी दृढ़ता से और अपनी अतीव शक्ति बताते हुए गोरों को भी बताया कि काले पीछे नहीं रह सकते और साउथ अफ्रीका को कामन वैल्थ से निकल जाना पड़ा ।

यूनाइटेड नेशन्स की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम को मालूम होता है कि शान्ति के सम्बन्ध में वहां हमारे प्रधान मंत्री के साथ श्री कृष्ण मेनन ने जो सेवाएं की हैं वे अपूर्व हैं और हम उनको भूल नहीं सकते ।

धार्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थल हैं । हमारे देश में अनेकों यात्रा स्थल हैं । राजकीय रंग में भारत देश विदेशियों के लिये यात्रा स्थल बना हुआ है ।

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति को इस बात का श्रेय है कि दूसरे राष्ट्रों के महान राज नेता भारत की यात्रा पर आते रहते हैं और भारत आकर भारतीय संस्कृति को, भारतीय नीति को और भारत ने जो प्रगति की है उसको देखते हैं । वह देखते हैं कि किस प्रकार भारत ने प्रजा प्रभुत्व की नीति को स्वीकार किया है और उसपर चल रहा है । इससे वह बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वह इस बात से बहुत सन्तोष प्राप्त करते हैं कि भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ऐसी महान प्रगति कर रहा है । जब श्री चाऊ एन लाई भारत आये थे उस वक्त यह नारा बड़े जोर से लगाया गया था कि हिन्दी चीनी भाई भाई । अब यह कम हो गया है जिसके कारण हैं । उस यात्रा के समय श्री चाऊ एन लाई बंगलौर गये थे जहां उनको एक पार्टी दी गई थी । मुझे याद है कि उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज को मान लिया था कि भारत ने प्रजा प्रभुत्व की नीति को धारण करते हुए भी चीन से जहां डिक्टेटरशिप है दस वर्ष में ज्यादा प्रगति की है । यह कोई आसान चीज नहीं है और इस पर हम गर्व कर सकते हैं । इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय रंग की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि भारत ने अपनी शक्ति से बढ़ कर प्रयत्न किया है जिस पर कि हमको गर्व करने का मौका है ।

जब राष्ट्रीय रंग की दृष्टि से मैं भारत सरकार की सेवाओं पर विचार करता हूं तो मैं देखता हूं कि हमें **अभी** बहुत से क्षेत्रों में काम करना है । मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम इन १४ सालों में सोते ही रहे और हमने कोई काम नहीं किया जो जनता के हित की दृष्टि से अच्छा समझा जा सकता है ।

इसके बाद मैं दो मोटी मोटी चीजें नीति के बारे में इस सदन के सामने रखना चाहता हूं ताकि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में विचार करे ।

एक बात तो सब से बड़ी मैं यह मानता हूं कि जो शिक्षण प्रणाली हमारे देश में, एक स्वतंत्र देश में, होनी चाहिए, वह प्रणाली धारण नहीं की गयी है । यह मुझे कहना पड़ेगा । हमें इसका

अनुभव है कि जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की उस वक्त जो छोटे छोटे लड़के थे वह भी बड़े उत्साह के साथ, आनन्द के साथ और गर्व के साथ जय जय कार के नारे लगाते थे। आज वह बच्चे बालिग हो गये हैं और मतदाता बन चुके हैं। मगर हम देखते हैं कि बालिग और मतदाता बनने के बाद वे केवल टीका ही टीका करते हैं कोई चीज रचनात्मक दृष्टि से सामने नहीं रखते। मैं समझता हूं कि इसमें हमारे उन मतदाताओं का दोष नहीं है। अगर किसी का दोष है तो शिक्षा प्रणाली का। हमने ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं अपनाई है जो हमारे बच्चों में देशाभिमान जागृत करे, जो उनमें स्वाभिमान जाग्रत करे और उनमें देश सेवा की भावना पैदा करे। हमारे शिक्षण क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं वे इस बारे में एकमत नहीं हैं। कभी वह कहते हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिएं, कभी कहते हैं कि नहीं होनी चाहिएं। अभी हमारे सामने हिन्दी और अंग्रेजी का प्रश्न है। इसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेज का भी सवाल है। यूनीवरसिटी में किस भाषा में पढ़ाना चाहिए यह भी प्रश्न हमारे सामने है। तो मेरा कहना है कि आप किसी भी भाषा में पढ़ाएं लेकिन उस शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की जो बुनियादी बात है वह अवश्य होनी चाहिए अर्थात् उस शिक्षा से विद्यार्थियों में देशाभिमान जागृत होना चाहिए, उनका स्वार्थ निकलना चाहिए, उनमें देश सेवा की भावना पैदा होनी चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमको लाना चाहिए यह मैं आपसे यहां कह देना चाहता हूं। ऐसा न होने के कारण हम आज दस साल से नुकसान उठा रहे हैं। आज भी देश सेवा की दृष्टि से जो विचार धारा विद्यार्थियों में होनी चाहिए वह हम नहीं पाते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र इस ओर ध्यान देना चाहिए।

एक और बात देश के सामने है। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद हम सभी की यह ख्वाहिश है कि देश से निर्धनता निकल जाए, देश से बेरोजगारी चली जाए और सभी को रोजगार का सुयोग प्राप्त हो और सभी सोचें कि हमको रोजगार मिल सकता है। हम देखते हैं कि एक तरफ तो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हमको बेरोजगारी की समस्या को हल करना है। इसमें शक नहीं कि पंचवर्षीय योजनाओं की दृष्टि से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है और बेरोजगारी की समस्या को किसी हद तक हमने साल्व भी किया है। मगर उसकी सीमा है। जब मैं पंचवर्षीय योजनाओं को देखता हूं और बेरोजगारी पर सोचता हूं तो यह एक अनएंडिंग चीज दिखायी देती है जिसका साल्यूशन नहीं मिलता। चाहे हम कुछ उद्योग खोलकर आठ दस हजार लोगों को नौकरी दे दें लेकिन यह कोई हल नहीं है। बेरोजगारी तो एक परमानेंट चीज है और इसका हल परमानेंट होना चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र के लोग यूनीवरसिटियों और स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद और जो अनपढ़ हैं वे भी रोजगार प्राप्त कर सकें और यह सोच लें कि हमें देश में किसी के सामने नौकरी के लिये दीन नहीं होना पड़ेगा लेकिन मर्यादा के साथ जो भी काम हम कर सकते हैं वह हमको मिल जाएगा। तो यह चीज उनके सामने होनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में जब मैं सोचता हूं तो मुझको कहना पड़ता है कि हमारी सरकार को अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी को बदलना चाहिए। बड़े बड़े राष्ट्रों के एक्सपर्ट आकर कहते हैं कि हिन्दुस्तान की इंडस्ट्रियल पालिसी में तबदीली होनी चाहिए, हिन्दुस्तान में काटेज इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और बड़ी इंडस्ट्रीज में डिमारकेशन होना चाहिए। इन तीनों प्रकार की इंडस्ट्रीज में किस प्रकार काम होना चाहिए इसका निर्णय होना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा तब तक यह संघर्ष इसी तरह कायम रहेगा। काटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बिग इंडस्ट्रीज का मुकाबला नहीं कर सकतीं। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस चीज का डिमारकेशन करना चाहिए कि कौन कौन चीजें स्माल स्केल और काटेज इंडस्ट्रीज में बननी चाहिएं और कौन कौन सी चीजें बिग इंडस्ट्री में। आज चूंकि हम सबसिडी देते हैं इसलिए खादी और हैंडलूम जिन्दा हैं मगर हम यह सबसिडी हमेशा नहीं दे सकेंगे। इसलिए जब हम खादी को चाहते हैं और हैंडलूम को और दूसरी चीजों को चाहते हैं तो हमको निर्णय करना होगा कि बिग इंडस्ट्रीज जो

[श्री चन्द्रिकी]

हैं उनको किस प्रकार काम करना चाहिए। जब तक हम बिग इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल और काटेज इंडस्ट्रीज के बीच में कोई डिमारकेशन नहीं डालेंगे तब तक कोई साल्यूशन नहीं निकल सकता। और जो आपकी इंडस्ट्रियल पालिसी है जब तक उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक उससे अनएम्पलायमेंट का प्राबलम हल नहीं हो सकता।

अन्त में केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। सत्य पथ पर चलने वाले के प्रतीक हैं और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रतीक हैं। भारतवर्ष में जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और जो भी देश सेवक हैं वे राष्ट्रपति जी को इस उच्च पदपर देखकर अभिमान करते हैं और समझते हैं कि जब कहीं सत्यपथ पर चलने वाले और निष्ठावान देश सेवको को अपने काम में धक्का पहुंचेगा तो राष्ट्रपति जी से उनको सहायता मिलेगी। ऐसी उन लोगों को आशा है। हमारे राष्ट्रपति जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में देश की सेवा की और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राजकीय रंग में देश की सेवा की। इन तमाम दृष्टियों से उनका देश में एक बहुत ऊंचा स्थान है। जो भी सरकार की नीति में त्रुटि पाई जाती थी उसके लिए कभी कभी सरकार को चेतन करने में भी उन्होंने पैर पीछे नहीं हटाया। खासकर हमने देखा कि इस शिक्षण प्रणाली के सम्बन्ध में जब स्ट्राइक्स होते थे, अशान्ति होती थी और युनिवर-सिटीज के विद्यार्थियों में जो एक प्रकार की खलबली मचती थी तो उसपर भी वह अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करते थे। सही मायने में हमारे शिक्षण में कुछ दोष अथवा त्रुटि है ऐसा उन्होंने कभी कभी अपना विचार प्रकट किया है। इस किस्म के विचार प्रकट करने और रखने वाले ऐसे निष्ठावान व्यक्तियों की हमारे देश में बड़ी आवश्यकता है। खासकर भारतीय संस्कृति के आधार पर जो इतना महान व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों की हमारे देश में बड़ी कमी है। बस इतना कह कर और राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का सम्पूर्णतया समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : मैं श्री माथुर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हम अपने देश में एक प्रजातंत्रात्मक और समाजवादी समाज कायम करना चाहते हैं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि हमने जो सफलताएं प्राप्त की हैं, वह हमारे लिये गर्व का विषय है। किन्तु यह भी नहीं समझना चाहिए कि कोई त्रुटियां नहीं हैं।

हमारी योजना का एक लक्ष्य यह है कि सब प्रदेशों का समान रूप से विकास हो। मैं यह नहीं कहता कि दक्षिण या केरल के साथ जानबुझ कर विभेद किया गया है, किंतु भावना यही है कि केरल की समस्याओं पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया। पहली दो योजनाओं में देश के विभिन्न भागों में कई परियोजनाएं शुरू की गई थीं, किन्तु केरल में एक भी नहीं। कुछ चिन्ताजनक खबरें आ रही हैं कि जल-रासायनिक उद्योग जो केरल में स्थापित किया जाना था, अब दूसरे स्थान पर बनाया जायेगा।

छोटे उद्योगों के बारे में मेरा सुझाव है कि नारियल और अन्य उद्योगों में नये तरीके अपना कर सुधार किया जाना चाहिए। रबड़, इलायची, चाय आदि उद्योगों को अधिक महत्व देना चाहिये, क्योंकि इन बागान उद्योगों से विदेशी मुद्रा की बहुत आय होती है। गरम मसालों की फसलें बीमारियों द्वारा खराब हो रही हैं किन्तु सरकार कोई सहायता नहीं दे रही। कुछ मास पहले इनके सम्बन्ध में एक समिति स्थापित की गई थी, किन्तु अभी तक उसकी कोई बैठक नहीं हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

म जानना चाहूंगा कि उस समिति का क्या हुआ है। केरल सरकार ने जो पृथक् राज्य व्यापार निगम स्थापित करने का सुझाव दिया था, उस की ओर भी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया।

नारियल बागानों में काम करने वाले लोगों की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया। सरकार को रबड़, नारियल आदि वाणिज्यिक फसलों को अधिक महत्व देना चाहिये और केरल की खाद्य की आवश्यकताएं केन्द्र द्वारा पूरी की जानी चाहिये। मद्रास और केरल राज्यों में बागानों के करों में जो अन्तर है, वह दूर किया जाना चाहिये।

दो वर्ष पूर्व केरल में जो बैंक संकट पैदा हुआ था, उसके बारे में वित्तीय ढांचे में संतुलन कायम करने के लिए कुछ नहीं किया गया।

केरल में उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत सी अच्छी चीजें हैं। बिजली बहुत सस्ती पैदा की जा सकती है जिससे बहुत से उद्योग चल सकते हैं। मैं इड्डिकी का उदाहरण देता हूं। इस परियोजना में विलम्ब नहीं होना चाहिये। मेरा एक और सुझाव यह है कि केरल के लोगों को अन्य स्थानों को प्रव्रजन करने की सुविधाएं देनी चाहियें। देश में बहुत से स्थान हैं, जहां जनसंख्या इतनी घनी नहीं है, जितनी केरल में है।

†**श्री ह० न० चटर्जी** (नवद्वीप): इस समय देश की सब से बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय एकता है। किन्तु इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी अपराधी सरकार स्वयं है। उसने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। पहली बात यह थी कि उसे प्रान्तीयतावाद और प्रादेशिक भाषावाद को रोकना चाहिये था। जब हमारे एक निकटवर्ती राज्य ने सीमान्त पर रहने वाले लोगों पर एक भिन्न भाषा थोपनी चाही थी, तो केन्द्रीय सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और इस तरह संविधान का उल्लंघन किया।

सरकार ने और भी गलतियां की हैं। कांग्रेस शुरू से ही भाषावार प्रान्तों के हक में रही है। मेरा आरोप यह है कि सरकार ने भारत की एकता के विरुद्ध काम किया है।

सरकार भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर रही है। मैंने आसाम की घटनाओं का अध्ययन किया है। सदन में आश्वासन दिया गया था कि एक न्यायिक जांच की जायेगी। किन्तु यह अभी तक नहीं हुई।

अब मैं विस्थापित व्यक्तियों की समस्या को लेता हूं। यद्यपि यह समस्या हल नहीं हुई फिर भी पुनर्वास मंत्रालय बन्द कर दिया गया है। यदि आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जायें, तो आपको लाखों विस्थापित व्यक्ति मिलेंगे। धुबूलिया में जो ७०० परिवार हैं उनकी दशा दयनीय है। उन के लिए पानी का केवल एक नलकूप है। नहाने के लिए उन्हें दो मील दूर जाना पड़ता हैं।

पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वहां अल्पसंख्यक वर्ग का एक भी व्यक्ति नहीं रह सकेगा। वहां से उन्हें धकेला जा रहा है। ५० लाख बंगाल में आ चुके। उन को देखभाल न करना पाप होगा। उनके लिए हमें और भूमि मांगनी पड़ेगी।

पूर्वी बंगाल के साथ हमारा ८०० मील लम्बा सीमान्त है। मैंने स्वयं १०० मील का दौरा किया है और मैं ने देखा है पटसन, पान, बीड़ी और अन्य वस्तुओं का चौर्यानियन बड़े पैमाने पर हो रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। डकैतियां और हत्याएं भी हो रही हैं। इन घटनाओं को रोकना हमारा कर्तव्य है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ह० न० चटर्जी]

अब मैं भारी प्रशासन व्यय की ओर आप का ध्यान दिलाऊंगा। १९५०–५१ में कुल विकास से अतिरिक्त राजस्व व्यय ३१४.२१ करोड़ था किन्तु १९६१–६२ में यह ६०४.४६ करोड़ रुपये अर्थात् दुगने के करीब हो गया है। मंत्रियों आदि की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

मैं श्री सिब्बी के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि राजनीतिज्ञों की दौलत की जांच होनी चाहिये। हमें भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना चाहिये।

श्री गु० सि० मुसाफिर (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बेशक राष्ट्रपति जी का जो इस दफा का अभिभाषण हैं वह बहुत मुख्तसर है। मगर फारसी का एक मुहावरा है।

"दर्चे बकामत केहतर बकीमत बेहतर"

जो चीज साइज में छोटी होती है वह गुणों के लिहाज से बेहतर होती है और अच्छी होती है। वैसे जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के १५वें पैरे में कहा है :

"इस उच्च पद को स्वीकार करने से पहले, संसदीय जीवन और उस के कर्तव्यों का भी मुझे कुछ अनुभव रहा है।"

यह ठीक है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह हमें सिफ़त मौसूफ हैं, वह गुणों के मुजस्सिमा भी हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि वह जब हमारा कांस्टिट्यूशन बना तो उस कांस्टिट्यूएन्ट असेम्बली के प्रधान थे। उन की देख रेख में हमारा सेकुलर संविधान बना और काफी सालों तक उन की देख रेख में इस संविधान को सफलता के साथ चलाया गया। राष्ट्रपति जी ने अपनी इस छोटी सी स्पीच में तकरीबन तमाम बातों का, जिन का मुल्क की तरक्की के साथ सम्बन्ध है, और जो जो काम हमारी सरकार ने इन सालों में किये हैं उन का जिक्र अच्छी तरह से किया है। इस में कोई शक नहीं है कि माद्दी लिहाज से हमारे देश ने पिछले सालों में काफी तरक्की की है। यह फिगर्ज यहां देने की जरूरत नहीं है। आप और सब मेम्बरान साहबान तो वक्तन फवक्तन मुताला करते रहते हैं आप देखेंगे कि हर लिहाज से, ख्वाह प्रोडक्शन के लिहाज से ख्वाह दूसरी बातों के लिहाज से, हमारे देश ने काफी तरक्की की है। मैं पंजाब से आता हूं, मैं देखता हूं कि पंजाब के अन्दर हर तरफ तरक्की हो रही है। अगर किसी मेम्बर साहब को इस का यकीन न हो तो वह चंडीगढ़ में जा कर देखें। लुधियाना में जो होजियरी और दूसरी इन्डस्ट्री की तरक्की हुई है उस को देखें। सोनीपत जो यहां से नजदीक है वहां पर जो ऐटलस साइकल का कारखाना है उस का मुलाहजा फरमायें। ये तो बिल्कुल छोटी बातें हैं। आलराउंड हम देखते हैं कि हमारे मुल्क ने काफी तरक्की की है। एक मेम्बर साहब ने कहा कि तरक्की की बात तो करते हो, दूसरे मुल्कों से मुकाबला कर के देखो। तो मैं बिना संकोच के कहता हूं, और दूसरे मूल्क भी कायल हैं, कि हालांकि आजादी के लिहाज से हमारी उम्र बहुत छोटी है लेकिन हम ने बहुत तरक्की इन सालों में की है। उस अर्से के साथ मुकाबला करके देख लिया जाए तो दूसरे मुल्क भी यह बात मानते हैं कि इतने अर्से में दूसरे मुल्कों ने इतनी तरक्की नहीं की है जितनी कि आजादी के इन थोड़े से सालों में हमारे देश ने तरक्की की है।

सन् १९५४ में मैं रूस गया तो लेनिनग्राड के एक मजदूर ने मुझसे बड़े जोश से कहा था कि आप क्यों ऐसी बात करते हैं कि आपका मुल्क पीछे है। इतने सालों में जो आपने तरक्की की है वह रूस भी नहीं कर सका क्योंकि अभी आजादी के बाद आपको अरसा बहुत कम मिला है।

तो मेरा कहना यह है कि हमारे किसी पार्लियामेंट के मेम्बर का यह कहना कि दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला करके देख लें, यह चिराग के नीचे अन्धेरे वाली बात है। उन्हें पता नहीं कि दूसरे मुल्क हमारे देश के मुताल्लिक क्या कहते हैं।

खैर, मैं आज एक खास बात की तरफ तवज्जह दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। माद्दी लिहाज से हमने जरूर तरक्की की है, मगर एक पहलू हमारा बहुत कमजोर है और उसका इकबाल इस वक्त हमारे महबूब नेता भी करते हैं। दूसरे लोग भी जो देश के हमदर्द हैं वह इस बात का इकबाल करते हैं कि इखलाकी लिहाज से कुछ न कुछ हमारी जो कमियां हैं वे ठीक नहीं हो सकी हैं। इखलाक से मेरा मतलब यह है कि कौमी यकजहती के मामले में जरूर इस वक्त भी हम कमजोर हैं। यह बीमारी हमारे अन्दर अगर मौजूद न हो तो हमारे बेहतरीन डाक्टर जो इसका इलाज कर सकते हैं—पंडित जवाहर लाल नेहरू से मेरी मुराद है—वह अलऐलान जलसों में और अपनी स्पीचों में इसको कभी न कहें और इतना वक्त वह इस काम पर कभी न दें ?

मेरा कहना यह है कि इस सिलसिले में भी जो कांग्रेस पार्टी है उसने हत्तुलवसा बड़ी कोशिश की है। यानी इस वक्त पिछले भावनगर के सेशन में कौमी एकता के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के काम को बढ़ाने के लिए एक सब कमेटी बनायी गयी, श्रीमती इन्दिरा गांधी उसकी चेयरमैन हैं। उस कमेटी ने पिछले अरसे में काफी मिटिंग्स की हैं, बम्बई में मीटिंग्स की हैं, दिल्ली में और दूसरी जगहों पर उसकी मीटिंग्स हुई हैं। बहुत सी तजवीजें उन्होंने सोचीं और उन पर अमल कराने की कोशिश की। यह पहला कदम था जो भावनगर में कांग्रेस ने एक सब कमेटी बनायी।

उसके बाद पंडित जी ने यानी हमारे प्रधान मंत्री जी ने यहां दिल्ली में एक चार रोजा कानफ्रेंस बुलायी। उन्होंने चार रोज तक और काम छोड़ कर उसकी प्रधानगी की। तमाम पार्टियों के मेम्बर उसमें बुलाये गए और शामिल हुए। उन्होंने अपनी अपनी तजवीजें बतायीं और चार रोज तक गौर किया गया इस बात पर कि हमारे देश में, इस विशाल देश में, हम कौमी यकजहती को किस तरह से रख सकते हैं।

उसके बाद फिर थोड़े रोज हुए कि हिन्दुस्तान भर के लेखकों की एक कानफ्रेंस श्री हुमायून् कबिर जी की अध्यक्षता में हुई और लेखकों ने बैठकर उस कानफ्रेंस में इस मसले पर विचार किया। इस कानफ्रेंस को गवर्नमेंट आफ इंडिया की साहित्य अकादमी ने आरगेनाइज किया था। इस में तमाम मुल्क भर के लेखकों ने इस पर विचार किया कि हम अपने मुल्क में नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह कायम रख सकते हैं।

और काश्मीर में एक कानफ्रेंस हुई जिसमें सिर्फ इस सबजेक्ट पर विचार करने के लिए मुल्क के अच्छे अच्छे लेखक और बोलने वाले बुलाए गए। मैं समझता हूं कि काश्मीर वैसे भी नेशनल इंटीग्रेशन का एक नमूना है। उस वक्त जब कि शुरू शुरू में कबायलियों ने हमला किया था काश्मीर पर तो दूसरे तीसरे रोज ही जाकर मैंने बारामूला की हालत को देखा और मैं ने अपनी आंखों वह जगह देखी जहां नेशनल कानफ्रेंस के एक वर्कर शेरवानी को बांध कर कोड़ों से मार मार कर खत्म कर दिया गया इसलिए कि नेशनल कान्फ्रेंस का कहना था कि चाहे हालात कुछ भी हों, हम देश के सामने यह बात रखना चाहते हैं कि यहां कम्युनलिज्म की बात नहीं चलेगी और कम्यूनल पालिसी की वजह से हम मारधाड़ नहीं होने देंगे। जो भी नेशनल कानफ्रेंस के बड़े बड़े लीडर थे उनका भी सम्बन्ध हिन्दुस्तान की यकजहती के साथ है और इसका क्रेडिट भी मैं समझता हूं कि उसी पार्टी को है जो पार्टी इस वक्त बरसरे इक्तिदार है और जिसने इस वक्त तहैया किया हुआ है कि वह नेशनल इंटीग्रेशन को कायम करके छोड़ेगी।

[श्री ह० न० चटर्जी]

इसके अलावा गवर्नमेंट आफ इंडिया के एजूकेशन डिपार्टमेंट ने श्री सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है जिसका काम है कि वह कालिजों और स्कूलों में यानी तालीमी इदारों में इस बात का खयाल रखे कि हम किस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन कायम रख सकते हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि अगर बच्चों में यानी तालीमी इदारों में यह काम किया जाए तो यह ज्यादा कामयाब हो सकता है। हम जो लोग बड़े हो गए हैं, जो इस वातावरण में पले हैं, हो सकता है कि उनके दिलों में कोई न कोई कमी हो। मगर जो बच्चे हैं जो अभी जवान होने वाले हैं अगर शुरू से ही उनको इस किस्म की तालीम दी जाए तो फिर हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन कायम रह सकता है।

मैं समझता हूं कि कौमी यकजहती एक बुनियाद है। हमारी अपनी तरक्की की बुनियाद है। जरूरी है कि हम गरीब का भला करें, अवाम और जनता की भलाई की बातें सोचें और ऐसे कानून बनाएं और कोशिश करें कि हमारे देश का गरीब अवाम उठे और ऊंचा हो ताकि सही मानों में समझा जाए कि हमारे देश की हालत सुधरी है। इस बात का अहसास लोगों को उसी वक्त होगा जब कि हमारे देश का अवाम खुशहाल होगा। लेकिन कौमी यकजहती के बगैर सारी खुशहाली खत्म हो जाती है। बेशक यह ठीक है कि गरीबी भी दूर हो सकती और दूसरी बुराइयां भी दूर हो सकती हैं और इसके बारे में हमें आशा भी हो सकती है। मगर अगर हमारी बुनियाद गलत हो तो फिर हमारा सुधार नहीं हो सकता। जिस तरह कोई माली जो अपने बाग को प्रफुल्लित करना चाहता है, अगर वह पत्तों को और फूलों को और डालियों को पानी के छींटे देता जाएगा तो उसका बाग हरा नहीं रह सकता। वही माली अच्छा और काबिल समझा जाएगा जो इस तरह पानी देता है ताकि उस बाग की जड़ हरी बनी रहे। अगर किसी वक्त पतझड़ आने की वजह से उस बाग के दरख्तों की पत्तियां सूख भी जाएं तो मौसम बहार आने पर वह फिर सरसब्ज हो सकता है। लेकिन सरसब्ज वही दरख्त हो सकता है जिसकी जड़ कायम है, जो दरख्त जड़ से उखड़ जाता है वह मौसम बहार आने पर भी प्रफुल्लित नहीं हो सकता। जिस दरख्त की जड़ कायम है उसको अगर किसी वक्त खिजां आकर बरबाद भी कर जाए तो वह फिर हरा भरा हो सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जो कविता की एक सतर अब कहना चाहता हूं उसको आप नहीं समझ सकेंगे और शायद और भी बहुत से मेम्बरान नहीं समझ सकेंगे। मैंने पंजाबी में एक गजल लिखी थी वह मौजूदा स्थिति पर ठीक धरती है। उसमें मैंने कहा था :

पतझड़ दे मारे बहारा च निसरन।
बहारां दे मारे कदे वी न मौले॥

यानी जो खिजां का मारा है उस पर तो बहार आ जाती है मगर जो बहार में ही मारा जाता है वह कभी प्रफुल्लित नहीं हो सकता। पानी की मारी हुई खेती फिर प्रफुल्लित नहीं हो सकती। इस वक्त हमें यह समझना चाहिए कि इस मामले में हम सब को यत्न और कोशिश करनी चाहिए। बेशक यह ठीक है जैसा कि दूसरे साइड के कुछ मेम्बर साहिबान ने कहा है। उन्होंने, जो कुछ थोड़ा काम हुआ है, उसका क्रेडिट स्वयं लेने की कोशिश की है। और वह बेशक क्रेडिट लें लेकिन यह क्रेडिट लेने की बात नहीं है बल्कि काम करने की बात है। क्रेडिट लेना बिल्कुल और बात है। यूं तो हमने एलेक्शन में देखा और कई दोस्तो की तकरीरें अपने कानों से सुनीं कि जब गोआ का मामला आया तो वह कहने लगे कि चूंकि अब ऐलेक्शन का वक्त आया है इसलिए

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि गोआ को ले लेना चाहिए लेकिन अभी तक वह बिल्कुल चुप रहे और गोआ के बारे में कमजोरी दिखाते रहे और लिहाज में रहे। मैं ने अपोजीशन के कई मेम्बर दोस्तों को यह कहते हुए सुना कि देखा हम ने तार भेजा और हमारा तार वहां पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद गोआ पर हिन्दुस्तान की फौजों ने चढ़ाई कर दी यानी सारा क्रेडिट उस हमारे तार को है जो कि हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को दिया। उस की वजह से उन्होंने गोआ पर चढ़ाई कर दी और गोआ को फतह कर लिया। इस ऐलेक्शन में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस वाले या बरसरे इक्तदार पार्टी के सभी लोग भले हैं अच्छे हैं और ठीक सोचते हैं और दूसरे सारा ही बुरा सोचते हैं मगर इस इलेक्शन से एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जो कुछ मैं आपको बतलाना चाहता हूं वह कोई अफसाना या कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत है। अभी तक तो मेरा ख्याल यह था कि हमारे देश में कम्युनल पार्टियां मौजूद हैं वह कुछ न कुछ कम्युनलिज्म को बढ़ाने की कोशिश करती ही रहती हैं ख्वाह चुनाव का मौका हो ख्वाह दूसरा मौका हो लेकिन हमारे देश की ऐसी पार्टियां जो कि कम्युनल पार्टीज नहीं हैं जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उन पार्टियों पर मुझे बड़ा भरोसा था। हालांकि मैं ४०–४५ साल का कांग्रेसी हूं मगर कभी कभी मैं किसी किसी कांग्रेसी की बात से बेजार हो जाता हूं तो मन में मैं यह सोचने लग जाता हूं कि यह कम्युनिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ही ऐसी पार्टियां हैं जिनमें और कोई कमी हो तो भले ही हो मगर वह कम से कम कम्युनल नहीं है। इस बात से तो बिल्कुल उन के मन साफ है। लेकिन इस बार चुनावों के दौरान जब मैं अपनी कांस्टीटुएंसी में घूमा तो देखा कि अकाली पार्टी जो कि पंजाब में इलेक्शन के मोके पर कम्युनल फिजा को बढ़ाने के लिए आगे आगे थी, उनका और कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही कैम्प था। कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा और अकाली पार्टी का झंडा एक ही कैम्प पर लहरा रहे थे। चुनावों और वोटिंग में इनका यह गठबंधन मैंने वहां पर देखा ......

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा): जरा अपनी केरल की बात भी तो बतलाइये जहां कि आप की कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाया था।

श्री गु० सिं० मुसाफिर : इस में कोई घबड़ाने की बात नहीं है। मैं किसी मेम्बर या किसी पार्टी के मुताल्लिक कोई ऐसी बात नहीं कहने लगा जिसके लिए कि शोर मचाया जाय। मैं ने तो महज अपने ख्यालात का इजहार किया है। इन पार्टियों का जो विधान है या इस सम्बन्धी बेसिक उसूल हैं वह बड़े ही अच्छे हैं और उनमें कम्युनलिज्म की बात नहीं है। लेकिन मैं तो अमल की बात करता हूं। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि हमारे अमृतसर में एक सज्जन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर खड़े हुए थे मगर अकाली पार्टी के लीडर ने बड़े बड़े जल्से कर के उसकी सपोर्ट में जो कुछ कम्युनलिज्म का प्रचार कर सकते थे वह किया। कहने का मुद्दा यह है कि चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को अकाली पार्टी जो कि एक कम्युनल पार्टी है उसने सपोर्ट किया। अब वह उम्मीदवार चुनाव में कामयाब हुए या नहीं यह दूसरी बात है। पंजाब में और खास कर अमृतसर में अकाली दल आदि जैसी कम्युनल पार्टियों से सांठ गांठ करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने मेरे उस एतकाद को जो मैं उनके बारे में अभी तक रखता था कमजोर किया है ......

उपाध्यक्ष महोदय : ज्ञानीजी, आप का समय समाप्त हो गया है।

श्री गु० सिं० मुसाफिर: बस मैं खत्म किये देता हूं। सिर्फ एक बात है आपकी इजाजत से और कहूंगा ।

नेशनल इंटैग्रेशन का जहां तक सवाल है इसके मुताल्लिक मैं इस मौके पर ज्यादा जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता था। राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने अभिभाषण में इस का कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया है। इस के मुताल्लिक तो मुझे हाली का एक शेर याद आ जाता है :—

"मुसीबत का एक एक से अहवाल कहना, मुसीबत से यह मुसीबत ज्यादा ।"

फिर भी यह एक ऐसी बात है कि इसका जिक्र करना ही पड़ा है। आखिर में मैं अपने अपोजीशन वाले भाइयों से यह अर्ज करूंगा कि आइये हम और आप एक काम तो मिल कर कर लें। इस मौके पर मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत शेर याद आ जाता है और मैं इसी पर अपनी स्पीच खत्म करता हूं :—

"चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है,
हमीं हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो, तो क्या तुम हो ।"

श्री शि० स्वामी (कोप्पल): उपाध्यक्ष महोदय, इस देश पर पिछले १५ साल से जो प्रजा प्रभुत्व की हुकूमत चल रही है उसको हम देखते आये हैं। उस प्रजा प्रभुत्व की सरकार के अध्यक्ष पद पर डा० राजेन्द्र प्रसाद ने गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया हुआ था। यह बात बिल्कुल सही है कि उन के गुण और किरदार इस मुल्क में हर एक सिटीजन से कहीं उंचे हैं। राष्ट्रपति महोदय को मैं उनके अभिभाषण के लिए बधाई देता हूं। लेकिन इतना मैं इस मौके पर जरूर कहना चाहूंगा। इस मुल्क में स्वराज्य प्राप्त करने के बाद जो सही मायनों में नेशनल हुकूमत कायम करना चाहते थे वैसी नेशनल हुकूमत अभी तक देश में कायम नहीं हो पायी है। वैसे कहने के लिए हम कह दिया करते हैं कि हमारे देश मे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई है और इस देश के नागरिक जम्हूरी साये में पल रहे हैं लेकिन अगर सच पूछा जाय तो मौडर्न डेमोक्रेसी के उसूल के मुताबिक यह नेशनल गवर्नमेंट नहीं है बल्कि एक पार्टी गवर्नमेंट है। खुद राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में यह बतला चुके हैं :—

"राष्ट्रपति निर्माण के कार्य की दिन प्रतिदिन की और अन्तिम जिम्मेदारी संसद की है। इस कार्य के लिये आपकी पूर्ण विचार शक्ति, विश्लेषण, रचनात्मक आलोचना सावधानी और समर्पण की क्षमता अपेक्षित है।"

हमारे भाई लोग अक्सर नेशनल इंटैग्रेशन की बातें किया करते हैं लेकिन यह नेशनल इंटैग्रेशन उसी वक्त हो सकता है जब कि मुल्क में नेशनल गवर्नमेंट सही मायनों में हम कायम करे। पार्टी गवर्नमेंट रख कर हम नेशनल इंटैग्रेशन लाने का दावा कैसे कर सकते हैं ? जिस तरीके से एक कम्युनल और रिऐक्शनरी गवर्नमेंट के असरात होते हैं उसी तरह के असरात एक पार्टी गवर्नमेंट से भी पैदा हो रहे हैं। हर एक पार्टी अपनी अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश में है। हर एक पार्टी इस देश को और इस प्रजा प्रभुत्व को अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रही है। जो भी पार्टी इन पावर होती है वह चाहती है कि उसकी हुकूमत हमेशा सेंटर में और तमाम राज्यों में जारी रहे। कांस्टीट्यूशन में कहीं यह जिक्र नहीं है कि किसी एक ही पार्टी भले ही वह मेजारिटी पार्टी हो उसी को गवर्नमेंट बनाने के लिए राष्ट्रपति के यहां से बुलावा आये। सही मायनों में राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए केवल मेजारिटी पार्टी को ही गवर्नमेंट बनाने के लिए राष्ट्रपति

महोदय के वहां से बुलावा आये, कुछ ठीक नहीं जंचता है । कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ७५ में यह दिया हुआ है :—

अनुच्छेद ७५ :

(१) प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की मंत्रणा पर करेगा ।"

(३) मंत्रि-परिषद् लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ;

प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्ज़ सदन के ज़िम्मेदार अशखास और ज़िम्मेदार मेम्बर्ज़ होने चाहिए, लेकिन एक दल की सरकार होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्ज़ एक ही पार्टी से चुने जाते हैं और इसलिए देश में नेशनल इन्टेग्रेशन—राष्ट्रीय एकीकरण—और को-आपरेशन नहीं हो सकता है । जब देश में कोई आर्थिक क्राइसिस पैदा हो या कोई जंग छिड़ जाये, तो सब पार्टियां देश की गुरबत को दूर करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाती है और मिल कर काम करती हैं । लेकिन हम को यह याद रखना चाहिये कि किसी नेशन मे इतहाद और इतिफ़ाक सिर्फ़ बातें करने से नहीं हो सकता है—वह मिल कर काम करने से होता है ।

इस बारे में गांधीजी ने साफ़ तौर पर कांग्रेस वालों को हिदायत की है—जोकि न सिर्फ़ कांग्रेस वालों, बल्कि मुल्क और दुनिया के सामने हैं—कि किस तरीके से कांग्रेस आरगेनाइजेशन और हुकूमत का री-ओरियन्टेशन और सुधार करना चाहिये ? श्री प्यारेलाल ने एक पुस्तक "महात्मा गांधी-दि लास्ट फ़ेज़" लिखी है, जिस में गांधीजी की इस आखिरी इच्छा का ज़िक्र किया गया है । हम न सिर्फ चुनावों मे, बल्कि इस सदन के अन्दर और बाहर, हर जगह गांधीजी का नाम हर रोज़ सुनते हैं । अभी कल ही कांग्रेस पार्टी के नेता, श्री जवाहरलाल नेहरू, ने कहा कि हम गांधीजी के उसूलों पर चल रहे हैं और हम उनके कहने के मुताबिक यहां पर जम्हूरी हुकूमत को आगे बढ़ा रहे हैं । लेकिन क्या में पूछ सकता हूं कि गांधीजी ने मरते वक्त क्या कहा था और उन की लास्ट विल और टेस्टामेंट क्या थी । उन्होंने कहा था कि :—

> "कांग्रेस का अपने वर्तमान रूप में, अर्थात् प्रचार के साधन और संसदीय मशीन के रूप में अब कोई लाभ नहीं रहा । भारत ने अभी सामाजिक, नैतिक और आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है । इसको अन्य राजनैतिक दलों और साम्प्रदायिक दलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिये ।"

गांधीजी ने बताया कि उसका नाम, घटना (कांस्टीट्यूशन), तत्व और सिद्धान्त क्या होने चाहिए । अपने आखिरी समय में उन्होंने श्री प्यारेलाल को यह लिख कर दे दिया कि कांग्रेस को डिज़ाल्व कर देना चाहिए और उसी आरगनाइज़ेशन को लोक सेवक संघ के नाम से चला कर और जिस राजनीतिक पार्टी की हुकूमत है, उसको खत्म कर के इस देश में एक पार्टीलेस डेमोक्रेसी की स्थापना करना ही हमारा फ़र्ज़ है । उन्होंने मरते समय बिड़ला हाउस में अपनी यह मंशा खास तौर पर जाहिर की कि हर एक व्यक्ति को लोक सेवक बनना चाहिए । लेकिन यह कितने दुख की बात है कि उनकी आखिरी इच्छा पर अमल नहीं होता है । लोग गांधीजी के नाम के नारे लगाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं, लेकिन अपने आखिरी वक्त मे उन्होंने पार्टीलैस डेमोक्रेसी को स्थापित करने का जो उसूल सामने रखा, उस पर अमल नहीं किया जाता है । अगर इस देश में हम सब पार्टियों वाले और तमाम नेता सहयोग देकर एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करके मुल्क का काम-काज नहीं चलायगे और इस प्रकार जनता का विश्वास और सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे, तो फिर चाहे किसी भी पार्टी का शासन हो, देश प्रगति नही कर सकेगा ।

[श्री शि० स्वामी]

आज पार्लियामेंट में जितने कांग्रेसी सदस्य और नेता हैं, उन में से हर एक अपने अपने ज़िले और ताल्लुके का राजा और हुकमरान बना हुआ है । जैसे हैदराबाद में मुसलमान राजा समझे जाते थे--मैं माफ़ी चाहता हूं कि "मुसलमान" कह रहा हूं, लेकिन मुसलमान भाइयों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है--जैसे किसी कम्यूनल हुकूमत में उस कम्युनिटी का हर एक व्यक्ति यह समझता है कि वह हुकमरान है, उसी तरह कांग्रेस के एक एक नेता के सामने गुटबन्दी और गुंडागीरी के लोग जमा हो गए हैं और अफ़सर लोगों पर इतना असर है कि मैं चाहता हूं कि हर एक......

श्री चं० ला० चौधरी (महुआ) : आन ए वायंट आफ़ आर्डर, सर। माननीय सदस्य को "गुंडागीरी" का शब्द निहायत अदब से वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वह बिल्कुल अनपार्लियामेंटरी है ।

श्री शि० स्वामी : अगर माननीय सदस्य को इससे तकलीफ़ महसूस होती है, तो मुझे कोई हुज्जत नहीं है, लेकिन मैंने किसी का नाम लेकर गुंडागीरी नहीं कहा, लेकिन आम तौर से ....

श्री बागड़ी : (हिसार) : किसी मेम्बर के बारे में यह नहीं कहा गया था ।

श्री चं० ला० चौधरी : कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसमैन के बारे में कहा गया था ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : माननीय सदस्य के लिये सारे दल को गुण्डा राज कहना उचित है ?

†**श्री उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को ऐसे शब्द प्रयोग में नहीं लाने चाहिये ।

†**श्री शि० स्वामी :** मुझे ये शब्द वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं । मेरे कहने का अर्थ यह था कि दलीय प्रशासन मे गुण्डा गर्दी करने वाले लोग लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं चाहे कोई दल सत्तारूढ़ हो ।

श्री प्यारेलाल ने सफहा ६४६ पर हरिजन के एक लेख का कुछ भाग दिया है --"गांधीजी के सिद्धान्तों के आधार पर ही भारत को वर्तमान प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, किन्तु दुःख की बात यह है कि जिन सिद्धान्तों के बल पर हम इस स्थिति को पहुंचे हैं, उनकी ही आज उपेक्षा की जा रही है।"

†हरिजन में लिखते हुए उक्त आरोपों का उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा था कि

†"एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो रही है"

पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बर्नार्ड शा के क्या विचार थे, इसके बारे में एक लेखक ने कहा है :--

> †"बर्नार्ड शा संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली से सहमत नहीं थे क्योंकि अधिकांश संसद सदस्य दल के चेतक के आदेशानुसार मतदान करते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की भावनाओं का कोई पता नहीं रहता ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** । उनका समय समाप्त हो गया है। उन्होंने १५ मिनट ले लिये हैं ।

†**श्री शि० स्वामी :** मैं अभी खत्म कर रहा हूं ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि जो एक पार्टी हुकूमत है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर सभी पार्टियों के मेम्बरों द्वारा चुने जायें। चाहे वे और मिनिस्टर एक ही पार्टी से लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

जायें, लेकिन जब वे मिनिस्टर बन जायें, पदग्रहण कर लें, तो उन्हें अपनी पार्टी को त्याग देना चाहिये और नेशनल लीडर्ज़ के तौर से मुल्क की तमाम पार्टियों के मैम्बरों को साथ मिला कर उनकी राय पर हुकमत चलायें न कि एक ही पार्टी और एक ही दल की राय से। इसलिए मैं पार्टीलैस डैमोक्रेसी को प्लीड करता हूं और दो जो एमेंडमेंट्स मैंने दी हैं टैक्सेशन और हाई प्राइसिस के बारे में, उनका समर्थन करते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

†**श्री भगवती** (दरांग) : अभिभाषण में ग्रामीण कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है किन्तु महत्व का विषय यह है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये ग्रामीण लोगों में पर्याप्त उत्साह कैसे पैदा किया जाये।

आचार्य विनोबा भावे ने इस सम्बन्ध में बहुत काम किया है। उन्होंने ग्रामदान का आन्दोलन चलाया है। पंचायती राज इसी आन्दोलन के द्वारा लाया जा सकता है। यदि हम प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद चाहते हैं, तो हमें लोगों में यह प्रचार करना पड़ेगा कि वे सामाजिक ढंग से सोचें और सामाजिक ढंग से रहें। इसलिये यह आन्दोलन केवल विनोबा जी पर नहीं छोड़ देना चाहिये। सरकार को भी इसे सफल बनाने के लिये ठोस कदम उठाने चाहियें।

ग्रामदान के प्रकार का एक आन्दोलन औद्योगिक क्षेत्र में भी शुरू करना चाहिये। सरकारी क्षेत्र को बहुत बढ़ाना चाहिये हमें उद्योगों को चलाने के लिये श्रमिक परिषदें भी स्थापित करनी चाहियें। कुछ लोग समझते हैं कि यह अव्यवहार्य सुझाव है। किन्तु आसाम में यह कार्यरूप में सफल हुआ है। वहां चाय बागानों में सहकारी संस्थायें स्थापित करके इसको सफलता मिली है।

श्री स्वैल ने उस दिन आसाम में पहाड़ी क्षेत्रों का एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। मैं समझता हूं कि पहाड़ी और मैदानी लोगों को इकट्ठे करना अच्छा होगा। इन को अलग अलग करने का कोई औचित्य नहीं है। यह समझना गलत है कि आसाम के आदिम जाति लोग मैदानी लोगों से मिल जुल कर नहीं रह सकते।

आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है एकता। अलगाव की बात करना, या झूठ पैदा करना आसान है। एकता करना कठिन काम है।

उस प्रदेश में सीमा की सुरक्षा की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। हिमालय प्रदेश में विदेशी जासूसों और असामाजिक तत्वों की बड़ी सरगर्मी है। अखिल भारतीय राजनीतिक दलों ने सीमा की सुरक्षा के प्रति अपेक्षित सतर्कता नहीं दिखाई है।

आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ की समस्या भी मामूली नहीं है। उस खतरे को दूर करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहियें।

आर्थिक विकास से देश की जनता सन्तुष्ट नहीं है। सभी असमानतायें दूर की जानी चाहियें। आसाम में ४ करोड़ ४० लाख किलोवाट जल-विद्युत् पैदा करने की क्षमता है, लेकिन उसकी अपनी खपत केवल २.५ किलोवाट ही है। चाय और जूट के जरिये आसाम देश को यथेष्ट विदेशी मुद्रा देता है। इतने पर भी औद्योगिक रूप से आसाम बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। आसाम को आगे बढ़ने के लिये सुविधायें दी जानी चाहियें।

आसाम को तृतीय वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अब १३ करोड़ रुपये वार्षिक मिल रहे हैं, जो पहले से तीन करोड़ अधिक हैं। लेकिन पेट्रोलियम की रायल्टी में कुछ कटौती होने की भी आशंका है। वित्त मन्त्री को इस मामले की जांच करनी चाहिये।

मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनोहरन्** (मद्रास दक्षिण) : राष्ट्रपति जी की सुयोग्यता, उदारता, विनम्रता और विचार-स्वतंत्रता विख्यात है । उससे किसी को कोई मतभेद नहीं हो सकता । पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से मुझे बड़ी निराशा हुई है । उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है । इस अभिभाषण में दक्षिण भारतीय जनता की सब से बड़ी आशंका--हिन्दी थोपे जाने की आशंका--का कोई उल्लेख ही नहीं है ।

प्रधान मंत्री कई बार कह चुके हैं कि दक्षिण भारत पर हिन्दी थोपी नहीं जायेगी । लेकिन उसके छः महीने एक वर्ष बाद ही राष्ट्रपति ने एक निदेश जारी किया था, जिससे हमारी आशंका और बलवती हो गई थी । बाद में राष्ट्रपति ने उसका स्पष्टीकरण किया था । पर अभी हाल में गृह-कार्य मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया है कि सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सीखनी चाहिये नहीं तो उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जायेगी ।

तब फिर किसे अन्तिम माना जाये ? प्रधान मंत्री के आश्वासन को, या गृह-कार्य मंत्रालय के परिपत्र को ?

हिन्दी के हामियों का ख्याल है कि हिन्दी को अनिवार्य बना कर वे राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करते हैं । राष्ट्रीय एकता ऐसी कोई खरीदी जा सकने वाली या मनमाने ढंग से पैदा की जा सकने वाली वस्तु नहीं है । वह शिक्षा और परस्पर आदान-प्रदान की भावना से ही पैदा की जा सकती है । लेकिन यहां वह भावना है ही नहीं ।

यदि उत्तर भारत के लोग हिन्दी थोपना ही भारत की एकता समझते हैं, तो एकता कभी नहीं होगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने राष्ट्रीय एकता के महत्व पर बल दिया है । मैं उसकी आलोचना नहीं करता । इसलिये कि द्रविड़ कड़गम के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा, वह उनकी अपनी राय है । लेकिन उनको अल्प-भाषा-भाषी लोगों की कठिनाइयां और उनकी भावनायें तो समझनी चाहिये । तभी समस्या सुलझ सकती है । प्रधान मंत्री ने भी द्रविड़ कड़गम की आलोचना की है । मैं अन्य मामलों में प्रधान मंत्री का बड़ा प्रशंसक हूं, पर उनके ऐसे आक्षेपों को मैं अधिक महत्व नहीं देता ।

हम द्रविड़ कड़गम के सात प्रतिनिधि यहां आये हैं । हमारी भावनाओं और हमारे विचारों को समझे बिना हमारी आलोचना करना, परिपक्व मस्तिष्क के व्यक्तियों का तो काम नहीं ।

श्री लंका में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों में से ८५ प्रतिशत तमिल भाषी हैं । इसलिये वहां उच्च आयुक्त का प्रथम सचिव कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो तमिल भाषा जानता हो । वहां तमिल-भाषी कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी । सभी जगह प्रतिनिधित्व किये गये, पर उसका कोई फल नहीं निकला ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** (करूर): माननीय सदस्य श्रीलंका में भारतीय उद्भव के लोगों का उल्लेख कर रहे हैं या जफना तमिल लोगों का, जो श्रीलंका के नागरिक हैं ?

†**श्री मनोहरन्** : भारतीय उद्भव के तमिल लोगों का, जो वहां के कुल तमिल-भाषियों में ८५ प्रतिशत हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन लोगों को हमारे प्रधान मंत्री ने राज्य हीन व्यक्तियों की संज्ञा दी है।

मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि श्रीलंका में भारतीय उच्च आयुक्त के प्रथम सचिव के पद पर किसी तमिल-भाषी को नियुक्त करने की मांग पर गम्भीरता से विचार करें।

मद्रास की जनता चाहती है कि मद्रास को 'ए' श्रेणी का नगर घोषित कर दिया जाये। उत्तर भारत में कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली 'ए' श्रेणी के नगर हैं। दक्षिण मे ऐसा एक भी शहर नहीं है।

मद्रास के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने भी मद्रास को 'ए' श्रेणी का नगर घोषित करने की मांग की थी, पर उसे अस्वीकृत कर दिया गया है। बम्बई को १९४७ में 'ए' श्रेणी में रखा गया था, जब उसकी जनसंख्या १६.६ लाख थी। मद्रास नगर की जनसंख्या इस समय १७.२५ लाख है। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

अभी तक दक्षिण भारत की उपेक्षा की गई हैं। केरल, आन्ध्र, मैसूर---पूरे दक्षिण भारत की उपेक्षा होती रही हैं। जब तक ऐसी उपेक्षा जारी रहेगी, तब तक राष्ट्रीय एकता स्वप्न मात्र रहेगी।

विधान मंडलों में अब हमारे दल की सदस्य-संख्या ५० हैं। इस से हवा का रुख पता चलता हैं।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिस में उन्होंने सारी महत्वपूर्ण बातों और नीतियों को रख दिया हैं। कुछ विरोधी माननीय सदस्यों ने कहा कि उन्होंने अपने अभिभाषण मे फलां बात नहीं कही और फलां बात का उस में उल्लेख नहीं हैं। मैं उन को कहना चाहता हूं कि हमारे फ़ाइव यीअर प्लान में सारी बातें लिखी हुई हैं और अगर वे चाहें, तो उन्हें देख सकते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो थोड़ी सी बातें ज़रूरी समझीं, उन को उन्होंने नमूने के तौर पर अपने अभिभाषण में कह दिया।

कुछ माननीय सदस्य नये आये हैं। वे नहीं जानते कि राष्ट्रपति का भाषण वास्तव मे गवर्नमेंट का भाषण होता हैं और गवर्नमेंट सारी बातों और अपनी सारी नीतियों को नहीं लिख सकती। वह नमूने के तौर पर थोड़ी सी बातों को राष्ट्रपति के द्वारा उन के भाषण में कहलवा देती हैं।

अपने भाषण में राष्ट्रपति ने हम सब से चाहे सरकारी सदस्य हों और चाहे विरोधी सदस्य, रचनात्मक काम करने का अनुरोध किया हैं। मैं यहां पर देखता हूं कि विरोधी माननीय सदस्य कोई भी ऐसा सजेस्शन या परामर्श नहीं देते हैं, जिस से देश में रचनात्मक काम में प्रगति हो सके। रचनात्मक काम में तो सब सदस्यों को रुचि लेनी चाहिए, चाहे वे सरकारी बैंचों पर बैठे हों और चाहे विरोधी बैंचों पर। यह तो सब का काम हैं। मैं दस बरस से देख रहा हूं कि किसी भी रचनात्मक काम मे हमारे विरोधी भाई डट कर और अच्छी तरह साथ नहीं देते हैं। वे तो केवल नुक्ता-चीनी करते हैं।

श्री महीड़ा (आनन्द) : ग़लत बात हैं।

श्री विभूति मिश्र : देश का उत्थान तो रचनात्मक कामों से ही हो सकता हैं। अभी हमारे देश को आज़ाद हुए केवल दस पंद्रह साल हुए हैं, लेकिन इस काल में बहुत बड़े बड़े काम किये गये हैं। पश्चिमी पाकिस्तान से आये रेफ़्यूजी लोगों को एक अरब से भी ज्यादा रुपया खर्च कर के बसाया गया। इसी प्रकार पूर्वी पाकिस्तान से आये रेफ़्यूजीज को बसाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये गये और उन को बसाया गया।

जब हिन्दुस्तान का शासन कांग्रेस के हाथ में आया, तो खज़ाने मे कुछ नहीं था। खज़ाने को दुरुस्त करना, देश की स्थिति को दुरुस्त करना और पांच सौ से भी ऊपर रजवाड़ों को अपने साथ मिलाना कोई आसान काम नहीं हैं।

श्री महीड़ा (आनन्द) : स्टर्लिंग बैलेंसिज़ (पौण्ड पावने) थे।

श्री विभूति मिश्र : वे बहुत कम थे और उन को भी हम ने देश के निर्माण में खर्च किया-- हम ने उन को बर्बाद नहीं किया।

इस के अलावा मैं बताना चाहता हूं कि पहले हिन्दुस्तान में टाटा का कारखाना, मैसूर का कारखाना और बंगाल में लोहे का कारखाना, सिर्फ़ यही कारखाने थे । देश का शासन कांग्रेस के हाथ में आने के बाद भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में तीन बड़े बड़े इस्पात के कारखाने बनाये गये हैं। इन के अलावा बोकारो का कारखाना बनने जा रहा है और इलैक्ट्रिकल सामान के प्लांट्स लगाये गये हैं ।

पुराने राजामहाराजा कहते हैं कि हम ने क्या किया है। मैं उन को कहना चाहता हूं कि जब से हमारे हाथ मे शासन आया, तो हम ने इतना कुछ किया, लेकिन जब उन भाइयों के हाथ में सत्ता थी, तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपनी प्रजा को वोट का अधिकार भी नहीं दिया था, लेकिन जब हमारे हाथ में राज्य आया, तो हम ने सब को वोट को अधिकार दे दिया।

गोआ ४५० बरसों से हम से बिछड़ा हुआ था । उस को सरकार ने अपने हाथ में लिया और देश के साथ मिलाया ।

एक माननीय सदस्य : पंद्रह बरस के बाद ।

श्री विभूति मिश्र : इस के अलावा उस ज़माने में जो सब से बड़ा देशी राज्य था--हैदराबाद, उस को चन्द घंटों में हमारी सरकार ने लिया। ये हमारे काम हैं। माननीय सदस्य हमारे कामों को गिनना चाहते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : चीन ने हमारी भूमिपर अधिकार किया, माननीय सदस्य यह भी बतावें ।

श्री विभूति मिश्र : देश की स्वतंत्रता के लिए जब हम लोग जेलखाने जाते थे, उस समय विरोधी दल के अधिकतर लोगों ने कुछ नहीं किया।

श्री महीड़ा : राजाओं ने देश को अपने राज्य समर्पित किये ।

श्री विभूति मिश्र : क्या उन के ज़माने में अंग्रेज़ यहां से हटे ? उस वक्त बहुत से लोग अंग्रेज़ों की खुशामद किया करते थे ।

हर क्षेत्र में और हर तरफ़ हमारे देश का उत्थान हुआ है। दस बरस के समय में हिन्दुस्तान में खेती, सड़कों, स्कूलों, अस्पताल, हर एक महकमे में तरक्की हुई है। मेरे ज़िले चम्पारन में २५० पक्की सड़कें बनी हैं, जब कि पहले वहां पर कच्ची सड़क भी नहीं थी। विरोधी माननीय सदस्य इन कामों को देखते नहीं हैं ।

मैं प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के ग़रीब विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां देती है। मैं इस के मुआफ़िक हूं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि कुछ ऐसी जातियां भी हैं, जिन में ग़रीब विद्यार्थी हैं और जो इस से छूट जाती हैं। उन गरीब विद्यार्थियों को भी आप छात्रवृत्तियां दें। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को हम मैरिट छात्रवृत्ति देंगे। लेकिन जो गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है कि वह खाना खा सके ,उसके

पास रहने के लिए घर नहीं है और उसका जो लड़का है जो विद्यार्थी है, वह किस तरह से पढ़ सकता है और इस काम के लिए उसके पास पैसा कहां से आयेगा। धनी आदमियों के बच्चों को तो ट्यूशन मिल जाती है, वे ट्यूशन लगा लेते हैं और उनको सरकार की तरफ से कई प्रकार की सहूलियतें दे दी जाती हैं, मगर जो गरीब विद्यार्थी हैं, उनको कोई सहूलियत नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो जातियां छूट गई हैं, उन जातियों के गरीब विद्यार्थियों को भी आपकी तरफ से छात्रवृत्तियां देने का प्रबन्ध हो ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

बिहार में जमीन पर सीलिंग लगी है। वहां पर सीलिंग के अलावा लैवी भी लगाई गई है। एक एकड़ से ऊपर की जमीन पर लैवी लगाई गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार के जो बड़े मुलाजिम हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, जिन को मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, उनकी तनख्वाहों में भी कमी की जाये। आप की तरफ से कहा जा सकता है कि आप गरीबी का बटवारा नहीं करते हैं। मगर मैं सदन में कहना चाहता हूं कि गरीबी का भी बटवारा होता है और जब ऐसा होता है तो आदमी में उत्साह पैदा होता है। महात्माजी जब जेल जाते थे, हमारे प्रधान मंत्री जी जब जेल जाते थे, तो हम लोग भी जेल जाते थे और जेल जाने का हमे उत्साह होता था। महात्मा गांधी तकलीफ से रहते थे तो हमें भी तकलीफ से रहने की इच्छा होती थी। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि गरीबी का भी बटवारा हो। बिहार में आपने परमानेंट सैटलमेंट को हटाया, दायमी बन्दोबस्त को हटाया। अब जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, उनकी तनख्वाहों में भी आपको जरूर कमी करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह मुनासिब बात नहीं होगी।

चुनाव के दिनों मे और वैसे भी मैंने देखा है कि बेकारी हमारे देश में बहुत ज्यादा फैली हुई है और यह एक जबर्दस्त समस्या बन गई है। इसको हल करना बहुत जरूरी है। हमारे ढेबर भाई ने अपनी स्पीच मे कहा है कि एक करोड़ बीस लाख आदमियों को हम ने काम दिया है। यह सही है। लेकिन इतने से ही काम नहीं चल सकता है। मैं चाहता हूं हमारी सरकार इस पर विचार करे कि बेकारी की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है और इसको जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करे।

एक भाई ने कहा कि चुनावों के दौरान में कांग्रेस ने बड़ी गड़बड़ियां की हैं। हमारे देश में एक चुनाव हुआ, दूसरा हुआ और तीसरा हुआ। इतना बड़ा चुनाव सारी दुनिया में कहीं शायद ही हुआ होगा। जो सरकारी कर्मचारी इस काम में लगे, उन्होंने जिस ईमानदारी, जिस तत्परता और जिस मुस्तैदी से काम किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है। उनकी तारीफ किये बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। चाहे वे स्टेट गवर्नमेंट्स के कर्मचारी हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सभी ने इस चुनाव में कार्यक्षमता दिखाई है, ईमानदारी दिखाई है और इतनी तत्परता और मुस्तैदी के साथ इस काम को किया है कि कोई हदोहिसाब ही नहीं

हमारे विरोधी भाई हम पर जातपात को भड़काने का इल्जाम लगाते हैं। साम्प्रदायिकता को हटाने के लिये ही गणेश शंकर विद्यार्थी का खून कानपुर में हुआ और मोहन दास कर्मचन्द गांधी जी एक महात्मा थे उनका खून इसी दिल्ली नगर में हुआ।

श्री रामसेवक यादव : खून पर पानी बहा दिया आपने, यही तो अफसोस की बात है।

श्री विभूति मिश्र : बैठ जाइये साहब, मेरी बात तो सुन लीजिये।

हम जो कांग्रेसजन हैं, वे जातीय अथवा साम्प्रदायिक आधार पर नहीं सोचते हैं। यह बीमारी कैसे आती है, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। हमारे जो विरोधी भाई हैं, उनकी तरफ से इस बीमारी को लाया जाता है। हिन्दू महासभा, जन संघ, राम राज्य परिषद् इत्यादि जितनी पार्टियां

[श्री विभूति मिश्र]

हैं, इन सब ने मिल करके शुरू से ही जब से कांग्रेस ने जातीयता और साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, उसके खिलाफ जातीयता का प्रचार किया है। आप हमारा इतिहास देखें और इनका इतिहास देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन जातीयता का समर्थक रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता के ज़हर के खिलाफ लड़ते हुए कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता ने अपनी कुर्बानी दी है और सभी कांग्रेस जनों ने कहा है कि जातीयता या साम्प्रदायिकता की भावना का भारत में से समूल नाश होना चाहिए। आप बतायें कि जिस संस्था की सारी जिन्दगी इन बुराइयों के खिलाफ मोर्चा लेने में गुजर गई, वह इनको प्रश्रय दे सकती है। मुझे इस कांग्रेस संगठन की सेवा करते ४२ वर्ष हो गए हैं। क्या हम लोगों के दिमागों में कभी भी इस तरह की चीजें आ सकती हैं। मैं जब चुनाव लड़ा तो मेरे खिलाफ एक स्वतंत्र पार्टी का उम्मीदवार था, एक प्रजा समाजवादी था, और एक इंडिपेंडेंट था। मैंने इन तीनों को देखा है। सारा रिकार्ड मौजूद है। किस किस उम्मीदवार ने किस किस जाति के वोट किस किस गांव में पाये हैं, इसको आप अच्छी तरह से उस रिकार्ड से जान सकते हैं। आप साम्प्रदायिकता अथवा जातीयता का इल्ज़ाम कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं लगा सकते हैं।

हमारे त्रिवेदी जी यहां नहीं हैं और अगर वह यहां होते तो मैं उनको बताता कि वह अपनी कांस्टिट्यूएंसी में चल कर देखें कि किस किस गांव में किस किस जाति वालों ने किस किस उम्मीदवार के हक में वोट डाला है।

हमारे एक भाई कह रहे थे कि सारे साउथ में कुछ नहीं हुआ है। मैं बदकिस्मती से नार्थ का रहने वाला हूं। लेकिन जब मैं रामेश्वरम् जाता हूं महादेव के दर्शन करने के लिए तो कभी भी मेरे दिमाग में यह बात नहीं आती कि मैं नार्थ का हूं। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जब कभी मैं जाता हूं तो कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आता कि है कि मैं पश्चिम से आया हूं या कहीं और से आया हूं। हमें चाहिए कि नार्थ, साउथ, वैस्ट और ईस्ट सबको अपना मानें। यह नार्थ, ईस्ट, वैस्ट या साउथ का झगड़ा एक पोलिटिकल स्टंट है। इसी पोलिटिकल स्टंट की वजह से हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ और अब फिर ऐसे ही आदमी पोलिटिकल स्टंट खड़ा करके देश का बटवारा करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर डैमोक्रेसी को चलना है और योजना को चलना है तो नार्थ, ईस्ट, वैस्ट या साउथ का जो झगड़ा है, वह बेकार का है और देश को डिसइंटेग्रेट करने के लिये इसको खड़ा किया गया है। मैं बतलाना चाहता हूं कि ये जो झगड़े हैं, प्रान्तीयता का झगड़ा, भाषा का झगड़ा, जातीयता का झगड़ा, इनको गरीब आदमी नहीं फैलाते हैं बल्कि जो पालिटीशियंज हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वे ही फैलाते हैं। इन झगड़ों की जड़ में पालिटीशियंज ही हैं। किसी को अगर असेम्बली में जगह नहीं मिली, किसी को पार्लियामेंट में अगर जगह नहीं मिली और अगर किसी को टिकट मिला भी तो वह हार गया, तो हारने के बाद उसके दिमाग में यह बात आती है कि प्रान्तीयता का झगड़ा, भाषा का झगड़ा इत्यादि झगड़ों को खड़ा कर दिया जाए। कांग्रेसमैन कोई नहीं इनको फैलाता है। कांग्रेस के पास पूंजी है। कांग्रेस १८८५ में स्थापित हुई थी और आज १९६२ है। यह जो पीरियड है, इस पीरियड में कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए अनेक कुर्बानियां की हैं। उसके पास पूंजी है जिसके सहारे वह चल सकती है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वे चार दिन चलती हैं और कई तो चार दिन भी नहीं चल पाती हैं, पहले ही टूट जाती हैं, आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब ऐसा होता है तो वे सोचते हैं कि इसके सिवा कोई उपाय नहीं है भाषा के, प्रान्त के झगड़े खड़े किये जायें।

मैं प्रधान मंत्री जी से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि ये जो भाषा प्रान्त इत्यादि के झगड़े खड़े करते हैं, उन पालिटीशियंज के खिलाफ वे सख्त कार्रवाई करें, शक्ति के साथ उनसे पेश आयें।

राजकाज के मामले ढिलाई बरतने से नहीं चलते हैं। यह ठीक है कि डिमोक्रेसी में सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सभी की बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जब कार्रवाई करने का वक्त आए तो मजबूती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश और जनता का हित सिद्ध हो सके।

एक भाई ने कहा कि खेती में जो कुछ हुआ है वह सरकार की वजह से नहीं हुआ है। उनकी यह स्पीच मेरे पास है। अगर खेती की उपज बढ़ जाए तो यह कहा जाए कि यह सरकार की वजह नहीं हुआ है और अगर वह नहीं बढ़ती है तो कहा जाए कि सरकार कुछ नहीं करती है, तो यह एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें हमारी जान किसी तरह से भी नहीं बच सकती है। गांव में आप जायें, वहां पर खाद बांटा गया है, बीज बांटा गया है, रुपया कर्ज के तौर पर दिया गया है, पानी का इन्तज़ाम किया गया है। यह सब कहां से हुआ है और किसने इस सब को किया है, यह भी आपको देखना चाहिए।

अब मैं पंचायतों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सब चीजों का मूल पंचायत है और पंचायतों की हम लोगों को स्थापना करनी चाहिए और इनको मज़बूत करना चाहिए। आज पंचायतों के ज़रिये कितने ही काम हो रहे हैं। एक भाई ने कहा कि पंचायतों के ज़रिये काम नहीं होते हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि बिहार में मालगुज़ारी वसूल करने का काम पंचायतों के ज़रिये होता है। यह उनका जिम्मा है और उनको साढ़े बारह प्रतिशत कमिशन के तौर पर मिलता है जो कि सरकार देती है। यदि इस काम को पूरा कर लिया जाता है तो साढ़े बारह प्रतिशत सरकार और देती है। इसका मतलब यह हुआ कि सौ रुपये में पच्चीस रुपये गांव की पंचायत को सरकार देगी। मैंने देखा है कि इस काम को वे बड़ी अच्छी तरह से कर रही हैं और मालगुजारी वसूल करने का काम अच्छे ढंग से चल रहा है। यह तो कोलैशन का काम है यह बड़ी अच्छी तरह से वहां हो रहा है। वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैं उन से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के खर्चे के ऊपर आप ध्यान रखें। खर्चा हो और आवश्यकता के अनुसार हो, लेकिन मैं यह कहूंगा कि आपकी सरकार में कहीं कहीं जो बेकार का खर्चा होता है उसको रोकने के लिये पूरा इन्तजाम कीजिये। मेरा अपना खयाल है कि सब कड़ाई के बावजूद भी हाल ही में एक डिवीजन कायम किया गया है कि वह देखे कि कौन जगह बेकार है और कौन आदमी बेकार रहता है। इस पर वह नियंत्रण रखे कि हमारे पैसे का हिसाब किताब अच्छी तरह से होना चाहिए।

मैं अपने राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके साथ हम लोगों का बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। राष्ट्रपति जी ने जिस तरह से रचनात्मक काम किया है उस तरह से वे आगे भी करेंगे। भगवान उन्हें स्वस्थ और दीर्घजीवी करे।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : हमारे राष्ट्रपति ने पूरी गरिमा और विनम्रता के साथ अपने पद का दायित्व निभाया है। मैं उनके प्रति अपना हार्दिक सम्मान व्यक्त करता हूं।

लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की त्रुटियां भी सभा के सामने रखूं। अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का ही प्रतिबिम्ब है, राष्ट्रपति के व्यक्तित्व का नहीं। इसलिये अभिभाषण की आलोचना सरकार की आलोचना है।

अभिभाषण में भारत के पड़ोसी देशों--पाकिस्तान और चीन--से बढ़ती हुई तनातनी का कोई उल्लेख नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

चीन ने बारह हज़ार वर्ग मील का भारतीय क्षेत्र अनधिकृत रूप से अपना कब्ज़े में कर लिया है। चीन का हमला बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कई नई चौकियां स्थापित कर ली हैं।

पाकिस्तान ने भी कई भारतीय क्षेत्रों पर दावा किया है। इसलिये कि भारत सरकार की वैदेशिक नीति कमजोर है।

भारत ने निःशस्त्रीकरण के लिये काफी प्रयास किया है। इसलिये उसे १८ देशों की निशस्त्रीकरण समिति का सदस्य चुन लिया गया है।

लेकिन विज्ञान की सफलतायें जनसंहार के साधन विकसित करने के लिये प्रयुक्त की जा रही हैं।

श्री हीरेन मुकर्जी ने अमरीकी अणु-परीक्षणों की तो निन्दा की है, पर रूसी परीक्षणों के बारे में कुछ नहीं कहा।

पिछली बार अभिभाषण सम्बन्धी वाद-विवाद के दौरान सत्तारूढ़ दल द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं की जांच के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाने का सुझाव रखा गया था, परन्तु उस दिशा में अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है।

सतारूढ़ दल ने अपने उम्मीदवारों के चुनाव के लिये प्रशासकीय व्यवस्था का अंधाधुन्ध प्रयोग किया है। समूचा चुनाव एक बड़ा गोलमाल बना दिया गया है। हर तरह की चाल-बाजियां की गई हैं।

इन सबके होते हुए भी स्वतंत्र दल ने विधान सभाओं के २०० और लोक-सभा के २६ स्थान जीत लिये हैं। वह देश का दूसरा सब से बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। प्रोफेसर मुकर्जी ने इसे दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों की जीत कहा है। यदि स्वतंत्र दल प्रतिक्रियावादी है, तो फिर हमें शब्दकोष में शब्दों के अर्थ बदलने पड़ेंगे। स्वतंत्र दल को सामन्तों का दल कहना निराधार है। पुराने जमाने का सामंतवाद अब दफनाया जा चुका है।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में सभी दलों के लिये एक आचार संहिता रखी थी। लेकिन चुनावों के दौरान स्वयं ही उसका पालन नहीं किया: कांग्रेस को देश के ५५ प्रतिशत मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है। इसलिये उसे बहुमत दल नहीं कहा जा सकता। उड़ीसा में कांग्रेस ने १९ लोक-सभा सीटों पर १२ लाख रुपये व्यय किये हैं जब कि प्रति उम्मीदवार संविहित व्यय २५,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। यदि इसी तरह चुनाव होते रहें, तो एशिया के अन्य देशों की भांति, हमारे यहां भी लोकतंत्र की कब्र खुद जायेगी। लोकतंत्र के लिये एक विरोधी दल का अस्तित्व परम आवश्यक है।

इंगलैण्ड में विरोधी दल को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना कि सरकारी दल को। लेकिन भारत में उसका बिल्कुल उल्टा है।

†श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभिभाषण में बताया गया है कि अब पंचायती राज आठ से बढ़ कर बारह नये राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। पंचायती राज हमारे देश की परम्पराओं के अनुकूल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारों की सहायता के लिये भी एक योजना सम्मिलित की गई है। देश में औद्योगिक उत्पादन की प्रगति संतोषजनक रही है। श्रमिक कल्याण के लिये कई विधेयक सभा में आने वाले हैं।

[**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** पीठासीन हुए]

कहा गया है कि कांग्रेस अपने आदर्शों को पूरा नहीं कर पाई है। कुछ हद तक यह सही भी है। सभी आदर्शों को तो कोई भी दल पूरा नहीं कर पाता। लेकिन यह भी सही है कि कांग्रेस ने उनकी पूर्ति के लिये पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है।

यह भी कहा गया है कि कांग्रेस को सत्तारूढ़ नहीं रहना चाहिये, क्योंकि उसे केवल ४५ प्रतिशत मतदाताओं का ही समर्थन मिल पाया है। लेकिन इससे अधिक समर्थन तो किसी भी दल को नहीं मिल पाया है।

स्वतंत्र दल के पास कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। चुनावों में कांग्रेस की जीत से स्पष्ट है कि जनता ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित सफलताओं और कार्यक्रम का पूरा समर्थन किया है।

चुनावों में यदि कोई अनियमितता हुई भी हो तो वहां के लोगों को चुनाव याचिका पेश करनी चाहिये थी। कदाचार रोकने का तो यही तरीका है। इसके लिये कुछ किये बिना ही किसी दल या अधिकारियों को दोष देना व्यर्थ है।

भ्रष्टाचार का आरोप भी बड़ा नमक-मिर्च लगा कर पेश किया जाता है। अब देश में भ्रष्टाचार दिन-दिन कम होता जा रहा है।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : अभिभाषण में न तो कोई प्रेरणा है और न उत्साह।

अभिभाषण में देश की आंतरिक और वैदेशिक समस्याओं का, मौजूदा समस्याओं का कोई उल्लेख ही नहीं है। उससे पता ही नहीं चलता कि सरकार क्या करने जा रही है।

पाकिस्तान ने हमारे देश को चुनौती दी है।

कश्मीर की समस्या एक तलवार की तरह हमारे सिर पर लटक ही रही है। अब सुरक्षा परिषद् फिर उस पर विचार कर रही है। पाकिस्तान आक्रामक है, फिर भी उसे सुरक्षा परिषद् में प्रार्थी क्यों माना जा रहा है?

पाकिस्तान का मंशा इसके जरिये अपना प्रचार करना है। वह असल में पाकिस्तानी जनता से अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा है।

हमारे प्रधान मंत्री जब नहरी पानी संधि के सिलसिले में कराची गये थे, तो जनता ने उनका भव्य स्वागत किया था। हमने समझा था कि दोनों देशों के सम्बन्ध अब सुधरेंगे। लेकिन उसके दो दिन बाद ही जनरल अय्यूब खां ने भारत के विरुद्ध अपने पंजे उघार दिये थे।

संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तक इस दिशा में कोई परिणाम नहीं दिखा पाया है। वह संसार की समस्यायें हल करने में असफल रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री हेम बरुआ]

नहरी पानी विवाद के मैत्रीपूर्ण हल के पश्चात् हमने सोचा था कि भारत व पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण युग का सूत्रपात होगा। तथापि उसके दो दिन पश्चात् ही पाकिस्तान के प्रेसीडेंट अयूब खां ने जो भाषण दिया उसे पाकिस्तान की बुरी नीयत का पता चल गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं कर सका है।

हमारी वैदेशिक नीति का विदेशों में यह प्रभाव पड़ा है कि हम अपनी सेनाओं में वृद्धि कर रहे हैं। पाकिस्तान के विचार से हम एक दुर्बल राष्ट्र हैं इसीलिये उसने कर्णफूली बांध बनाने का एकपक्षीय निर्णय कर लिया है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस बांध के बनने के फलस्वरूप १२$^{1}/_{2}$ वर्ग मील भूमि जलमग्न हो जायेगी। मेरे विचार से इससे कहीं अधिक भूमि लगभग १०० मील जलमग्न होगी। जब एक बार भारतीय भूमि का यह भाग जलमग्न हो जायेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन करना बहुत कठिन हो जायेगा।

इसी प्रकार चीन ने हमारी १४००० वर्ग मील भूमि हड़प ली है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो सरकार क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा नहीं कर सकती उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों देशों के सरकारी अधिकारियों के प्रतिवेदन प्रकाशित होने पर यह आशा की गई थी कि संभवतः चीन का हृदय परिवर्तन हो जाये क्योंकि प्रतिवेदन से भारत के मत को पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ था। इसके विपरीत चीन ने भारत पर तरह तरह के आरोप लगाना आरम्भ कर दिया। लद्दाख में चीनी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं जब प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है तो वे कहते हैं कि क्षेत्र बहुत विस्तृत है उसकी रक्षा नहीं की जा सकती है।

कांग्रेसी सरकार ने भावात्मक एकता का नारा बुलन्द किया था, तथापि इस समय अभिभाषण में इसका कहीं जिक्र भी नहीं है। सच्चाई यह है कि राष्ट्रीयता हमारे लिये एक नवीन सिद्धांत है जिसका जन्म अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था। इसमें संदेह नहीं कि विभिन्नता के बीच भारत में एकता विद्यमान है तथापि अधिकांश यह होता है कि एक समुदाय के हित दूसरों से टकराते हैं। फल यह होता है कि राष्ट्रीयता का स्थान सामुदायिक हित ले लेते हैं। अतः राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार करना आवश्यक है लेकिन इस अभिभाषण में इसका कहीं जिक्र नहीं है।

विदेशी शासन काल में जनता में निराशा थी लेकिन इस निराशा में एक मुलम्मा चढ़ा हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्त होने पर यह मुलम्मा हट गया और निराशा की भावना ऊपर उभर आई, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से जनता को अवसर प्राप्त हुए हैं तथापि लोगों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता और संघर्ष भी बढ़ा है। सरकार इस पर ध्यान देने तथा उसका उपचार करने में असमर्थ रही है।

†**श्री स० चु० जमीर** (नामनिर्देशित—नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र): चीन की बढ़ती हुई शक्ति और उसके आक्रमण ने उत्तरी पूर्वी सीमान्त पर सुरक्षा की समस्या पैदा कर दी है। चीन अभी तक भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार किये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि सभा में बार बार यह आश्वासन दिया गया था कि आक्रमण रोकने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं तथापि यह भी ज्ञात हुआ है कि चीनी लद्दाख क्षेत्र में ६ मील अन्दर तक घुस आये हैं समझ में नहीं आता कि ऐसा किस प्रकार संभव हुआ है ।

हमारे पड़ौसी राष्ट्रों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं मुख्यत: पाकिस्तान के साथ काश्मीर विषय में हमारा बहुत मतभेद है। और यह संबंध तब तक खराब ही रहेंगे जब तक कि काश्मीर का मामला तय नहीं हो जाता है ।

अभी हाल नेपाल के महाराजा ने यह बताया कि काठमांडू-ल्हासा-मार्ग का निर्माण नेपाल का आंतरिक मामला है उसका केवल आर्थिक महत्व है। प्रतिरक्षा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि मेरे विचार से भारत इन बातों की उपेक्षा नहीं कर सकता है ।

यह हर्ष का विषय है कि बर्मा के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्री पूर्ण हैं तथापि नागा उपद्रवी बर्मा से ही अपने भारत विरोधी काम का संचालन कर रहे हैं इसके अतिरिक्त काचिन राज्य में चीनी घुसते जा रहे हैं और इस प्रकार वहां बर्मा विरोधी वातावरण तैयार किया जा रहा है। अत: भारत को चाहिये कि वे बर्मा के सहयोग से इन विद्रोहियों का दमन करें।

उक्त कारणों से सीमांत स्थिति बिगड़ती जा रही है। और वहां के निवासियों को खतरा पदा हो गया है अत: सरकार को चाहिये कि उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करे।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सीमान्त में रहने वाले आदिवासी बहुत उपयोगी हैं। पिछले महायुद्ध में भी उन्होंने जापानियों के विरुद्ध मित्रराष्ट्रों को बहुत सहायता पहुंचाई थी। क्या युद्ध होने पर अब भी ये आदिवासी भारत की उसी प्रक र सहायता करेंगे। मेरे विचार से वे ऐसा नहीं करेंगे। कारण यह है कि भारत के अन्य निवासियों के साथ उनकी भावात्मक एकता के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं ।

इसके लिये यह भी आवश्यक है कि उनकी धार्मिक तथा सामाजिक दशा का सुधार किया जाय उन्हें वर्तमान गिरी दशा से उठाया जाये ।

आसाम तथा मनीपुर क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों की जनता की राजनैतिक आकांक्षायों की पूर्ति की जानी चाहिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर): सभापति जी, राष्ट्रपति जी के भाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ भी कहने के पूर्व माननीय राष्ट्रपति जी की सेवाओं के प्रति और उन के द्वारा स्थापित आदर्श परम्पराओं के प्रति सम्मान प्रकट करना मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूं ।

माननीय राष्ट्रपति जी ने पिछले दस वर्ष की अवधि मे अपने परिश्रमी स्वभाव से और दूरदर्शी विचारों से जहां जहां हमारे राष्ट्र का नेतृत्व किया है वहां सब से बड़ी बात तो इस परम्परा का आरम्भ कर उन्होंने किया है कि नियत समय से अपने पद से मुक्त होने का स्वत: निर्णय करना और अपने वेतन के सम्बन्ध में जो सरकार से नियत है एक चतुर्थी मात्र लेकर निर्वाह करना। इन अनुकरणीय आदर्श से मेरा अपना विचार है कि उनके आने वाले उत्तराधिकारी और साथ साथ हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे ।

दूसरी विशेष बात जो मैं राष्ट्रपति जी के भाषण पर कहना चाहता हूं वह निर्वाचन आयोग के सम्बन्ध में है ।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

अभी हमारे देश में निर्वाचन सम्पन्न होकर चुके हैं । निर्वाचनों में कुछ इस प्रकार की घटनायें देश के सामने आई हैं जिन की कि विस्तार से चर्चा करना इस समय अपेक्षित इसलिए भी न होगा क्योंकि उनमें बहुत सी घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ पेटीशंस अभी दायर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मोटी सी भाषा में मैं इस बात को यूं कहना आवश्यक समझूंगा कि हमारे देश में प्रजातंत्र की जो भित्ति खड़ी की जाती है, उसका बुनियादी पत्थर जहां से आरम्भ होता है, वह निर्वाचन आयोग है । लेकिन मुझे भय है निर्वाचन आयोग कहीं धीरे धीरे शासन के हाथों का खिलोना मात्र बन कर न रह जाय, कहीं ऐसी स्थिति कहीं आकर पैदा न हो जाय कि प्रजातांत्रिक प्रणाली जिसे देश के अंदर सुरक्षित समझा जाता है, धीरे धीरे उस से जनता की आस्था हटती न चली जाय। इस बात को विशेष रूप से कहने की आवश्यकता मुझे यूं प्रतीत हुई कि क्योंकि हमारी चार दिवारी के आस पास प्रजातंत्र से अस्था हटने का क्या परिणाम हुआ है संभव है आपको जानकारी होगी कि अभी कुछ समय पूर्व दिल्ली से राज्य सभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होना था और राज्य सभा के सदस्य के निर्वाचन के मतदाता नगर निगम के सदस्य होते ही हैं । लेकिन क्योंकि उस समय तक नये नगर निगम के सदस्य जो चुने गये हैं उन के नाम गजेट नहीं हुए थे लिहाजा स्वाभाविक था कि जो पुराने नगर निगम के सदस्य थे उस के मतदाता होते और उन पुरानों में बहुत बड़ी संख्या इस प्रकार की थी जो कि कांग्रेस विरोधी दल के थे । इसलिए उन्होंने निर्वाचन आयोग से मिल कर उस चुनाव को २० दिन के लिये आगे टलवाया ताकि नये सदस्यों के नाम गजेट हो जांय और उस के बाद उन के द्वारा राज्य सभा के सदस्य का निर्वाचन हो । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें आगे चल कर निर्वाचन आयोग के प्रति इस प्रकार का अविश्वास उत्पन्न कर देंगी कि जनता में निर्वाचन आयोग के प्रति कोई आस्था नहीं रह जायगी । इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब विचार हो रहा है तब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की उपेक्षा न की जाय।

दूसरी बात जिसकी ओर मेरे माननीय मित्र ने संकेत भी दिया उस सम्बन्ध में भी कहना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं और वह यह कि जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हम ने जहां अपने देश की और बहुत सी परम्पराओं के सम्बन्ध में कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या होगा, हमारे राष्ट्र का ध्वज क्या होगा, हम ने अपनी राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध मे भी कुछ निश्चय किये थे और बहुत कुछ सोचने विचारने के पश्चात् हम ने १५ वर्ष की अवधि इस के लिये निर्धारित की थी कि १५ वर्ष के पश्चात् जहां आज अंग्रेजी है वहां हिन्दी उसका स्थान ले लेगी । इस में १२ वर्ष व्यतीत होने आये । उस १२ वर्ष की अवधि में उस हिसाब से कितना हम आगे बढ़े हैं यदि सोचें तो हम को देख कर स्वयं अपने ऊपर पश्चाताप होगा। अभी कुछ देर पूर्व मेरे एक साथी माननीय सदस्य जो कि मेरी बगल में बैठे हुए थे और जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़घम के प्रतिनिधि थे उन्होंने जहां हिन्दी के सम्बन्ध में और बहुत सी बातें कहीं एक बात उन्होंने यह भी कही कि केन्द्र के लोग हिन्दी को दक्षिण के लोगों पर थोपना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार की भावनाएं देश में उभर रही हैं उसका बहुत बड़ा दायित्व हमारी केन्द्रीय सरकार की शिथिल नीति के ऊपर भी है कि जिस ने अपने लिए एक अवधि निर्धारित की थी, लेकिन निर्धारित अवधि के लिए

कुछ कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया था । इस प्रश्न को इस तरीके से बराबर शिथिलता के साथ टाला जा रहा है । परिणाम यह है कि क्षेत्रीय भाषाएं राज्य भाषा के सम्बन्ध में आकर अपने को उस का प्रतिद्वन्दी बना कर सोचती हैं । हिन्दी की लड़ाई क्षेत्रीय भाषाओं से नहीं है । तामिल, तेलगू, कन्नाडा, मलयालम, लम, बंगाली , आसामीज, जितनी भी भाषाएं सब स्थानों पर बोली जाती हैं, वे फलें फूलें और विकास करें। इस में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । हिन्दी की उन्नति से तात्पर्य तो केवल यहां तक है कि अंग्रेज के समय में जिस स्थान पर अंग्रेजी थी उस स्थान पर हम ने हिन्दी को लाना है । क्षेत्रीय भाषाओं से उसका किसी प्रकार का कोई विरोध है ही नहीं । लेकिन जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को और हिन्दी को लेकर जो इस प्रकार के आन्दोलन उत्पन्न करते हैं उन के पीछे एक राजनैतिक भावना भी निहित होती है । इसी बारे मे एक अन्य बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि केन्द्रीय सरकार के गृह-मंत्रालय की ओर से प्रति वर्ष कुछ इस प्रकार की लिस्ट प्रकाशित होती है कि इस वर्ष केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में इतने हजार व्यक्तियों ने हिन्दी प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण की है । इस वर्ष उनकी संख्या लाखों में पहुंच गयी है लेकिन उस का व्यावहारिक रूप क्या है ? वह प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लेते हैं परन्तु चूंकि व्यवहारिक कार्य के लिये उनको अवसर नहीं दिया जाता है इसलिए वह धीरे धीरे उस को भूलने लगते जाते हैं। लोगों की यह शिकायत ठीक ही है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी तक हिन्दी को व्यवहारिक क्षेत्र में प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है । मेरा अपना निवेदन बड़ी नम्रता के साथ यह है कि जिन कर्मचारियों को आपने व्यय करके हिन्दी में प्रशिक्षित किया है और जो उस में काम करने के योग्य हो गये हैं उन को कम से कम हिन्दी को व्यवहारिक रूप मे प्रयोग करने का अवसर प्रदान करें ।

दूसरी बात सब से बड़ी बात यह है कि आप को कठिनाई हो सकती है , केन्द्रीय सरकार को तामिल वालों, के साथ, तेलगू वालों के साथ और कन्नड़ वालों के साथ हिन्दी में व्यवहार करने मे कठिनाई हो सकती है लेकिन हमारी केन्द्रीय सरकार को जो हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त हैं उन के साथ हिन्दी में व्यवहार करने में क्या कठिनाई है ? कम से कम १२ वर्षों में हमें इतना तो आगे बढ़ जाना चाहिये था कि जितने हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त हैं उन के साथ हमारे केन्द्र का जो पत्र व्यवहार होता है या दूसरे जो कार्य हैं वह हिन्दी में आरम्भ हो जाते लेकिन उन प्रान्तों के साथ भी हमारा हिन्दी में पत्र व्यवहार तक नहीं है । इसलिए स्वाभाविक है रूप से यह प्रतीत होता है कि हमारे मस्तिष्क में वह पवित्रता जो कि संविधान में १५ वर्ष की अवधि निर्धारित करते समय थी, आज वह पवित्रता उस रूप में सुरक्षित नहीं है । मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर विचार करते समय इस बात को गम्भीरता के साथ लिया जाय और प्रधान मंत्री जी क्योंकि अभी हिन्दी को राजभाषा होने में ३ वर्ष और रह जाते हैं, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दें जिस से राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क में जो विक्षोभ है और एक संदिग्ध स्थिति बनती चली जा रही है उस के सम्बन्ध में कोई निर्णायक मार्ग अपना सकें और सोच सकें आगे चल कर इस सम्बन्ध में होना क्या है ।

तीसरी बात जिसको कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि राष्ट्रीय के सम्बन्ध में । दिल्ली में अभी हाल में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था । इस सदन में भी राष्ट्रपति जी के

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

अक्षुण्णता अभिभाषण पर उस सम्बन्ध में कई प्रकार की चुनाएँ हुई हैं कि राष्ट्रीय एकता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है । साथ ही मुझे आप यदि अनुमति दे तो में चाहूंगा कि जिस तरीके से अबतक हमारा वह क्रम रहा औरप्रान्तों की सीमाएं छोटी करने की और अभी तक हमारा ध्यान रह, मेरा अपना तजुर्बा हैं कि राष्ट्र को अक्षुण्णिता को यदि सुरक्षित रखना है तो बजाय प्रान्तों की सीमाएं छोटो करने को के उनको सोमाओं की और विस्तृत करने की और हमारा पग पहुना चाहियें । मोटी भाषा में यदि में कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि मैं इन विचारों का समर्थक हूं कि यह जो राज्यों के सोमायें हैं यदि एक ऐसा अवसर भी आजाये कि उन सीमाओं को समाप्त करके एक केन्द्रीय प्रशासन की स्थापना की जा सके, तो वैसा करके राष्ट्रीय अक्षुण्णता के मार्ग में हम बहुत बड़ा योग दे सकेंगे । इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह भी होगा कि केन्द्रीय सरकार का और प्रान्तों का कि जो आज आपस में उनमें तालमेल नहीं खाता है और जिसका कि परिणाम यह हुआ है कि प्रान्तीय सरकार का प्रशासन जो निर्णय लेता है केन्द्रीय सरकार यहां पर बैठ कर और बड़े नेता अलोचना भी करते हैं और दुखी भी होते हैं लेकिन उस के बारे में कोई इस प्रकार का आदेश नहीं दे सके जिससे ऐसा अवसर न आये, उनमें तालमेल स्थापति हो जायेगा । अभी कल अथवा परसों की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कई मंत्रीमंडलों के गठन के सम्बन्ध में कहा कि प्रान्तों में जो बड़े बड़े मंत्रिमंडलों का निर्माण हो रहा है उसको मैं कतई पसन्द नहीं करता । अब उत्तरप्रदेश के मंत्रिमंडल की ही बात लीजिये । उत्तर प्रदेश के अन्दर २४८ रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं और उसमें ४३ मिनिस्टर्स यानी हर सवा छे मेम्बरों के ऊपर एक मिनिस्टर बना । लेकिन पंजाब ने इससे भी आगे बढ़ कर अपनी दुनिया बनाई । वहां ६० विधान सभा के सदस्यों में ३० मिनिस्टर बना कर रख दिये । एक प्रोजेर, एक सेकेंडर और तीसरा मिनिस्टर । यह पंजाब की स्थिति आकर बन गयी । यह जो बात बनती चली जा रही है यह उस शासन की दृढ़ता का परिचायक नहीं है बल्कि जहां जहां इस प्रकार से मिनिस्टरों को फौजे तैयार हो रहीं हैं, यह शसन की दुर्बलता का परिचायक है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार उनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं कर सकती यह तो केन्द्र की बड़ी दुर्बल नीति का परिचायक है । मैं समझता हूं कि केन्द्र और प्रान्तों का आपस में तालमेल न होने का यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है ।

एक अन्य बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि लोग इस सम्बन्ध में सोचते हैं, कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बड़ी दुर्बल है, कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को पुष्ट करें लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके कि सम्बन्ध में स्वतः केन्द्रीय सरकार निर्णय ले सकती है । हम अपने संविधान में परिवर्तन करें या उस सम्बन्ध में कोई थोड़ा सा संशोधन करें । उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश मैं जितने भी १५ प्रदेश अथवा राज्य हैं उनमें ९ प्रदेश ऐसे हैं जहां विधान सभाओं के साथ साथ विधान परिषदें यानी लेजिस्लेटिव कौंसिल भी हैं । ६ प्रदेश अभी इस प्रकार के हैं जहां कि विधान परिषदें नहीं हैं । जब उन प्रान्तों का बिना विधान परिषदों के भी कार्य चल सकता है तो कोई किसी प्रकार की कठिनाई उन ९ प्रान्तों के लिये भी न होनी चाहिये । उन ९ प्रान्तों में विधान परिषदों का बोझ जनता के कंधों पर लादना यह कहां तक युक्तिसंगत है ? एक ओर तो आप अर्थशास्त्र की बात करते हैं और कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से हमारा देश कमजोर है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बड़ी दुर्बल है । अर्थ के सम्बन्ध में हम कठिनाई अनुभव करते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है कि हम दूसरों के पास भीख मांगने के लिये जाते हैं लेकिन दूसरी ओर स्थिति यह है कि व्यर्थ के खर्च हम अपने कंधों पर लादें चले जा रहे हैं । मेरा विचार यह है कि अब वह समय आगया है कि इस सम्बन्ध में भी हमको दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिये । छोटे छोटे प्रान्तों का हम निर्माण करते चले जा रहे हैं । पंजाब जैसे मुठी भर लोगों के प्रदेश में विधान

सभा है और उस के ऊपर एक विधान परिषद् है । इसी तरह से जम्मू तथा कश्मीर राज्य में एक विधान सभा है और उसके ऊपर एक विधान परिषद् है । अब इन में विधान परिषदों की क्या आवश्यकता है । मेरा अपना विचार यह है कि अब वह समय आ चुका है जब कि केन्द्रीय सरकार को दृढ़ता के साथ इस बारे का निर्णय लेने की आवश्यकता है ।

एक बात जो कि मैं अपने वक्तव्य के अन्त में कहना चाहता हूं वह यह यह है कि यदि हम अपने देश की अक्षुण्णता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारे देश में इस प्रकार के साम्प्रदायिक संगठन जो कि आज फिर धीरे धीरे अपना सिर उठा रहे हैं और जो कि किसी भी समय हमारी राष्ट्रीय एकता के लिये संकट सिद्ध हो सकते हैं, सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उन के उपर दृढ़ता से कुछ नियन्त्रण करे । हम इस बात गकी केवल आलोचना मात्र कर के ही संतुष्ट नहीं हो सकते कि द्रविड़ मुनेत्र कड़घम वालों की ओर से प्रथकतावादी मनोवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है अथवा अकाली दल की ओर प्रथकतावादी मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिल रहा है। मुस्लिम लीग ने फिर पुराने नारे लगाना शुरू कर दिया है । इत्तिहादुल- मुसलमीन फिर से सिर उठाती चली जा रही है । अगर सरकार वास्तव में हृदय से यह अनुभव करती है कि उन की पृथकता-वादी मनोवृत्ति आगे चल कर देश के लिये खतरा साबित हो सकती है, तो उसका यह नैतिक कर्तव्य है कि वह दृढ़ता से उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करे ।

इस हाउस में कई बार यह चर्चा हुई है कि आसाम में पाकिस्तान से लाखों की संख्या में जो नागरिक आ गए हैं, उन्होंने आसाम के आन्तरिक वातावरण को क्षुब्ध कर दिया है । अब सुना जाता जाता है कि वही स्थिति पश्चिमी बंगाल की बनने जा रही है और नादिया से कलकत्ता तक एक लिंक, एक शृखला, बनती जा रही है । अगर सरकार ने इस बारे में उचित समय पर पग न उठाया तो जैसे आज आसाम के लिये एक भया वह स्थिति पैदा हो गई है, उसी प्रकार कल पश्चिमी बंगाल के लिये भी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है और होते होते यह स्थिति सारे देश के लिये भयावह होगी ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, १ मई, १९६२ / ११ बैशाख १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ३०, अप्रैल, १९६२
१० वैशाख, १८८४ (शक)]

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण . . .	६३९

दो सदस्यों ने निम्नलिखित भाषाओं में शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया :

१ ने अंग्रेजी में; और

१ ने उड़िया में ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . .		६६९–९४
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६९	पूर्वी क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन . .	६६९–७१
२७०	कांडला पत्तन के लिये बिजली . .	६७१–७२
२७२	हुगली के जहाज चालक	६७२
२८३	हुगली के जहाज चालक	६७२–७४
२७३	बिजली की दरों में असमानता . .	६७४–७७
२७४	खड़गपुर–टाट सेक्शन पर लाइन को दोहरा करना . .	६७७-७८
२७५	रेंड़ बांध	६७८–८०
२७६	रेलवे में डिवीजन प्रणाली के ढंग का संगठन	६८०–८२
२७७	बिजली के 'मल्टिपल यूनिट स्टाक' का उत्पादन	६८२-८३
२७८	"जल जवाहर" नामक जलयान का डूबना .	३८३-८४
२७९	रेलवे कर्मचारियों के लिये यात्रा तथा भाड़े की रियायतें	६८४-८५
२८०	रेलवे के लोको शैडों में सामयिक श्रमिक .	६८५-८६
२८१	कलकत्ता हवाई अड्डे पर टर्मिनल इमारत	६८६-८७
२८४	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड . .	६८७-८८
२८५	यमुना पर आगरा में राजपथ का पुल . .	६८८
२८६	बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनायें . .	६८८–९०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर : (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२८८	उरन से गेटवे आफ इंडिया तक झूला पुल . .	६६०–६१
२८९	गन्ने की पिराई	६६१—६३
२९०	गेहूं का उत्पादन	६६३–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६६४—७४८
तारांकित प्रश्न संख्या		
२७१	देश में बाल पक्षघात (पोलियो) के मामले . .	६६४–६५
२८२	नर्सों का प्रशिक्षण	६६५
२८७	सोन-पुल	६६५
२९१	माता टीला बांध	६६६
२९२	"इंडियन नेविगेटर" जहाज के साथ दुर्घटना . .	६६६
२९३	नमूने की मोटर कोच . . .	६६६–६७
२९४	मनीपुर में डाक्टरों की कमी	६६७
२९५	नर्मदा घाटी परियोजना . . .	६६७
२९६	इलेक्ट्रो मैगनेटिक सौटिंग मशीन . .	६६७–६८
२९७	हैजा	६६८
२९८	कलिंग एयरलाइन्स	६६८
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५०	पठानकोट रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय . . .	६६८
२५१	बटाला में चीनी निर्माण	६६९
२५२	अमृतसर पठानकोट लाइन पर यात्रियों को सुविधा .	६६९
२५३	दिल्ली में सड़क दुर्घटना	७००
२५४	टेलीफोन के कनेक्शन	७००
२५५	दिल्ली में कोढ़ियों का बन्ध्यकरण . .	७०१
२५६	क्विलौन में ऊपरी पुल . . .	७०१
२५७	नई दिल्ली में स्कूल के बच्चों के लिये स्वास्थ्य सेवा योजना .	७०१–०२
२५८	दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति	७०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
२५९	संवरण पद	७०३
२६०	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संवरण पदों पर पदोन्नति	७०३
२६१	१९६१–६२ में विभागीय भोजन व्यवस्था . .	७०३–०४
२६२	श्रीरंगपटनम के समीप कावेरी पर पुल . . .	७०४
२६३	नंजनगूड, दक्षिण रेलवे के समीप रेलवे सड़क का पुल .	७०४
२६४	मध्य प्रदेश में मध्यम सिंचाई योजनाएं . . .	७०४–०५
२६५	मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनाएं . . .	७०५
२६६	टेलीप्रिंटर	७०५–०६
२६७	बिहार में चीनी मिलें	७०६
२६८	गन्ने पर कर	७०६–०७
२६९	दिल्ली का चिड़िया घर	७०७
२७०	चीनी	७०७–०८
२७१	भारत में अन्धे व्यक्ति	७०८
२७२	टेलीग्राम टेलीफोन के तारों का चोरी के मामले . .	७०८
२७३	पाल वाले जहाजों द्वारा ले जाया गया सामान . .	७०९–१०
२७४	नौवहन कम्पनियों को ऋण	७१०
२७५	दिल्ली से कोटद्वार तक एक्सप्रेस गाड़ी . . .	७१०
२७६	कलकत्ता में भूमिगत रेलवे	७१०–११
२७७	बाढ़ के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय समिति . . .	७११
२७८	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	७११–१२
२७९	१९६१ में रेलवे दुर्घटनायें	७१२
२८०	रबी की फसल	७१२–१३
२८१	ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली लगाना . . .	७१३–१४
२८२	पंचायतों में हरिजन प्रतिनिधि . . .	७१४
२८३	नई दिल्ली में रेल के फाटकों पर ऊपरी पुल . .	७१५
२८४	मछुओं को सहायता	७१५
२८५	सर्प-दंश की चिकित्सा के लिये केरल को अनुदान . .	७१६
२८६	गोआ विलय की स्मृति में डाक-टिकट . .	७१६
२८७	अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य की संस्था, बंगलौर	७१६–१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२८८	मछली पकड़ने के बन्दरगाह	७१७
२८९	बंगलौर नगर के लिये जल-संभरण . . .	७१७–१८
२९०	कावेरी नदी का जल	७१८
२९१	चीते के बच्चे	७१८
२९२	छूत के रोगों का निवारण	७१९
२९३	बनसन्द्रा रेलवे स्टेशन	७१९
२९४	कम्बडोकोडा और हरंगी परियोजनायें . . .	७१९–२०
२९५	कश्मीरी सेव	७२०–२१
२९६	कलकत्ता से बम्बई के लिये बेल फल की बुकिंग . .	७२१
२९७	दिल्ली–फाजिल्का छोटी लाइन पर यात्री-डिब्बों में पंखों की व्यवस्था	७२१
२९८	दिल्ली–फाजिल्का छोटी लाइन पर गाड़ियों में सोने की बर्थें .	७२१
२९९	दिल्ली में आंत्रशोध के मामले	७२२
३००	सफदरजंग हवाई अड्डे से कुतुब मीनार तक का रास्ता .	७२२–२३
३०१	केंद्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् . . .	७२३
३०२	उद्यानों का विकास	७२३
३०३	टेलीफोन	७२३
३०४	दुर्घटना की रोक थाम के लिये मशीन का आविष्कार .	७२४
३०५	सब से अच्छे ग्राम सेवक का चुनाव . . .	७२४
३०६	मोतीहारी के जिला न्यायालय के निकट हाल्ट स्टेशन .	७२४
३०७	दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण	७२५
३०८	बीकानेर रेलवे स्टेशन में विश्राम और अल्पहार गृह .	७२५
३०९	दिल्ली में यातायात की दुर्घटनायें . . .	७२५–२६
३१०	दूसरी योजना में नई रेलवे लाइनें . . .	७२६
३११	खण्डवा–दोहद रेलवे लाइन का निर्माण . . .	७२६–२७
३१२	दिल्ली में गर्मी में बिजली संकट . . .	७२७
३१३	हिसार और सिरसा में रेलवे बुकिंग एजेंसियां . .	७२७–२८
३१४	हिसार रेलवे स्टेशन के पास पुल . . .	७२८
३१५	रोहतक–भिवानी रेलवे लाइन का निर्माण. . .	७२८
३१६	धनबाद नगर में यातायात की समस्यायें . . .	७२८–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३१७	डाक तथा तार विभाग की प्रतियोगिता परीक्षायें . .	७२९
३१८	पोचमवाद और श्रीसलम परियोजनायें . . .	७२९
३१९	मनीपुर द्वारा चावल का समाहार . . .	७३०
३२०	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे अधिकारियों को पेशगी वेतन-वृद्धि .	७३०
३२१	बगांईगांव (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के इंजीनियरिंग कारखाने में सामयिक श्रमिक	७३१
३२२	दार्जिलिंग में कर्मचारियों को शीतकालीन भत्ता . .	७३१
३२३	सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचे हुए रेलवे अधिकारी . .	७३१-३२
३२४	खंडवा और अजमेर के बीच सवारी गाड़ियों की रफ्तार .	७३२
३२५	गुजरात में नलकूप	७३२-३३
३२६	बीजापुर लोकल ट्रेन में जंजीर का खेंचा जाना . .	७३३-३४
३२८	केरल में मानसिक स्वास्थ्य	७३४
३२९	केरल में कोढ़	७३४-३५
३३०	त्रिवेन्द्रम सेंट्रल स्टेशन	७३५
३३१	केरल में समुद्र कटाव रोक कार्य . . .	७३५
३३२	उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधाएं .	७३५-३६
३३३	स्मृति टिकट	७३६
३३४	पंजाब को कोयले की ढुलाई	७३६
३३५	नंगल बांध को पोंग बांध से मिलाने वाली रेलवे लाइन	७३६-३७
३३६	बेलन गंज (आगरा) माल स्टेशन से माल का बुकिंग .	७३७
३३७	रेलवे बोर्ड के अधीन 'विजिलेंस इन्स्पेक्टरों' का स्थानान्तरण .	७३७
३३८	चिनाव नदी में बिजली की संभाव्यता का सर्वेक्षण . .	६३८
३३९	लखनऊ की आलम बाग वर्कशाप के भीतर पार्क .	७३८
३४०	ट्रंक टेलीफोनों में खराबी . . .	७३९
३४१	चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति समिति की सिफारिशें . .	७३९
३४२	केन्द्रीय काजू तथा मसाला समिति . .	७४०
३४३	नदी परियोजनाओं की सिंचाई और विद्युत् क्षमता . .	७४०-४१
३४४	उड़ीसा में विकास खंड . . .	७४१
३४५	खेतरी-चिरावा रेलवे लाइन	७४१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३४६ नजफगढ़ और नरेला के बीच सीधी टेलीफोन लाइन . ७४२
३४७ चेचक के टीके ७४२
३४८ खुर्जा के सहकारी घी विक्रेता ७४२
३४९ कम्बडोकोडा और हरंगी बांध परियोजनायें . . . ७४२—४३
३५० बिझिजाम फिशिंग हार्बर ७४३
३५१ ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल . . . ७४३
३५२ चक्रधरपुर (बिहार) में माल-डिब्बा कारखाना . ७४३—४४
३५३ सुकिन्दा परादीप एक्सप्रेस हाइवे . . ७४४
३५४ छपरा (मध्य प्रदेश) में आउट एजैन्सी . . . ७४४
३५५ दक्षिण पूर्व रेलवे पर सियोनी गंज साइडिंग को बन्द कर देना . ७४५
३५६ खाद्य पदार्थों का आयात . . ७४५—४६
३५७ बरना परियोजना ७४६
३५८ डाक तथा तार घरों के लिये भवन . . ७४६
३५९ दक्षिण रेलवे पर विभागीय भोजन व्यवस्था ७४६—४७
३६० दक्षिण रेलवे पर श्रम कल्याण निरीक्षक . . ७४७
३६१ आलू की पौध . . . ७४७
३६२ थाना 'क्रीक' पर पुल . . ७४७—४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ७४८—५१

(१) श्रीमती वी० बिमला देवी ने विद्युत् परियोजनाओं के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता के कारण आंध्र प्रदेश में की गई बिजली में २० प्रतिशत कटौती से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाया।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया और इस सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य सभा-पटल पर भी रखा।

(२) श्रीमती मैमूना सुल्तान ने पाकिस्तान हाई कमीशन द्वारा एक मान-चित्र, के कथित परिचालन की ओर, जिसमें भारत के कुछ राज्य-क्षेत्रों को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है, प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना : (क्रमशः)	
(३) श्री प्र० चं० बरुआ ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर बहुत संख्या में मुसलमानों के जमा हो जाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी मिशन के आरोप की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
समितियों के लिये निर्वाचन	७५१–५२
(१) खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के सदस्यों के रूपमें काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
(२) खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
विधेयक पुरः स्थापित .	७५२
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक ।	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	७५२–८९
२६-४-१९६२ को श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
मंगलवार, १ मई, १९६२ / ११ वैशाख १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा ।	

GMGIPND—LS III—417 (Ai) LSD –25–6–62—150